हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक सोमवार, दिनांक 11 फरवरी, 2019 को माननीय उपाध्यक्ष, श्री हंस राज की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 02.00 बजे अपराह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

11-02-2019/1400/NS/HK /1

प्रश्न संख्याः 849 (स्थगित)

श्री रमेश चन्द ध्वालाः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी के साथ-साथ मुख्य शहर भी है। अतः यातायात का सही तरीके से प्रबंध बहुत जरुरी है। आज यह शहर ओवरक्राउडिड बना हुआ है। यातायात को सुचारू रूप से चलाने हेतु बड़ी-बड़ी गाड़ियों या हैवी व्हीकल्ज़ को शोघी से मैहली होते हुए चलाया जाए और शहर में केवल छोटी गाड़ियां और लोकल बसें ही आनी चाहिए। इससे ट्रेफिक में भी निजात मिलेगी। क्योंकि साथ लगते प्रदेश पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व उत्तराखंड से काफी मात्रा में बसें व ट्रक शिमला आते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि सरकार इसके संबंध में क्या व्यवस्था कर रही है? दूसरा, यातायात में अनुभव किए गए व्यवधान जैसे कोई बस रुकती है और सवारियां उतारती है तो पीछे सारे-का-सारा जाम लग जाता है। ये व्यवधान यात्रियों को बसों से उतारने के समय होता है तो इसके लिए सड़क के किनारे पक्के भाग से दूर हट करके जहां-जहां व्यवस्था हो सकती है, बहुत स्थानों पर सवारियों को उतारने के लिए बस ले-बाई बनाए जाने हेतु प्रयास किए जाएं।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री रमेश चन्द ध्वालाः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए ही भूमिका बांध रहा हूं। यह प्रश्न ही है। जहां ओवरक्राउडिड होता है और बस खड़ी हो जाती है तथा फिर सवारियां उतारते हैं तो ट्रेफिक जाम लग जाता है। हर साल 10-15 प्रतिशत गाड़ियां बढ़ रही हैं। जिस जगह पर चौड़ाई अच्छी हो तो क्या वहां पर सरकार ओवर लोडिंग को दूर करने के लिए ऐसी व्यवस्था करने बारे विचार रखती है? जहां-जहां सरकारी और प्राईवेट जमीनें हैं, वहां पर ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि साईड पर बस या गाड़ी खड़ी करके सवारियों को उतारा जाए।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य आप अपना प्रश्न करें, आपको लिखित में विस्तार से उत्तर दिया गया है।

श्री रमेश चन्द ध्वालाः मैं इतना जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसा विचार रखती है?

मुख्यमंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि शिमला प्रदेश की राजधानी है और राजधानी के साथ-साथ इंटरनेशनल लैवल का एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। इसमें भी दो राय नहीं है कि पिछले कुछ अर्से से बहुत बड़ी तादाद में शिमला में ट्रेफिक बढ़ा है। छोटी-बड़ी गाड़ियों का नम्बर बढ़ा है। जिसके कारण बड़ी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। जहां तक माननीय सदस्य ने पूछा कि शिमला शहर के अंदर अगर कंजैशन है, ट्रेफिक बहुत ज्यादा है और गाड़ियां और बसें भी चलती हैं तथा ऐसी सूरत में जिन गाड़ियों में माल ढोया जाता है, उनको शोघी से मैहली की तरफ बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए।

11.02.2019/1405/RKS/HK-1

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि शिमला शहर में दिन के समय भारी माल वाहक वाहनों की आवाजाही निषेध है जिन्हें टुटीकण्डी-मैहली-ढली बाईपास से जाने की अनुमति प्रदान की गई है। रात के समय केवल उन्हीं भारी माल वाहक वाहनों को आने की अनुमति प्रदान की गई जिनके पास शहर के अंदर सामान लाने की बिल्टी या बिल आदि उपलब्ध हो। लेकिन इसके बावजूद भी शिमला शहर में ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ गया है। शिमला शहर में वर्ष 2005 में 31, 228 वाहन पंजीकृत थे और आज की तारीख में यह संख्या 77,939 हो गई हैं। यानी वाहनों की संख्या में बहुत बड़ा इज़ाफा हुआ है। वर्ष 2005 में शिमला में कुल 66,617 वाहन दिन में चलते थे जबकि आज इनकी संख्या 1,65,878 पहुंच गई है। निश्चित रूप से जब कोई टूरिस्ट शिमला आता है और वह ट्रैफिक में फंसता है तो उसे बहुत बड़ी असुविधा होती है। सरकार इस मसले को लेकर बहुत गंभीर है। पर्यटकों को टूरिज्म का आनंद लेने के लिए यह एक बहुत बड़ा व्यवधान है। ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए विभाग ने बहुत बड़े स्टैप भी उठाए हैं। आई.एस. बी.टी. को शहर से बाहर बनाया गया है जिससे ट्रैफिक में काफी फर्क पड़ा है। शिमला शहर में छोटी गाड़ियों की संख्या बढ़

गई है जिस कारण रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्ज में गाड़ियों की भीड़ देखने को मिलती है। ऐसी हालत में चाहे पार्किंग को बढ़ाने की बात हो या ट्रैफिक मैनेजमैंट को और बेहतर करने की बात हो, इन सारी चीजों को ठीक करने की कोशिश की जा रही है।

श्री रमेश चंद ध्वालाः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या शोघी-मैहली सड़क को चौड़ा करने के लिए बजट प्रावधान किया गया है? क्या यह सड़क बड़े वाहनों की आवाजाही के लिए ठीक है और क्या सरकार इस सड़क को चौड़ा करने का विचार रखती है?

दूसरा, मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि जहां-जहां काफी भीड़ है, क्या वहां पर फ्लाईओवर बनाए जाएंगे?

मुख्य मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिमला की ट्रैफिक को दुरुस्त करने के लिए स्वाभाविक रूप से हमें विचार करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। शिमला शहर की ट्रैफिक समस्या को रोकने के लिए जो लोंग टर्म प्लान है, उसमें रोप वे बनाने पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ-साथ शहर की ट्रैफिक को ठीक करने के लिए वैब कोर्स के साथ एक एम.ओ.यू. साइन किया जा रहा है। कहां सड़कों की वाइडनिंग पोसिबल है वह भी इसका एक पार्ट है और इसके ऊपर स्टडी की जा रही है। रोप वे का स्कोप कहां से निकल सकता है इस पर आज से पहले भी चर्चा होती रही, प्लान भी बनाए गए लेकिन वे अभी मैच्योर नहीं हो पाए। हम इन सारी चीजों को लेकर कुछ कह दें, यह भी ठीक नहीं होगा, लेकिन हम निश्चित रूप से इस पर काम करने की कोशिश करेंगे।

11.02.2019/1410/बी0एस0/वाई0के0-1

मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं कि जो टूटीकंडी में हमारी 700 वाहनों को खड़ा करने के लिए पार्किंग बनी है। वह शुरू भी कर दी गई है। हमने आदेश भी कर दिए हैं कि वहां पर गाड़ियों को पार्क करें। इसके बावजूद हमें शिमला शहर के बाहर कोई बड़ी पार्किंग प्लान

करनी पड़ेगी। उसके बाद शिमला शहर तक लोगों को पहुंचाने के लिए, लोगों के लिए शहर में पहुंचाने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। वहीं वर्तमान में एक रास्ता दिखता है जिससे इस समस्या का हल हो सकता है। अभी तक हम देख रहे थे कि टूटीकंडी पार्किंग बना करके हमने तैयार तो कर दी है। लेकिन उसके बावजूद भी जो भी टूरिस्ट आता है वह वहां पर नहीं रूकता वह सीधा शिमला शहर में ही पहुंचता है। मुझे लगता है कि जो भी पर्यटक आता है उसे वह सुविधा वहां नहीं मिल पाती है जो उसे मिलनी चाहिए। इसके साथ ही अब सब लोगों की स्वाभाविक रूप से एक आदत भी हो गई है कि जहां हमने पहुंचना है हमारी गाड़ी उसी आंगन में लगनी चाहिए। अभी तक हम शिमला में देख रहे हैं कि सचिवालय के पास जो हमारी पार्किंग है उसका भी लोगों द्वारा इस्तेमाल नहीं हो रहा है। यही हाल टूटीकंडी वाली पार्किंग हाल है । लोग गाड़ी खड़ी ही नहीं कर रहे हैं। सचिवालय वाली पार्किंग के बारे में तो जिस कॉन्ट्रेक्टर को यह पार्किंग आबंटित हुई है उनका कहना है कि जब आप आते हैं मेरी पार्किंग का थोड़ा-बहुत इस्तेमाल हो जाता है नहीं तो यहां कोई भी गाड़ी पार्क नहीं करता। सामने पार्किंग है परंतु लोग उसके बावजूद गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी कर रहे हैं। इस स्वभाव को ठीक करने की आवश्यकता है। हमारा पुलिस विभाग और जिला प्रशासन ने बहुत कोशिश इस बारे में की है। इस पर अभी और सख्ती भी की जाएगी। सड़क पर गाड़ी खड़ी करने वाले का चालान भी किया जाता है। उसके बाद वही बात आती है कि चालान हुआ तो उन लोगों के फोन भी हमें ही आते हैं कि हमारी गाड़ी का चालान हो गया है अब इसे ठीक करवाओ। ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने जिन चीजों को ले करके हमें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने प्रधान सचिव, परिवहन की अध्यक्षता में एक कमेटी का भी गठन किया है। वे भी इन सारी चीजों को देख रहे हैं कि शिमला की इस समस्या से कैसे निजात पा सकते हैं। पहले इससे आगे तक की बातें हुई हैं । टनल के बारे में भी बात हुई है। लेकिन वे बातें अभी तक बातें ही हैं। इससे आगे कुछ कहना भी सही नहीं होगा।

उपाध्यक्ष : अंतिम अनुपूरक पश्न श्री राकेश पठानिया जी ।

श्री राकेश पठानिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जैसी आपने स्काई ट्रास्पोर्टेशन का जिक्र किया। विदेशों में भी अक्सर यह देखा जा रहा है कि स्टील स्ट्रक्चर के ऊपर स्काई रोप वे ट्रास्पोर्टेशन आरम्भ हो चुकी है और यह लगभग हर देश में आरम्भ हो गई है। यह पहाड़ी स्थानों पर ही ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। उसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। क्या हमारी सरकार इस बारे में कोई विचार कर रही है?

मुख्य मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम सभी बातों को ले करके जो किया जा सकता है उन सभी बातों पर खुले मन से विचार कर रहे हैं। हमारी शिमला में भवनों का निमार्ण ही इस तरीके से हुआ है कि उनके बीच में से यह सारी चीजें निकालना बहुत कठिन कार्य है। जो स्काई वाला उदाहरण माननीय सदस्य ने दिया है उस बारे में भी हम विचार-विमर्श कर रहे हैं। इस संबंध में भी हमारा कुछ दिन पहले विचार हुआ है और इन सारी चीजों का उसमें जिक्र हुआ है। उसमें उनका कहना है कि उसके लिए उन्हे काल्म को नीचे से ऊपर तक उठाना है । बहुत जल्द हम शिमला शहर की ट्रैफिक भीड़ को ठीक करने के लिए वैबकोर्स के साथ हमारा एक एम.ओ.यू. साइन होने की दिशा में आगे बढ़ा है। वे इन सारी चीजों को ले करके विचार कर रहे हैं कि कहां सड़कों को चौड़ा किया जा सकता है । हमारी मुश्किल है कि कॉल्म खड़ा करने के लिए भी शिमला में जगह नहीं रही है । यदि इस दिशा में भी आगे बढ़ने की संभावना होगी तो हम अवश्य इस बारे में विचार करेंगे।

उपाध्यक्ष : : मुझे लगता है कि प्रश्न का उत्तर माननीय मुख्य मंत्री जी ने बड़े विस्तार से दिया है। ....(व्यवधान)....

11.02.2019/1415/DT/YK-1

माननीय सदस्य श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी अंतिम सप्लीमेंटरी करेंगे।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु (नदौन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न शिमला से संबंधित है और हम शिमला के निवासी हैं। मैं 10 साल तक नगर निगम में पार्षद रहा हूं। जो शिमला का डि-कंजैशन है, यह समय के साथ बढ़ता जाएगा। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने प्रिंसीपल सैक्टरी ट्रासर्पोट के नेतृत्व में एक शिमला मोबिलिटी प्लान बनाया है। स्वतंत्रता के पश्चात् सचिवालय के साथ से सारा ट्रैफिक जाता है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, यदि भविष्य में शिमला के ट्रैफिक को कम करना है तो शिमला में जो 3 टनल्ज बननी है, जिसकी डी0पी0आर्ज0 बन चुकी हैं, क्या सरकार उन टनल्ज के माध्यम से भी शिमला में ट्रैफिक डि-कंजैंशन करने का कार्य करेगी?

दूसरा, सचिवालय के साथ जो जगह है, वहां पर हमने पार्किंग बना रखी है। उसी पार्किंग और आपके ऑफिस के नीचे 20 बीघा जगह है। अगर आप छोटा शिमला से कसुम्पटी वाली लाइन को देखे तो उसमें तीन तो नगर निगम की बिल्डिंग आती है। ये श्री सुरेश भारद्वाज, माननीय शिक्षा मंत्री जी भी जानते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि छोटा शिमला में सचिवालय के नीचे जो Ellerslie Building है, वहां पर जो क्वाटर्ज हैं, उनको खाली करवाने के लिए कांग्रेस सरकार के समय में भी बात हुई थी, उसको खाली करवा करके पूरे सचिवालय के वाहन वहां पर खड़ा किया जा सकता है। क्योंकि हाइकोर्ट और सचिवालय के पास जहां सड़क तंग थी, वहां पर सड़क चौड़ी हो रही है। छोटा शिमला में अगर बिल्डिंग को एक्वॉयर करके सड़क को चौड़ा किया जाएगा तो काफी हद तक शिमला के ट्रैफिक को कम किया जा सकता है। क्योंकि हमारे आधे ऑफिसिज़ एस0डी0ए0 कॉम्पलैक्स में है और आधे चक्कर की तरफ है, जिसके कारण यह जाम लगता है। इन बातों को ध्यान में रखा कर इस ट्रैफिक को प्लॉन किया जाए।

मुख्य मंत्री: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सुझाव दिए हैं अगर वे वर्कएबल हैं तो निश्चित रूप से उन पर विचार किया जाएगा।

जहां तक आपने टनल्ज की बात की है, ये ठीक है कि तीन टनल की डी0पी0आर्ज0 का प्रोसैस हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी कई कारणों से यह मामला लम्बित है। ये

हमारे ध्यान में है और हमारी कोशिश भी है कि अगर ये तीन टनर्ल्ज के बजाय एक टनल भी बन जाती है तो उससे भी हमें थोड़ी-बहुत राहत जरूर मिलेगी। जैसे लक्कड़ बाजार के बस स्टैंड़ में बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है। हम विचार कर रहे हैं कि उसको भी वहां से बाहर के लिए शिफ्ट किया जाए। जो आप सचिवालय से नीचे एक 20 बीघा लैंड़ बता रहे हैं, ये बात हमारे ध्यान में लाई है, हम इसको एग्जामिन करेंगे। यदि यह व्यावहारिक होगा तो हम जरूर कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश है कि शिमला की ट्रैफिक की कंजैक्शन को कम करने के लिए जो भी करना पड़ेगा, जहां सड़कों की वाइडनिंग करने का स्कोप निकल आएगा, इसकी प्रोपर क्लीयरेंस लेने के बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि शिमला में बाहर से आने वाले टूरिस्ट को भी पार्किंग की सुविधा मिले और शिमला के अंदर जो लोग स्थायी रूप से रहने वाले हैं उनको भी पार्किंग की सुविधा मिले। इस बात को हम सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे।

11-02-2019/1420/ए.जी./एन.जी./1

प्रश्न संख्या 990

श्री राकेश जम्वाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जो जवाब आया है उसमें बीबीएमबी का मानना है कि हमारे पास कोई भी जमीन खाली नहीं है । बीबीएमबी के पास सुन्दरनगर में बीएसएल प्रोजैक्ट है उसमें बहुत सी जमीने ऐसी हैं जो वर्तमान में खाली पडी है । लेकिन बीबीएमबी ने यह सूचना किस प्रकार से दी है, मैं वहीं पर रहता हूं , जब वहां पर प्रोजैक्ट का कार्य शुरू हुआ था तो अनेकों कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए आवास बनाए गए थे । लेकिन वर्तमान में बीबीएमबी ने वह सभी क्वाटर खाली करवाकर कर्मचारियों के लिए मल्टी स्टोरी क्वाटर वहां पर बनवा दिए हैं। वहां पर सैकडों बीघा जमीन खाली पडी है और उस जमीन पर बीबीएमबी की वर्तमान में क्या योजना है क्योंकि प्रोजैक्ट बन कर तैयार हो गया है और चल रहा है । सुन्दरनगर शहर में वह जमीन एक ऐसी प्राईम लैंड है ..

उपाध्यक्ष : आप अपना प्रश्न पुछिए ।

श्री राकेश जम्वाल : बीबीएमबी की जमीन वहां पर खाली पडी है और बीबीएमबी का यहां पर जवाब आया है कि हमारे पास कोई खाली जमीन नहीं है । प्रैक्टिकल तौर पर वहां पर सैकडो बीघा जमीन बीएसएल प्रजोक्ट के अन्तर्गत खाली पडी है । सरकार उस जमीन को वापिस लेने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

बहु उद्देश्यीय परियोजनाएं एवं उर्जा मन्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है उसमें अनुमद क और ख में मैंने कहा है कि कितनी जमीन उन्होनें प्रदेश सरकार को दी थी और लीज पर कितनी दी थी । माननीय सदस्य सरप्लस लैंड की बात कर रहे हैं, उसमें जहां सुन्दरनगर चुनाव क्षेत्र प्रभावित है, वहीं मेरा चुनाव क्षेत्र भी प्रभावित है । इन्होने यह ठीक कहा है कि बहुत से क्वाटर जो वहां पर बने थे उनके स्थान पर मल्टीस्टोरी क्वाटर बना दिए हैं । वहां पर बहुत सी जमीन देखने को उपलब्ध लगती हैऔर जो जवाब बीबीएमबी से आया है मैने वहीं सूचना इस माननीय सदन में रखी है । नियम 130 के अन्तर्गत माननीय सदस्य ने भी अपना मुद्दा उठाया था और उसका रिप्लाई भी अभी हमारे पास रैवन्यू विभाग के माध्यम से सदन में आया है । रैवन्यू विभाग के माध्यम से सूचना दी गई है कि वहां पर काफी जमीन उपलब्ध है । मैं यह भी सदन के सामने रखना चाहूंगा कि जो लैंड इक्वायर हुई थी वह भूमि अधिकरण नियम-1894 के अनुरूप हुई थी । Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 उसमें तो प्रोविसन है । अब हमें यह लीगली एग्जामिन करना पडेगा क्योंकि यह कह रहे हैं कि हमारे पास जमीन उपलब्ध नहीं है और सरकार के तौर पर हमने यह पाया है कि इनके पास जमीन उपलब्ध है । हम इनसे सूचना लेंगे कि हमने जो जमीन आईडैनटीफाई की है इसे बीबीएमबी के माध्यम से किस प्रयोग में लाया जाएगा । इस जमीन को लीगली तौर पर कैसे दोबारा सरकार के पास लाया जाए उसके लिए हमें एग्जामिन करना पडेगा और उसके बाद जो रिपोर्ट आऐगी तभी मैं कुछ इस पर कह सकता हूं । मैं एक बात मानता हूं कि जो बीबीएमबी ने जवाब दिया है उसमें कन्ट्राडिक्शन है ।

श्री राकेश जम्वाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार सुन्दरनगर में लगभग 73 हजार वर्ग मीटर जमीन मौका पर खाली पडी है और उसके साथ-साथ 15 हजार 335 वर्ग मीटर पर जो क्वाटर बने है वह गैर रिहायशी हैं और बीबीएमबी का उन पर कब्जा है । जब बार-बार इस मामले को हम विधानसभा में उठाते हैं तो बीबीएमबी ने एक काम शुरू कर दिया है कि वहां पर जो खाली जमीन पडी है उस के चारों ओर बाउन्डरी लगा रहे हैं । मेरा माननीय मन्त्री जी से और माननीय मुख्यमन्त्री जी से आग्रह है कि जो जमीन बीएसएल प्रोजैक्ट में बीबीएमबी के पास सुन्दरनगर में खाली है उसको हिमाचल सरकार वापिस ले ।

11/02/2019/1425/RG/AG/1

हमारा सुन्दरनगर शहर धीरे-धीरे बहुत बड़ा शहर बनता जा रहा है, अगर यह जमीन हिमाचल प्रदेश सरकार के पास वापस आती है तो वहां बहुत सारे अनेकों अन्य प्रोजैक्ट्स और आ सकते हैं?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष जी, **जैसा मैंने पहले अपने उत्तर में कहा कि यह जमीन उपलब्ध है और इसके बारे में सूचना भी आई है। परन्तु अब हम इसको लीगली कैसे क्लेम करें, क्योंकि बी.बी.एम.बी. प्रोजैक्ट के माध्यम से जमीन का अधिग्रहण किया गया है, अब प्रदेश सरकार उसको लीगली कैसे ले सकती है, मैंने कहा कि सरकार इसको ऐग्जामिन करेगी।**

श्री विनोद कुमार(नाचन) : माननीय उपाध्यक्ष जी, इसके 'क' भाग में माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि ब्यास सतलुज लिंक परियोजना में बिजली उत्पादन शुरू हुआ था तब वहां 6593 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत थे और वर्तमान में वहां 8,448 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ये जो 8,448 अधिकारी/कर्मचारी वहां अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनमें से हिमाचल प्रदेश के कितने अधिकारी/कर्मचारी इस परियोजना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं? वैसे तो श्री राकेश जी ने इस विषय को लेकर अपनी बात यहां कही है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा इस परियोजना में बग्गी से लेकर सुन्दरनगर तक हमारे पास बहुत बड़ी मात्रा में सरप्लस लैण्ड वहां है और जैसा

यहां बी.बी.एम.बी. की ओर से उत्तर आया है कि इनके पास कोई भी जमीन नहीं है, मुझे लगता है कि यह बहुत निराशाजनक उत्तर बी.बी.एम.बी. की ओर से यहां दिया गया है। मैं चाहूंगा कि डी.सी. की अध्यक्षता में एक ऐसी समिति का वहां गठन किया जाए जो वहां की वस्तुस्थिति से सरकार को अवगत करवाए और आने वाले समय में सारी सरप्लस लैण्ड हिमाचल प्रदेश को वापस मिले, मैं यही कहना चाहूंगा।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष जी, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि जब पहले यह प्रोजैक्ट लगा था उस समय हमारे स्टाफ की संख्या 6593 थी और वर्तमान में यह संख्या 8,848 है। परन्तु मैं माननीय सदस्य को फिर वही बात कहना चाहता हूं कि इस पर हमारा लीगली कोई क्लेम नहीं है कि हम इसके लिए क्लेम करें और वर्ष 2011 में जो 7.19% रेशो की हमारी भागीदारी निश्चित हुई थी और हमारा 7.19% का क्लेम है। पहले इसके ऊपर हमारे किसीक्लेम की बात नहीं थी। लेकिन फिर भी जो स्टाफ की जहां तक बात है, उसमें हमारा पॉवर विंग और इर्रीगेशन विंग दोनों इसमें आते हैं। पॉवर विंग में हमारे कुल 337 पद स्वीकृत हैं और इसमें 70 क्लास-I एवं क्लास-II के पद हैं। इसका मतलब यदि हम स्ट्रैन्थ के हिसाब से 7.19% का हिसाब लगाएं तो यह संख्या 23 बनती है। लेकिन वहां उससे भी ज्यादा हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि रेशो के हिसाब से वहां हमारी स्ट्रैन्थ ज्यादा है।

मुख्य मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष जी, वैसे तो माननीय मंत्री जी ने बहुत ही विस्तार से उत्तर दिया है। यह सच है कि जब इस प्रोजैक्ट का काम चला था, उस समय वहां के अधिकारियों और वहां जो लेबर काम करती थी, उनके लिए कौलोनी बनी। लेकिन उसके बाद जब प्रोजैक्ट कमीशन स्टेज में आ गया तो धीरे-धीरे वहां कुछ लेबर रिटायर हो गई, कुछ शिफ्ट हो गई और कुछ की छंटनी हो गई। वहां जो बहुत बड़ी कौलोनी बनी है, उसमें भी हम देखते हैं कि बहुत सारे मकान खाली पड़े हैं। हम इस मामले को कई बार टेक अप चुके हैं कि वहां सरप्लस लैण्ड को हिमाचल प्रदेश को वापस किया जाए। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो हमारा Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 है जिसका जिक्र माननीय मंत्री जी ने भी किया है, उसमें यह प्रावधान है, when any land acquired under this Act remains unutilized for a period of five years from the date of taking over the possession, the same shall be returned to the original owner or their legal

heirs, as the case may be, or to the land bank of the appropriate Government by revision in the matter as may be prescribed by the appropriate Government.

11/02/2019/1430/MS/DC/1

प्रोविजन है। परन्तु उसके बावजूद भी कई बार हमें वह जमीन उपलब्ध नही हो पाती है। हम लिखते रहते हैं लेकिन जमीन नहीं मिलती है। हमने भी अपनी सरकार आने के बाद इस मामले को दो-तीन बार टेकअप किया है। वे हां, हां करते हैं लेकिन कुछ नहीं होता है। यह विषय डी0सी0 के अधिकारक्षेत्र का नहीं है। हमारा यह प्रोजैक्ट केन्द्र सरकार का है इसलिए केन्द्र सरकार से ही हमें इसे टेकअप करना पड़ेगा और यह जमीन वापिस तभी मिल पाएगी, जब वहां से सारी औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी। माननीय उपाध्यक्ष जी, हम फिर से इस मामले को उठाने की कोशिश करेंगे क्योंकि जो अनयुटिलाइज्ड जमीन पड़ी है, उसमें बहुत कुछ करने की संभावनाएं हैं। जैसे वहां पर विकास से संबंधित बहुत से काम हो सकते हैं। इसके अलावा वहां पर हमारी इण्डस्ट्रीज लग सकती हैं और अगर वह भी नहीं लगानी है तो वहां पर कॉलोनिज बना सकते हैं क्योंकि शहरों में वैसे ही काफी भीड़ हो गई है। वास्तव में इस जमीन की हमें आवश्यकता भी है इसलिए इस विषय को हम दुबारा टेकअप करेंगे ताकि हमें यह जमीन प्राप्त हो सके।

प्रश्न संख्याः 1272

अध्यक्षः प्रश्न संख्या 1272, श्री विक्रमादित्य सिंह, अनुपस्थित।

प्रश्न संख्ययाः 1273

श्री परमजीत सिंहः माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो बी0बी0एन0 पुलिस जिला है, यह 1 जनवरी, 2009 से चालू हुआ था और वहां पर प्रवासियों की इतनी भारी संख्या है कि सोलन जिला से अलग होकर यह जिला बना था। सोलन जिला में पुलिस बल की संख्या 617 है और बी0बी0एन0

में 315 है। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हमारे क्षेत्र में पुलिस बल को बढ़ाया जाएगा तो उससे एक तो खनन माफिया पर रोक लगेगी और जो वहां इतना ज्यादा अपराध बढ़ रहा है, वह भी बन्द हो जाएगा। इसके अलावा बद्दी क्षेत्र के अन्दर ट्रैफिक की भी बहुत ज्यादा समस्या रहती है जिससे उस क्षेत्र के लोग बहुत परेशान हैं। इसके साथ-साथ मेरा यह भी निवेदन रहेगा कि वहां पर डी0एस0पी0 (ट्रैफिक) पुलिस की एक पोस्ट क्रिएट की जाए और पुलिस बल को बढ़ाने बारे भी विचार किया जाए।

मुख्य मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने पहले ही उत्तर दे दिया है कि मामला सरकार के विचाराधीन है। हालांकि वर्ष 2008 में यह पुलिस डिस्ट्रिक्ट बद्दी बनाई गई थी और उसके बनाने की वजह यह थी कि वह पंजाब से लगा हुआ बॉर्डर एरिया है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह बना था कि जब इण्डस्ट्रियल पैकेज हिमाचल के लिए मिला था तो बद्दी में हमारा बहुत बड़ा इण्डस्ट्रियल सैक्टर विकसित हुआ था और वहां कानून-व्यवस्था तथा ट्रैफिक को कन्ट्रोल करने हेतु भी इसे बनाया गया था। उसके साथ-साथ नई चीजों को लेकर, जिसको आज की तारीख में हम बार-बार कह रहे हैं, वह ड्रग्ज का मुद्दा भी है। तो इन सारी चीजों को ठीक करने की दृष्टि से वहां हमारी पुलिस डिस्ट्रिक्ट बनी है और उसके माध्यम से उस दिशा में काम कर भी रहे हैं। आज तक वहां पर सब तरह के कर्मचारी जो पोस्ट्स किए गए हैं उनकी संख्या 322 हैं। अब हम अनुभव कर रहे हैं कि यह स्ट्रैंथ वहां के लिए नाकाफी है। वहां पर ट्रैफिक के साथ-साथ जो इण्डस्ट्रियल सैक्टर ग्रो हुआ है, उसके कारण और साथ में यह ड्रग्ज का मुद्दा भी हमारे लिए चिन्ता का विषय बना हुआ है।

11.02.2019/1435/जेके/डीसी/1

यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। बॉर्डर एरिया के साथ जो हमारा पंजाब, हरियाणा के साथ सटा हुआ एरिया है, वहां पर बहुत बड़ी तादाद में गलत तरीके से ड्रग्ज़ की मात्रा लाने व ले जाने से प्रदेश को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। वह बहुत बड़ी चिन्ता का विषय बना हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां हमारे पास कुल पांच थानें हैं जिनमें से एक

महिला थाना भी है। जहां तक इन्होंने कहा चाहे माइनिंग की बात है, चाहे दूसरे जितने भी ड्रग्ज़ के मामले हैं, चाहे कानून व्यवस्था से सम्बन्धित इशूज़ हैं, उन तमाम इशूज़ को ध्यान में रखते हुए उनके ऊपर विचार हो रहा है कि वहां पर जो 322 की स्ट्रैंथ है, उसको और ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, **मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो स्ट्रैंथ बढ़ाने का मामला है, वह विचाराधीन है। एक प्रपोज़ल इसमें हमारी पहले से ही प्रोसैस हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जहां पर इस प्रकार के हालात हैं, वहां पर निश्चित रूप से ज्यादा स्टाफ बढ़ाया जाएगा ताकि इन सभी चीजों को ठीक प्रकार से मॉनिटर किया जा सके।**

श्री लखविन्द्र सिंह राणाः (नालागढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि यह ठीक है कि बी0बी0एन0 में बाहर के बहुत लोग आ चुके हैं और उनकी पहचान करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है कि जो फेक्टरियों में लोग काम करते हैं उनके पीछे का क्या बैकग्राउंड है, वे क्रिमिनल हैं या नहीं? बद्दी से लेकर नालागढ़ के बीच में बहुत ज्यादा एरिया ऐसा पड़ता है जहां पर पुलिस स्टेशन होना अति आवश्यक है। इसी तरह से हमारे नालागढ़ से लेकर स्वारघाट के बीच में एक पुलिस पोस्ट जोगो है ।उसको अपग्रेड किया जाना चाहिए ताकि वहां पर जो घटनाएं बढ़ी हैं, उनको रोका जा सके। जैसे कि यहां पर ट्रैफिक की बात की गई, श्री परमजीत सिंह जी ने कहा कि वहां पर

शाम को लोग अपनी गाड़ियों में नहीं जा सकते क्योंकि तीन-तीन घंटे तक जाम लगा रहता है, इसलिए वहां पर एक डी0एस0पी0 (ट्रैफिक) की पोस्ट होना अति आवश्यक है। मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इन बातों के ऊपर सरकार गम्भीर है, क्या इन पदों को शीघ्र भरेगी?

मुख्य मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो यहां पर नालागढ़ और बद्दी के इलाके के बारे में बात कही है, उन सारी बातों को लेकर मैंने बहुत विस्तार से ज़वाब दे दिया है। आप जोगो का जिक्र कर रहे थे, वहां पर पुलिस पोस्ट है। मैंने यहां पर एक बात कही है, जिसको मैं दोबारा से कहना चाहता हूं कि यह इलाका ऐसा है जिसमें पुलिस फोर्स

को और ज्यादा स्ट्रैंथन करने की आवश्यकता है। जैसे कि मैंने यहां पर कहा कि माइनिंग एक इशू है, उसके बाद इण्डस्ट्रियल सैक्टर दूसरा इशू है इसलिए वहां पर कानून-व्यवस्था को सुनिश्चित करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता रहती है। वहां बहुत बड़ी संख्या में लेबर क्लास रहती है। वे लोग फेक्टरीज़ में काम करने के लिए आते हैं। वहां से लेबर के इशूज आते हैं उनको भी टैकल करने की भी बहुत आवश्यकता रहती है। इसके साथ-साथ जो तीसरा इशू है, जिसका मैंने यहां पर जिक्र किया, ड्रग्ज़ का नया इशू पिछले कुछ अर्से से एक्टिव हुआ है। जिसके कारण हमें महसूस होता है कि इस इलाके को पुलिस फोर्स के द्वारा और ज्यादा स्ट्रैंथन करने की आवश्यकता है क्योंकि यह पंजाब व हरियाणा के साथ सटा हुआ इलाका है और ऐसी परिस्थिति में कोई भी आदमी हिमाचल प्रदेश में अगर आने का रास्ता ढूंढता है तो यह सरल रास्ता उनके लिए है। यहां पर पंजाब से कोई गलत काम करके आ जाता है। गलत वारदात को अंजाम दे करके वह कोशिश करता है कि हिमाचल में आए। ऐसी चीजों को रोकने की बहुत आवश्यकता है। **मैंने कहा है कि पांच पुलिस थाने वहां पर ऑलरेडी एग्जिस्टैंस में हैं लेकिन उसके बावजूद भी उसको फ्रदर स्ट्रैंथन करने के लिए हमारा विचार है, उसको हम सुनिश्चित करेंगे।**

11-02-2019/1440/SS-HK/1

प्रश्न संख्याः 1274

श्री नन्द लालः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो जवाब यहां पर जनमंच के बारे में रखा है इसके उत्तर में बताया गया है कि 1,61,37,553/- रुपये का खर्चा हुआ है। जिसमें अभी 12-13 बिल्ज़ और आने हैं। Since it is a programme तो आगे इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक-एक जनमंच कार्यक्रम होना है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इसमें खाना, ट्रांसपोर्ट और जो ऑफिसर व कर्मचारी लोग जाते हैं उनका टी0ए0/डी0ए0 भी शामिल होता है?

Secondly, since it is a programme, कल को कोई माननीय विधायक अपने यहां शिकायत निवारण का कार्यक्रम चलाए या रखे तो क्या इस पर भी सरकार विचार रखती है और उसमें भी ये सारी सुविधाएं दी जायेंगी?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष जी, यह बिल्कुल ठीक कहा कि यह जो फिगर 1,61,37,553/- रुपये की दी गई है यह सिर्फ 95 जनमंच कार्यक्रम जो हुए हैं उसी की फिगर दी गई है। जबकि इसमें अभी 11 बिल और आने बाकी हैं। लेकिन इसमें सरकार की ओर से प्रावधान किया गया है कि हम एक जनमंच में दो लाख रुपये तक खर्च कर सकते हैं। फिर भी उसमें एक लाख रुपया सामुदायिक भोजन के लिए है और बाकी टैंट्स व दूसरी सुविधाएं जन-मानस के लिए सरकार उपलब्ध करवा रही है। कई बार भारी बारिश के कारण वाटर प्रूफ टैंट लगाना पड़ता है उसकी वजह से खर्चा ज्यादा भी हो जाता है। लेकिन जिस तरह से यह जनमंच कार्यक्रम लोकप्रिय हो रहा है इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं कि एक नयी सोच के साथ इन्होंने इसको आगे बढ़ाया है। उससे धीरे-धीरे अगर इसमें खर्चा बढ़ेगा भी, तो उसे बढ़ायेंगे। मैं तो समझता हूं कि हर महीने जनमंच होता है और जिस विधान सभा क्षेत्र में इसका आयोजन होता है वहां के माननीय विधायक अक्सर वहां पर होते हैं। अगर फिर भी कोई माननीय विधायक अलग से शिकायत निवारण कार्यक्रम करना चाहता है वैसे अभी इसके बारे में हमारा कोई विचार नहीं है लेकिन फिर भी अगर माननीय मुख्य मंत्री जी का आदेश होगा तो वह मान्य होगा।

श्री जगत सिंह नेगी (किन्नौर)ः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि ये जो जनमंच आयोजन किये जा रहे हैं इसमें कई जगह पर चार-चार लाख रुपये खर्च किये जा रहे हैं और कई जगह पर दो लाख रुपये हैं और कई जगह पर दो लाख रुपये से कम खर्चा है। यह किस तरह से बजट की बंदरबांट है कि जहां जिसका दिल करे उतने लाख रुपये खर्च कर दे?

दूसरी बात यह है कि जितना खर्चा हो रहा है क्या आप इसका ऑडिट करवायेंगे क्योंकि यह पैसा पब्लिक का है? आप इसका ऑडिट अवश्य करवायें।

तीसरी बात जनमंच के बारे में यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जनमंच के कार्यक्रम में वे स्वयं आयेंगे। आपका

स्वागत है, आप आएं। लेकिन इनका एक छोटे से एरिया पर चार लाख रुपये का खर्चा है तो मेरे ख्याल में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो एक करोड़ रुपये से ऊपर खर्च होगा? क्या इस किस्म का खर्चा करने का कोई औचित्य है?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष जी, यह तो लोगों की संख्या पर निर्भर करता है अगर माननीय मुख्य मंत्री जी या माननीय मंत्रियों के कार्यक्रम होते हैं। जिस तरह से लोग न्याय के लिए वहां पर आ रहे हैं और उनको उसका लाभ भी मिल रहा है, उससे लोगों की संख्या बढ़ रही है।

दूसरा प्रश्न इन्होंने पूछा कि अलग-अलग खर्चा है, कहीं डेढ़ लाख रुपया है और कहीं दो लाख रुपया है। तो उसके बारे में मैंने पहले ही कह दिया कि अगर कार्यक्रम आपके पी0ओ0 में होगा और दूसरी बार कल्पा से ऊपर रोगी में होगा तथा

तीसरा पूह में होगा तो निश्चित रूप से टैंट और जितनी भी कुर्सियां वैगरह ले जानी पड़ेगी, ट्रांस्पोर्ट का थोड़ा खर्चा बढ़ेगा और जो हम धाम का आयोजन करते हैं, वह समाज के लिए ही करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं करते। वह जनहित के लिए करते हैं। उसमें अगर खर्चा बढ़ता है तो सरकार खर्च करेगी।

मुख्य मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा हूं कि इस कार्यक्रम से हमारे मित्रों को बहुत ही परेशानी है। कई बार क्या होता है कि एक ही तीर निशाने पर लगता है और वही काम पूरा कर देता है। मुझे लगता है कि जनमंच भी ऐसा ही कार्यक्रम है। आप इसमें अनावश्यक रूप से क्या खोदने की कोशिश कर रहे हैं? प्रदेश सरकार अगर चुनी हुई सरकार है तो हमारा दायित्व क्या है, हमारा काम क्या है? हमारा दायित्व लोगों की समस्याओं का समाधान करना है, लोगों को उनके काम-काज में मदद करना है। अगर यह मदद उनके घर या गांव में उपलब्ध हो जाए तो यह उनके लिए और भी ज्यादा अच्छा

रहता है। ऐसी परिस्थिति में हमने यह निर्णय लिया है। जहां तक आप खर्चे की बात कर रहे हैं, जनमंच का जो आयोजन होता है, जो मिनिमम रिक्वायरमैंट होती है, साउंड सिस्टम लगना है, लोगों के बैठने की व्यवस्था करनी है, लोगों ने अपनी समस्या के समाधान के लिए वहां पर पहुंचना है, तो बैठने की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। बारिश है, धूप है, उनको बैठने के लिए शामियाना लगाने की जरूरत पड़ेगी। अधिकारी वहां पर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आएंगे तो वहां पर उनके बैठने का अरेंजमैंट भी करना पड़ेगा और जनमंच सुबह 9-10 बजे से शुरू होता है और कुछ जगह तो यह शाम के 6-7 बजे तक चलता है तो क्या ऐसी परिस्थिति में, वहां पर जो लोग आए हैं, जिनकी समस्याओं का समाधान करना है, सारा दिन उनको क्या हम पानी के लिए भी नहीं पूछेंगे? जो अधिकारी सुबह घर से निकलकर वहां लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद उनका समाधान करने के लिए बैठेगा, सारा दिन क्या उसको भोजन का भी इन्तज़ाम न करें ? मुझे लगता है कि यह बहुत अमानवीय सोच है। इन सारी बातों पर विचार करने के बाद हमने तय किया कि सादा भोजन, जो लोग समस्याओं के समाधान के लिए वहां पर आते हैं, जिन्होंने शिकायत की है, उनको भोजन की व्यवस्था की जाएगी और वही भोजन मंत्री भी करेगा और अधिकारी भी करेंगे। उसमें ऐसा नहीं है कि अधिकारियों के लिए अलग से मैन्यू बनेगा और मंत्रियों के लिए अलग से भोजन बनाकर परोसा जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं खुद अपने विधान सभा क्षेत्र में जनमंच में गया था। जिस पंक्ति में हमारे शिकायत करने वाले लोग थे, जिनकी समस्याओं का समाधान होना था, जिस पंक्ति में उन्होंने भोजन किया उसी में बैठ कर हमने भी वहां उनके साथ भोजन किया। जो भोजन उनको परोसा गया, वही हमने भी ग्रहण किया। तो मन्शा के पीछे इसका भाव जानने की कोशिश कीजिए। यह खोदने में आप मत लगें। हर जगह, हर बात को खोदने की आप कोशिश करते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जहां तक आप कह रहे हैं, पब्लिक मनी है और इसका एक नियम है। नियमानुसार इसका ऑडिट होता है। कौन मना कर रहा है? हम आज भी ऑडिट करने के लिए तैयार है और इस बात को हमने

सुनिश्चित किया है कि कहीं भी जनमंच में, पब्लिक मनी का मिसयूज़ नहीं होने देंगे। इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक बात और पूछी, अब इनको और ज्यादा चिन्ता हो गई कि मुख्य मंत्री ने कह दिया कि यह जनमंच का कार्यक्रम अब जिले में भी होगा तो इनकी परेशानी और बढ़ गई। ...(व्यवधान)...आप क्यों परेशान होते हो?

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः आप जहां मर्जी करो लेकिन यह आपके गले में फंसेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, "प्रशासन आपके द्वार" कार्यक्रम पहले भी होता रहा है। यह कोई नई योजना नहीं है।

मुख्य मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष जी, यह बिल्कुल नई योजना है और उसमें और इसमें रात-दिन का अंतर है। ...(व्यवधान)...

उपाध्यक्षः अग्निहोत्री जी, बीच में न बोलें। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हम आपको समय देंगे। ...(व्यवधान)...माननीय मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं, आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आपको समय देंगे। आप बैठिए।

11.2.2019/1450/av/yk/1

---(व्यवधान)---

मुख्य मंत्री : ---(व्यवधान)--- गले में तो आपके फंसा हुआ है। आपके तो गले में अटका हुआ है और ऐसे अटका हुआ है कि यह न नीचे निगला जा रहा है और न बाहर निकाला जा रहा है।

श्री मुकेश अग्निहोत्री (हरोली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनमंच कार्यक्रम एक नई योजना नहीं है। इससे पहले ---(व्यवधान)---

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आपके लिए समय देंगे। ---(व्यवधान)--- माननीय मुख्य मंत्री जी बोल रहे हैं। ---(व्यवधान)--- बैठ जाइए। अगर आपने कुछ पूछना है तो आपको भी समय देंगे।---(व्यवधान)---

श्री मुकेश अग्निहोत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी इलेबोरेट करके बता रहे हैं। ---(व्यवधान)--- आप कह रहे हैं कि पहली बार हो रहा है।

मुख्य मंत्री : हां, मैं कह सकता हूं कि जनमंच पहली बार हो रहा है। यह आज तक के इतिहास में पहली बार हो रहा है। पहले जो प्रशासन जनता के द्वार कार्यक्रम चलाया गया था उसमें शिकायत निवारण केवल एक औपचारिकता होती थी। उसका कोई अर्थ नहीं होता था। यह जनमंच आपके लिए मुसीबत बनी हुई है, आप इसलिए परेशान है। जनमंच इस प्रदेश सरकार का और आज तक के इतिहास का पहला कार्यक्रम है। ---(व्यवधान)--- इस और उस कार्यक्रम में रात-दिन का अंतर है। ---(व्यवधान)---सरकार पर बोझ नहीं पड़ा। ---(व्यवधान)---

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य मुकेश अग्निहोत्री जी, आपको समय देंगे। आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आपको समय देंगे। ---(व्यवधान)--- आप बैठिए, प्लीज। आपको पूरा समय देंगे। ---(व्यवधान)--- माननीय सदस्य राकेश पठानिया जी, आप भी बैठ जाइए, मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं।

मुख्य मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जनमंच कार्यक्रम आज से पहले कभी नहीं हुआ और यह हमारी सरकार द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम है। जनमंच कार्यक्रम और प्रशासन जनता के द्वार कार्यक्रम में रात-दिन का अंतर है। ---(व्यवधान)--- पहले इस प्रकार का कोई मैकेनिज्म नहीं था। ---(व्यवधान)--- मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं क्योंकि मैंने सरकार के रहते हुए भी और विपक्ष में भी प्रशासन जनता के द्वार कार्यक्रमों में हिस्सा लिया हुआ है। ---(व्यवधान)--- आप गलत

जानकारी दे रहे हैं। उस कार्यक्रम में भी खर्च होता था। वहां पर जो अधिकारी लोग जाते थे उनका भी भोजन होता था। वहां पर लोगों को बैठने के लिए शामियाना व कुर्सियां लगती थीं। ---(व्यवधान)--- लेकिन वहां पर ---(व्यवधान)--- अरे! बैठिए आप। यह क्या तरीका बनाया हुआ है? आप लोगों ने यह क्या मजाक बनाया हुआ है? यहां पर जब मुझे बोलने की अनुमति दी गई है तो आप लोग बीच में ---(व्यवधान)--- बीच में यूं ही बोलते रहना कोई ठीक बात नहीं होती। मैं यहां पर जब चेयर की अनुमति से बोल रहा हूं ---(व्यवधान)--- हमें उससे भी ज्यादा ऐतराज है।

उपाध्यक्ष : सभी माननीय सदस्य बैठ जाइए। प्लीज, प्लीज, आपको समय देंगे। माननीय सदस्य नन्द लाल जी, आप क्या बोलना चाह रहे हैं?

श्री नन्द लाल (रामपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बात यह थी कि सरकार का जो कहीं भी खर्चा हो रहा है क्या हमें उस बारे में यह जानने का हक भी नहीं है कि इसका ऑडिट होता है या नहीं होता है?

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मुख्य मंत्री जी इस बारे में पूरा जवाब दे रहे थे।

मुख्य मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत शांति से जवाब दे रहा था। ---

(व्यवधान)---

उपाध्यक्ष : मेरा सत्ता पक्ष से अनुरोध है कि माननीय मुख्य मंत्री जी जवाब दे रहे हैं और आप लोग बीच में न बोलें।

मुख्य मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत शांति से जवाब दे रहा हूं। आपने मुझे बोलने के लिए अनुमति दी है और विपक्ष से माननीय सदस्य हाथ से इशारा करके मुझे बैठने के लिए कह रहे हैं। ---(व्यवधान)--- माननीय सदस्य श्री नन्द लाल जी ने मुझे हाथ हिलाकर इशारा किया। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि आप प्रश्न पूछिए और हम प्रश्न का जवाब देने को तैयार हैं। ---(व्यवधान)--- टैम्पर मेरा लूज नहीं होता। आपने (श्री

मुकेश अग्निहोत्री जी को कहा।) पीछे नहीं देखा जब श्री नन्द लाल जी मुझे हाथ से बैठने का इशारा कर रहे थे। हमारा टैम्पर कभी लूज नहीं होता और इनका टैम्पर हमेशा ही लूज रहता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि एक व्यवस्था की गई है और उस व्यवस्था के माध्यम से प्रदेश की जनता की समस्याओं का समाधान करना हमारी प्राथमिकता है। प्रदेश की जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए इसमें कोई गुरेज नहीं करेंगे। लेकिन जहां तक पब्लिक मनी की बात आती है तो हमने यह सुनिश्चित किया है कि अगर कहीं भी जनमंच में पैसे का दुरुपयोग होते देखा गया तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी।

11/02/2019/1455 /टी0सी0वी0/वाई0के0/1

<u>प्रश्न संख्याः 1275</u>

श्री आशीष बुटेलः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से तीन बातें जानना चाहूंगा। सर्वप्रथम यह कि यदि किसी मकान, बिल्डिंग या गऊशाला को बरसात के कारण नुकसान हुआ है तो पटवारी उसकी रिपोर्ट कानूनगो को करता है और कानूनगो यह रिपोर्ट तहसीलदार को प्रेषित करता है, फिर एस0डी0एम0 (सिविल) से उस व्यक्ति को वह कंपेनसेशन प्राप्त होता है। लेकिन पालमपुर सब डिविज़न में कुछ केसिज़ ऐसे हैं जो कि वापिस भेजे गए। मैं सबसे पहले तो उसका कारण जानना चाहूंगा कि वे केसिज़ किन कारणों से वापिस भेजे गए ?

दूसरा, जब उन्होंने ये केस वापिस भेजे तो तहसीलदार उनको वैरिफाई करने के लिए फिजिक्ली उस जगह पर दोबारा गए। लेकिन तब तक इतना समय बीत चुका था कि जिस व्यक्ति के घर को नुकसान हुआ था, उस डैमेज्ड घर को उसने रहने लायक बना दिया था। जिसके कारण उसकी कंपेनसेशन का अमाउंट भी कम हो गया। क्या इसकी वैरिफिकेशन के लिए कोई एक समयसीमा सुनिश्चित की जाएगी?

तीसरा, मैं आपके ध्यान में एक बहुत गंभीर बात लाना चाहता हूं। अगस्त के महीने में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बरसात की वज़ह से कई घरों को बहुत नुकसान हुआ, जिनकी रिपोर्टिंग अगस्त के महीने में ही हो गई थी। लेकिन लगभग 6 महीने का समय बीत जाने के बाद भी अभी तक उनको कंपेनसेशन नहीं मिल पाया है। Sir, will this process of settlement of the claim right from the date it is reported; till the time it is settled, be time bound ?

मुख्य मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैंने इस बारे में, इनके विधान सभा क्षेत्र के संबंध में काफी डिटेल में रिप्लाई दे दिया है। फिर भी मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि During the last year upto 15th January, 2019, 143 number of cases of damaged houses/cowsheds/buildings were reported in Palampur Constituency. उसका ब्रेकअप इस प्रकार से है as under (i) houses 84 cases, (ii) cowsheds 59 cases and (iii) building zero cases. Rs. 21,57,200 (Rs. Twenty one lakh fifty seven thousand and two hundred) has been paid/released as relief compensation to all the 143 sufferers. जहां तक आपने बताया कि कई केसिज में ऐसा भी हुआ कि मकान टूट गया और उस मकान में लोग रहते थे। उन्होंने कंपेनसेशन के लिए आवेदन किया लेकिन प्रशासन समय पर नहीं पहुंचा। जिसके कारण उसकी मौके पर जो सही ऐस्टिमेशन होनी थी, वह नहीं हो पाई। क्योंकि मकान मालिक कब तक उस स्थिति में रहता और उसने अपने मकान को रिपेयर करके रहने लायक बना दिया। उसके बाद जब वहां पर सरकारी विभाग के अधिकारी आते हैं तो उन्होंने देखा कि मकान ठीक स्थिति में है। लेकिन उस मकान को ठीक तो उस मकान मालिक ने स्वयं बनाया है। इस संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि उसमें यह भी प्रावधान है कि जब कोई मकान डैमेज होता है तो उसकी तुरन्त फोटो ले लेनी चाहिए। इस प्रकार का मैकेनिज्म हमें भी डेवैल्प करना चाहिए। लेकिन गरीब लोगों के पास इन चीजों की जानकारी का अभाव रहता है। इससे यह फायदा होता है कि जब सरकारी विभाग वाले आए तो आप बता सकते हैं कि जब नुकसान हुआ था तो उस व़क्त मकान की यह स्थिति थी। इस प्रकार से यह कंपेरिजन के लिए अहम भूमिका के रूप में काम आएगा। इसी तरह से एफ0आई0आर इत्यादि औपचारिकताएं भी तुरन्त करनी

चाहिए। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति पूरी जिंदगी मेहनत करने के पश्चात् अपना मकान बनाता है और जब वह मकान टूट जाता है या डैमेज हो जाता है तो स्वभाविक रूप से उस परिवार पर वह एक बहुत बड़ा संकट होता है। ऐसी परिस्थिति में हम सुनिश्चित करेंगे कि जो कंपेनसेशन का प्रोसैस है और

11-02-2019/1500/NS/AG /1

उस मकान का जो डैमेज़ हुआ है, वहां पर उसका आक्कलन करने के लिए तुरंत टीम पहुंचे और विज़िट करे। मैं इस बात को मानता हूं कि इसमें थोड़ा समय ज्यादा लगता है। कई बार परिस्थिति ऐसी होती है कि एक ही रात में बारिश ज्यादा हो जाती है और डैमेज़ रिपोर्ट कई स्थानों से आ जाती है। जब एक या दो स्थानों पर जाने की बात होती है उसको तो जल्दी किया जा सकता है। लेकिन जब 20 स्थानों पर मकान टूटने की खबर आती है तो उसमें थोड़ी-बहुत दिक्कत आती है। जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा कि **इस मैकेनिज़म को ठीक करने की आवश्यकता है तो हम इसको सुनिश्चित करेंगे।**

जहां तक आपने बताया कि बहुत सारे केसिज़ वापिस हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें वेरिफिकेशन का प्रोसैस होता है और उस प्रोसैस को पूरा करना पड़ता है। लेकिन मैं इस बात को जरुर कहना चाहूंगा कि वेरीफिकेशन के प्रोसैस में अगर सिंपल एप्लीकेशन किसी ने लिख दी है और उसके आधार पर उसको कंपेनसेशन मिलेगा तो ऐसा संभव नहीं हो पाता है। **ऐसी परिस्थिति में वेरिफिकेशन की जरुरत रहती है और उसमें देरी न हो, हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे।**

यहां पर आपने कहा कि **आपके विधान सभा क्षेत्र में वेरिफिकेशन में देरी हुई, केस भेजा, फिर फॉर्मेलिटीज़ के चक्कर में केस वापिस आया तो इन सारी बातों को हम आने वाले समय में ठीक करने की कोशिश करेंगे।** क्योंकि नुकसान तो नुकसान है। अगर किसी का घर डैमेज़ हो जाता है तो उसको राहत समय पर मिलनी चाहिए, जल्दी मिलनी चाहिए और उचित मिलनी चाहिए।

प्रश्न काल समाप्त

साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य

उपाध्यक्षः अब माननीय मुख्यमंत्री माननीय सदन को इस सप्ताह की कार्यसूची से अवगत करवाएंगे।

मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय सदन को इस सप्ताह की कार्यसूची से अवगत करवाता हूं जो इस प्रकार हैः-

सोमवार, 11 फरवरी, 2019 (1) शासकीय/विधायी कार्य।

(2) बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2019-2020- सामान्य चर्चा।

मंगलवार, 12 फरवरी, 2019 (1) शासकीय/विधायी कार्य।

(2) बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2019-2020- सामान्य चर्चा।

बुधवार, 13 फरवरी, 2019 (1) शासकीय/विधायी कार्य।

(2) बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2019-2020-सामान्य चर्चा एवं समापन।

वीरवार, 14 फरवरी, 2019 (1) शासकीय/विधायी कार्य।

(2) गैर-सरकारी सदस्य दिवस

शुक्रवार, 15 फरवरी, 2019 (1) शासकीय/विधायी कार्य।

(2) बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2019-2020- मांगों पर चर्चा एव मतदान।

शनिवार, 16 फरवरी, 2019 (1) शासकीय/विधायी कार्य।

(2) बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2019-2020- मांगों पर चर्चा एव मतदान।

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

उपाध्यक्षः अब श्री रमेश चन्द ध्वाला, सभापति, प्राक्कलन समिति, (वर्ष 2018-19), समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

श्री रमेश चन्द ध्वालाः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्राक्कलन समिति, (वर्ष 2018-19), के षष्टम् कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 31वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2017-18) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा शहरी विभाग से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

उपाध्यक्षः अब श्री राकेश पठानिया, सभापति, लोक उपक्रम समिति,(वर्ष 2018-19), समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

श्री राकेश पठानियाः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक उपक्रम समिति,(वर्ष 2018-19),50वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 71वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

उपाध्यक्षः अब श्री सुख राम, सभापति, कल्याण समिति,(वर्ष 2018-19), समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

श्री सुख रामः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से समिति का 13वां कार्रवाई प्रतिवेदन जोकि समिति के अष्टम् मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2017-18) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई तथा मांग संख्याः32 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति उपयोजना की वित्तीय वर्ष 2018-19 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

उपाध्यक्षः अब कर्नल इन्द्र सिंह, सभापति, जन-प्रशासन समिति,(वर्ष 2018-19), समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

कर्नल इन्द्र सिंहः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से समिति के षष्टम् प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि राजस्व विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है, की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

उपाध्यक्षः अब श्री बलबीर सिंह, सभापति, मानव विकास समिति,(वर्ष 2018-19), समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

श्री बलबीर सिंहः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से समिति के 11वें कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 22वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा योजना विभाग से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

उपाध्यक्षः अब श्री सुरेश कुमार कश्यप, सभापति, सामान्य विकास समिति,(वर्ष 2018-19), समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन

के पटल पर भी रखेंगे।

श्री सुरेश कुमार कश्यपः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से समिति के नवम् मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

उपाध्यक्षः अब श्री बिक्रम सिंह जरयाल, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति,(वर्ष 2018-19), समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

श्री बिक्रम सिंह जरयालः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से समिति के 11वें कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के तृतीय मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2018-19) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा उद्योग विभाग से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

11.02.2019/1505/RKS/AG-1

<u>वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बजट अनुमान</u>
<u>सामान्य चर्चा</u>

उपाध्यक्षः आज से वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट अनुमानों वार्षिक वित्तीय विवरण पर सामान्य चर्चा प्रारम्भ हो रही है तथा 13 फरवरी, 2019 को माननीय मुख्य मंत्री महोदय के उत्तर के साथ इसका समापन होगा। समय की उपलब्धता को देखते हुए विपक्ष के नेता को 45 मिनट और अन्य माननीय सदस्यों को अधिकतम 12 या 15 मिनट का समय सुनिश्चित किया गया है। मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे अपना-अपना भाषण बजट तक ही सीमित रखकर निर्धारित समयावधि के भीतर समाप्त करें। मैं सर्वप्रथम विपक्ष के नेता, श्री मुकेश अग्निहोत्री को चर्चा आरम्भ करने के लिए आमंत्रित करता हूं।

श्री मुकेश अग्निहोत्री (हरोली)ः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने 9 फरवरी, 2019 को इस सदन में जो बजट अनुमान प्रस्तुत किए उस पर बोलने का आपने मुझे मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछले बजट में कहा थाः-

सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं,
मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए।

सूरत बदलने के लिए आप क्या कर रहे हैं, इसका खुलासा मैं सदन में करने जा रहा हूं। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में यह पहला दस्तावेज़ है, जिस दस्तावेज में यही मैंशन नहीं है कि बजट का आकार क्या होगा? क्या कोई सरकार ऐसा दस्तावेज़ बनाती है जिसमें यह नहीं लिखा हो कि कुल बजट कितना होगा? मेरे पास पिछले बजट की कॉपी है और इसके पैरा संख्याः 156 में लिखा है कि -'41 या 42 हजार करोड़ रुपये का बजट अनुमानित है'। आप प्रैस कॉन्फ्रैंस में बता रहे हैं कि बजट का आकार 44, 387 करोड़ रुपये होगा लेकिन आप सदन में नहीं बता रहे हैं कि बजट का आकार क्या होगा? आप मुझे बताएं कि आपका दस्तावेज़ किसने तैयार किया है? इस दस्तावेज़ के प्रोड्यूसर और डायरैक्टर कौन हैं? पिछला वर्ष माननीय मुख्य मंत्री जी का पहला वर्ष था और आपने बजट में लिखा था कि वेतन पर इतने, पैंशन पर इतने, ब्याज पर इतने, कर्ज़ों की वापसी पर इतने, अन्य कर्जों पर इतने और रख-रखाव पर इतने पैसे खर्च होंगे। लेकिन इस बार आपको आंकड़े छुपाने की क्या जरूरत पड़ी?

मुख्य मंत्रीः माननीय मुकेश जी, इस पर सभी आंकड़े दर्शाए गए हैं।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय मुख्य मंत्री महोदय, आपने आंकड़े नहीं दिए हैं। आपने इस पर परसैंटेज लिखी है।

11.02.2019/1510/बी0एस0/डी0सी0-1

माननीय मुख्य मंत्री जी पिछले बजट में तो लिखा था कि 246 प्रतिशत कर्जा माननीय वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने बढ़ा दिया। कृपा करके वर्तमान की सरकार का भी बता

देते तो अच्छा होता। आप भी उसी तरीके से बजट बना रहे हैं जो पूर्व में बने थे लेकिन आप माननीय सदन को इस संदर्भ में आंकड़े ही न दें, माननीय सदन को आप बताएं ही न कि कितना-कितना खर्च किया है। यह ठीक नहीं है। इस बजट दस्तावेज का मतलब ही क्या रह जाता है। इसे इसलिए बनाया गया है ताकि माननीय सदन को जानकारी मिल जाए। आपका 44387 करोड़ रुपये का डाक्यूमैंट है । आपने 7352 करोड़ रुपये सीधे-सीधे राजकोशिय घाटे पर आ गए। आप बजट का आकार बताने की बजाए आप सीधे घाटे पर आ गए। प्राप्तियां एवं व्यय को कर्जे के माध्यम से पूरा किया जाएगा। आपने मात्र एक अंधी गली का रास्ता बताया है कि जो भी रेवेन्यू घाटा है उसे मैं कर्जों के माध्यम से पूरा करूंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी क्या आपको इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं मिला। क्या इसके अतिरिक्त कोई और सोच आपकी नहीं बनी ? मैं भाषण के आरंभ में आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कर्जे से बचना और अफसरों से बचना । दोनों चीजों से आपने बचना यह आपके लिए सही रहेगा। ...

श्री मुकेश अग्निहोत्री : क्योंकि जिस ढंग से अधिकारियां ने आपसे बजट की प्रेजेंटेशन करवाई है वह सही नहीं है। वैसे मैं आपकी नजर करना चाहता हूं,

मुझ पे तेरी नजर, तुझ पे मेरी नजर ।
यह सफर में जरूरी है हम सफर ॥
मैं संभलकर बहकने का गुर सीख लूं।
तू बहक कर संभलने का फन सीख ले।।

एक साल जश्न मनाते हुए सरकार का हो गया, काफी हो गया। अब बहकने की बजाए संभल कर गाड़ी चलाने का वक्त आ गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजकोषीय घाटा आपके सामने है। ये वही माननीय मुख्य मंत्री जी हैं जो हमें कहते थे कि घी पी करके शासन चलाते रहे। अब आप क्या कर रहे हैं? आपने तो यहां पर बड़े संस्कृत के श्लोक रखे थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सीधे तौर पर कहना चाहता हूं कि कोई भी सरकार हो

जैसी भी सरकार हो कोई भी सरकार खुद कभी नहीं कहती कि वे कर्जा ले करके शासन चलाएगी। कुछ-न-कुछ चाहे फर्जी हो, यहां पर कोई-न-कोई आंकड़ा रख दिया जाता है कि हम 10 प्रतिशत कर लगा देंगे। कह देते हैं कि हम पंजाब पुनर्गठन के तहत कुछ पैसा ले लेंगे। कुछ तो बोलते। लेकिन सीधे-सीधे छाती ठोक कर यह कहना कि मैं कर्जा लूंगा यह सही बात नहीं है। यह बजट प्रबंधकों को सीधेतौर पर शाबाशी देनी चाहिए जिन्होंने माननीय मुख्य मंत्री जी को किसी अन्य रास्ते पर चलने ही नहीं दिया। यह भी साफ हो गया कि मोदी सरकार से कुछ मिलने वाला नही है और न ही कुछ मिला है। आप संसाधन पैदा करने के कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं और न ही कोई आपने इशारा किया है कि आप प्रदेश में संसाधन पैदा करेंगे। एक नई थ्योरी फोरेन फडिंग की दे दी है। यह कहा गया है कि 10,330 करोड़ रुपये फोर्न फडिंग की जाएगी। यह माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनकी गंगोत्री दिल्ली में सूख चुकी है। उसमें रिजर्व बैंक के चेयरमैंन ने भी इस्तीफा दे दिया है। उनके पीछे ये पड़े रहे कि पैसा दो पैसा दो। जब इनको पता चला कि वहां से कुछ मिलने वाला नहीं है और न कुछ मिल रहा है । अब ऐसी-ऐसी बातें बजट में कही गई हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी आप शुद्ध मिला करके उधार की गाड़ी में सवार हो चुके हैं। आपकी यह कर्जे की सवारी का अंत में पता चलेगा क्या होगा। आप कहा करते थे कि माननीय वीरभद्र सिंह जी ने 17 हजार करोड़ के कर्ज ले लिए। आप कहां जा रहे हैं? पूर्व मुख्य मंत्री जी के लिए तो केन्द्र में कोपरेट करने वाली सरकार नहीं थी।

11.02.2019/1515/DT/DC-1

अब तो नगर निगम से लेकर दिल्ली तक आपकी सरकार है ,एक ही सल्तनत, एक ही सम्राज्य है और आप कर क्या रहे हैं? कर्ज लेकर आप सम्राज्य चलाएंगे और विकास के लिए पैसा है नहीं ,यह आपको मान लेना चाहिए कि आप किस ढंग से कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट को अगर आगे पढ़ें तो इसमें इन्होंने कहा कि सतत विकास लक्ष्य है हमारा और वर्ष 2022 मुख्यमंत्री जी का जब अखिरी साल आएगा इन्होंने कहा था कि वर्ष 2022 तक हम अधिकांश लक्ष्य की हम प्राप्ति करेंगे और इनकी जो

किताब है 'Fiscal Responsibility & Management' यह मेरे पास किताब है इसमें इन्होंने लिखा है कि वर्ष 2022-23 तक इन्ट्रस्ट पेमेंट के लिए 6621 रूपये चाहिए। आप किस ढंग से हिमाचल प्रदेश को दिवालियापन की तरफ ले जा रहे हैं आपने रेवेन्यू डैफिसिट जो 7.11 है अभी जिसकी आप बात कर रहे हैं। आपने जो प्रोजैक्शन दी है 16.72 की 16.72 मुख्यमंत्री जी आप खुद ही अन्दाजा लगा लो जब 16.72 पे जाएगा तो हिमाचल प्रदेश किधर जाएगा और वर्ष 2022 के बाद तो जी0एस0टी0 का रिफंड भी नहीं मिलेगा, कोई पैसा नहीं होगा आपके पास । आप हिमाचल प्रदेश को ऐसी जगह खड़ा कर जाएंगे, यह स्थिति मैं नहीं ब्यान कर रहा हूं। यह आपकी दी हुई किताबें ब्यान कर रही हैं जिसमें आपने लिखा है यह तो आपके अधिकारियों ने आपको ढंग से पढ़ाई ही नहीं । मैं आपको यह कहना चाहूंगा 30.6.2022 के बाद जी0एस0टी0 का रिफंड नहीं मिलेगा और 1.7.2022 के बाद प्रदेश का रेवेन्यू पूरी तरह प्रभावित हो जाएगा । और non-availability of GST compensation जिस ढंग से आपके ऊपर बैठने वाली है अगर आपने टैक्स कलैक्शन को इम्प्रूव नहीं किया तो आपको बजट पेश करने में मुश्किल हो जाएगी। इस विधान सभा में जो स्थिति आपने खड़ी कर दी है कर्जा 50 हजार करोड़ छू गया है और 60 हजार करोड़ को छू जाएगा आपकी किताबें ही दिखा रही हैं जो आपने अपना विजन डॉक्यूमैंट प्रस्तुत किया है। हिमाचलियों के आगे, सारे हिमाचल प्रदेश के आगे यह विजन डाक्यूमैंट मेरे पास भी है। आपने कहा है कि आप कर्ज मुक्त राज्य बनाएंगे। आपका विजन तो कर्ज मुक्त राज्य था अब आप धड़ल्ले से कह रहे हैं कि कर्जे थोक में लिए जाएगे ।

मुझे कई दफा बड़ी हैरानी होती है। हमारे प्यारे साथी हैं माननीय रमेश चंद ध्वाला जी आप इनको क्यों परेशान कर रहे हैं प्लानिग बोर्ड खत्म हो गया है। नीति आयोग बन चुका है आप इनको क्यों झूठी सवारी करवा रहे हो, देश में नहीं अब प्लानिग बोर्ड और इनको बैठा दिया अध्यक्ष बना के इनका गुस्सा तो जायज है, इनको गुस्सा आ जाता है। नीति आयोग हो गया है सारे देश में और हिमाचल प्रदेश में प्लानिंग बोर्ड बनाया जा रहा है। ....(व्यवधान)...

माननीय मंत्री जी मैं विधायक के इंस्टीच्यूशन को स्ट्रेंथन करने का पक्षधर रहा हूं। आपने माननीय ध्वाला जी को गाड़ी दी हमें अच्छा लगा कि हमारा साथी है और गाड़ी दी आपने दूसरे साथी को चाहे चीफ व्हिप बना के ही किसी ढ़ग से रास्ता निकाला कोई बात नहीं ,हमारा साथी है लेकिन रास्ते तो सही निकाले जाएं । अब आप यह पेश कर रहे हैं कि 71 सौ करोड़ की आपने प्लान बना दी आप बताओ कि उस प्लान में दिल्ली क्या देगा ? देगा एक पैसा भी आपने अपने अधिकारियों से पूछा कि काहे की प्लान बन रही है अब तो नीति आयोग है और एक ढर्रे पे चले हुए है आप कर रहे हैं करते जाओ। पहले प्लानिग कमीशन होता था कम से कम 90-10 में कोई न कोई फंडिग आ जाती थी

11-02-2019/1520/एच.के./एन.जी./1

और कोई ना कोई नया प्रोजैक्ट आ जाता था परन्तु इस बार तो दिल्ली के बजट में भी कुछ नहीं लिखा गया है । आप विकास दर की बात कर रहे थे कि मेरी विकास दर 7.3 आ गई है। श्री वीरभद्र जी के समय में वर्ष 2015-16 में 8.1 थी, फिर आपकी नोटबन्दी आ गई और विकास दर डिप कर गई । 2015-16 में विकास दर 8.1 आ चुकी थी । लेकिन आप विकास दर की बात करते हैं, माननीय मुख्यमन्त्री जी मुझे आप यह बताईए की रोजगार देने का आप कोई रास्ता नहीं निकाल पा रहे हैं । हिमाचल प्रदेश के सभी एम्पलाएमैन्ट एक्सचेंज में 1 लाख 37 हजार 662 नए लोगों के पंजीकरण हुए है । यहां हम सब साथी लोगों के पास लोग आते हैं और कहते हैं कि नौकरी लगा दो । 1 लाख 37 हजार 662 नए लोगों के पंजीकरण हुए है पिछले साल, आप यह बता दें की कितने लोगों को नौकरी दी है । आप नौकरी का आंकडा दें क्योंकि बेरोजगारी का आंकडा 12 लाख से बढ कर 13 लाख हिमाचल में पहुंच गया है । यह हम सब के लिए चिन्ता का विषय है । आप यह इतराते हुए नहीं हट रहे कि मैने बहुत काम किया ।

उपाध्यक्ष महोदय टूरिज्म में गिरावट आ गई, जितने टूरिस्ट हिमाचल में आते थे उनकी संख्या गिर गई और यह आपकी किताब में लिखा हुआ है । आपने पिछली किताब में

लिखा था कि अब मैं क्वालिटि टूरिस्ट लाऊंगा लेकिन आपके विदेशी टूरिस्ट की संख्या गिर गई और यह भी किताब में आपने लिखा है । हिमाचल प्रदेश फल राज्य है और यहां फलों का उत्पादन गिर गया, आपने अपनी किताब में लिखा है कि फल उत्पादन गिर गया। आपने लिखा है कि खाद्य उत्पादन इस प्रदेश में गिर गया । माननीय सदस्य यह एक गम्भीर मुद्दा चल रहा है । आपकी किताबों में यह सब लिखा हुआ है । माननीय श्री राकेश पठानिया जी आज आपका दिन नहीं है । आपके पीछे सदस्य लगे हुए हैं, जिन्होने बोलना है। क्या आप अपने माननीय सदस्य को हल्का मान रहे हैं ? उपाध्यक्ष महोदय, बजट किस ढंग से रखा जाता है, बजट में सिर्फ यह नहीं होता कि एक्सपैन्डीचर कर दिया । माननीय मुख्यमन्त्री जी ने बजट किस ढंग से पेश किया जैसेलोहडी के त्यौहार में "सुन्दर मुन्दरीय हो तेरा क्या...", किसी को दो सौ दे दो, किसी को पांच सौ दे दो, किसी के हाथ में च्वन्नी रख दो, किसी के हाथ में रेवडी रख दो । आपने प्रदेश के विकास की प्लौनिंग कहां की ? आपने डैवलपमैंट का थीम कहां दिया इसमें ? विकास की बात कहां की आपने ? इस बजट में डैवलपमैन्ट सबसे बडी कैजुअलिटी हुई है । विकास की कोई बात आपने पूरे दस्तावेज में नहीं रखी । आपने चुनावों को देखते हुए कह दिया कि जो पिछले साल लोगों के बढाए थे उनको दो सौ रूपये, पांच सौ रूपये, सौ रूपये आगे बढाने की कोशिश की है लेकिन आपने विकास की तो बात कहीं पर नहीं की है । आप कर्जे के दलदल में फंस रहे हो और रिसोर्स मोबेलाईजेशन की बात नहीं कर रहे हो । उपाध्यक्ष महोदय, नए-नए निगम-बोर्ड क्रिएट कर रहे हैं । यह वहीं मुख्यमन्त्री हैं जो सदन के बाहर कांग्रेस के निगम बोर्डों के खिलाफ आग उगलते रहे कि कांग्रेस ने यह बना दिया, ये निगम के अध्यक्ष बना दिए, 25 बना दिए, 30 बना दिए तो आप क्या कर रहे है ? आपने अभी थोक में निगम-बोर्ड के चेयरमैन बना दिए और जिस दिन सदन खतम होगा उस दिन आप और बना देंगे । उपाध्यक्ष महोदय, कर्जे से सरकार चलानी है और रोज नए बोर्ड बनाए जा रहे हैं । एक बनाया है पौंग क्षेत्र विकास बोर्ड, पौंग डैम का बना रहे तो गोविन्द सागर क्यों नहीं बना रहे हो ? गुडिया बोर्ड, युवा नव जीवन बोर्ड, गोवंश संवर्धन बोर्ड, हायर एज्यूकेशन कोसिंल,

क्या-क्या बना रहे हो आप ? क्या आप रोजाना नए बोर्ड बनाऐंगे? आज दिन तक आप कहते थे कि पुराने निगमों-बोर्डों को मर्जर की आवश्यक्ता है, कम करने की जरूरत है । आप राजनैतिक लोगों को वहां पर जगह देने के लिए कोई न कोई रास्ता निकालते जा रहे हैं । उपध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमन्त्री जी ने बजट में 18 स्कीमें दी हैं और मुख्यमन्त्री जी को पता ही नहीं है कि मैने कितनी दी है । प्रैस को इन्होने कहा है कि 18 स्कीमें दी हैं । इनका प्रैस नोट जो जारी हुआ है उसमें 18 स्कीमें आ गई मैने सारी पढी है । अगर आपने सुननी हैं तो आपको 18 की 18 गिना देता हूं ।

11/02/2019/1525/RG/HK/1

मुख्य मंत्री : स्कीम अलग होती है, इनिशियेटिव अलग होता है।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : नहीं-नहीं, इस हिमाचल में जाना जाएगा कि हमारा मुख्य मंत्री बड़ा स्कीमी है। यह बात जरूर आएगी। आपने 30 स्कीमें पिछले साल दे दीं , 18 स्कीमें आपने इस बार दे दीं और आप स्वयं ही नहीं बता रहे हैं कि कितनी स्कीमें हैं? आप बताएं कि आप हर साल कोई-न-कोई नया मायाजाल बुनते हैं, कुछ-न-कुछ आप सोचते हैं। पहले आपने नेशनल हाईवे को चुना। उसके बाद आप सेन्टर से 9,000 करोड़ रुपये की ग्रांट पर आ गए, फिर आपके मंत्री जी 14,000 पर आ गए और तीसरे मंत्री 15,000 पर आ गए और रोज़ बोलियां लगाते थे कि इतने हजार करोड़ रुपये आ गए। अब आप फौरेन फण्डिग पर आ गए, जो आपके नंबर-2 हैं, इन्होंने आपको नया रास्ता फौरेन फण्डिग का दिया। यह फौरेन फण्डिग किसकी है? मैं देख रहा था कि आपने लिखा क्या है? फौरेन फण्डिग में आपने क्या कहीं भी यह लिखा है कि किसी भी फौरेन फण्डिग या जिन प्रोजैक्ट्स की आप बात करते हैं, क्या किसी का पैसा भी आया? आप कब तक कागज़ी संसार में या सैद्धान्तिक मंजूरियों में घूमते रहेंगे?

मुख्य मंत्री : मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग यह पैसा क्यों मांगते हैं?

श्री मुकेश अग्निहोत्री : माननीय उपाध्यक्ष जी, यह देखिए कि तानाबाना कैसे बुना हुआ है? पुरानी सिंचाई योजना के नवीनीकरण के लिए 4070 करोड़ रुपये का कन्सेप्ट नोट तैयार

है और फौरेन फण्डिग के लिए प्रेषित हो रहा है। 'Doubling of Farmer's Income through Water Conservation and Other Activities' के लिए भारत सरकार ने 708 करोड़ रुपये की संस्तुति एशियन विकास बैंक को भेज दी है। 'हिमाचल बाढ़ एवं नदी प्रबन्धन परियोजना' Asian Infrastructure Investment Bank(AIIB) को अभी भेजा जा रहा है, संस्तुति की जा रही है। --(व्यवधान)---इसमें पहले चरण में 1,288 करोड़ रुपये और दूसरे चरण में 2,062 करोड़ रुपये मिलेंगे। इसके अतिरिक्त Himachal Pradesh Sub Tropical Horticulture, Irrigation and Value Addition(SHIVA) फलों के लिए 1,688 करोड़ रुपये के लिए ए.डी.बी. को संस्तुति की जा रही है या भेजा जा रहा है। इसके बाद 'Securing Rural Livelihood through Bio-Diversity Conservation, Landscape Management and Skill Development का 250 करोड़ रुपये, 'Disaster Risk Reduction and Preparedness Project in Himachal Pradesh' में भी 2,420 करोड़ रुपये की फौरेन फण्डिग का जिक्र है। ये सब संस्तुतियां की जा रही हैं और आपने मायाजाल ऐसा फैला दिया कि पता नहीं 13,000 करोड़ रुपये हिमाचल प्रदेश के कोष में जमा हो गया। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं और हिमाचलियों से फरेब क्यों कर रहे हैं? हिमाचल प्रदेश की जनता से आप लगातार धोखा क्यों कर रहे हैं? मुख्य मंत्री जी, यह जो आपका तौर-तरीका है, मेरा आपको यह कहना है कि आप तबियत से काम करो।

कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता,
एक पत्थर तो तबियत से उछालो, यारो।

आप थोड़ा तबियत से काम करो। लेकिन जिस तरीके से आप चल रहे हैं, वह ठीक नहीं। माननीय उपाध्यक्ष जी, इन्होंने यहां आरक्षण की बात की। इन्होंने आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के परिवारों को, नौकरी एवं शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का दावा किया है। दो कैबिनेट हो गईं, अभी बहुत समय है। एक कैबिनेट 19 जनवरी और दूसरी 5 फरवरी को हुई। आप यहां कह रहे हैं कि हमने यह कर दिया। क्या यह सच्चाई नहीं है कि आपने यह मसला तीन मंत्रियों की समिति को भेजा है, तीन मंत्रियों की समिति के बारे में समाचार-पत्रों में छपा है। यह एक उप-समिति बनाई गई है जिसमें श्री सुरेश भारद्वाज जी, माननीय शिक्षा मंत्री, श्री वीरेन्द्र कंवर जी, माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री तथा श्री रामलाल मारकण्डा जी, माननीय कृषि मंत्री जी को नामज़द किया गया है। आपका जो

कैबिनेट नोट मैंने देखा, उसमें केवल बी.पी.एल. को आरक्षण हुआ है। इसमें 4,00,000/- रुपये तक आय सीमा का प्रस्ताव उसमें आया और केन्द्र सरकार ने 8,00,000/-रुपये तक की आय का प्रस्ताव किया था और आपने यहां 4,00,000/-रुपये तक की आय का ही प्रस्ताव किया है। आप कम-से-कम कैबिनेट तक तो फैसला कर लो। जो केन्द्र सरकार ने आरक्षण के बारे में फैसला किया, आप तो फैसला ही नहीं कर पा रहे हैं कि इसको कैसे देंगे? आप एस.सी., एस.टी. और दूसरे वर्गों को डिस्टर्ब किए बिना इस आरक्षण को कैसे लागू करेंगे? आपने मंत्रि-मण्डल की उप समिति बनाई और यहां दस्तावेज़ में लिख दिया। जबकि सबसे बड़ी सैंक्टिटी इस सदन की है और यहां हर बात सही तरीके से रखी जानी चाहिए।

11/02/2019/1530/MS/YK/1

पिछले साल जो 30 योजनाएं आपने यहां पर अनाउंस की थीं, उनकी सक्सैस स्टोरी तो बता दीजिए? बजट भाषण समाप्त करने के बाद मुख्य मंत्री जी मुंह जुबानी बोल रहे हैं कि वे योजनाएं निरन्तरता में रहेंगी। लिखने का साहस नहीं हो रहा है। आपको इन सब योजनाओं पर पहले एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। आज भी मेरा इस बारे में प्रश्न लगा था लेकिन जवाब आया कि इन 30 योजनाओं की सूचना एकत्रित की जा रही है। आपको ही पता नहीं है कि आपकी महत्वाकांक्षी योजनाओं की क्या स्थिति है? आपको कुछ तो पता होना चाहिए कि एक साल में कितनी योजनाएं आगे बढ़ी हैं, किसके लिए कितने पैसे रखे थे, कितने खर्च हुए और स्कीमवाइज लाभार्थी कौन-कौन हैं। लेकिन अभी तक स्कीमें नोटिफाई होती जा रही हैं। आपने जितनी भी ये स्कीमें लाँच की थीं, उन सबके आपके सारे पैसे बच गए हैं क्योंकि कोई स्कीम शुरु ही नहीं हुई। कोई स्कीम अभी अधिसूचित हो रही है और कोई स्कीम अभी कैबिनेट में जा रही है। आपका दूसरा बजट लग रहा है लेकिन अभी तक आप पहले की योजनाओं के ही टैण्डर लगा रहे हैं।

इसी तरह आपने पंचायतों में कोई मोक्षधाम नहीं बनाए। आपने पिछली बार कहा कि युवाओं को नौकरी देने के लिए "मुख्य मंत्री स्वावलम्बन योजना"में 40 लाख रुपया दूंगा और इस बार कह दिया कि 60 लाख रुपये दूंगा। आपने पिछले साल 40 लाख रुपया कितने युवाओं को दिया? एक आपने 30 लाख रुपये वाली "मुख्य मंत्री युवा आजीविका

योजना" दी थी। आप बताइये कि उसके कितने लाभार्थी हैं? आपने कह दिया कि हमने उम्र बढ़ा दी और 18 से 45 कर दी जबकि आपके पास डाटा ही नहीं है और बैंक वालों ने किसी युथ को लोन नहीं दिया। यह आपको पता होना चाहिए। "पब्लिक सर्विसिज गारन्टी ऐक्ट" के बारे में आपने कहा कि इसको लागू करूंगा जबकि वह पहले से ही लागू है। आप उसको क्या लागू करेंगे?

इसी तरह से राशन से संबंधित योजना आदरणीय वीरभद्र सिंह जी ने चलाई थी और राशन जनता को मिल रहा है। इसके अलावा "मुख्य मंत्री खेल संरक्षण योजना" भी वीरभद्र सिंह जी ने चलाई थी और आपने कहा कि ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य, कोई ठण्डे बस्ते में नहीं है। आपने कहा कि जाल लगाने की अनुमति दूंगा।

अगर आप सोलर पैनल लगाने के लिए 85 परसेंट सब्सिडी दे रहे हैं तो जाल लगाने के लिए 50 परसेंट सब्सिडी क्यों देंगे जबकि लोगों की मांग जाल की है? उसके बाद पॉली-हाउस योजना का भी यही हाल है। अभी हाल ही में ट्रिब्यून में पॉली-हाउस के ऊपर एक आर्टिकल आया था कि यह योजना पूरी तरह से पिट गई है। फिर आपने "मुख्य मंत्री नूतन पॉली-हाउस योजना" शुरु कर दी। अब यह नए नाम से योजना आ रही है लेकिन पहले उसकी समीक्षा तो कर लीजिए कि पॉली-हाउस का क्या हाल है। इसी तरह से कह रहे हैं पुराने मीटर बदले जाएंगे। अरे! मीटर लगातार बदले ही जा रहे हैं, इसमें क्या नया काम हो रहा है? फिर "विद्यार्थी वन मित्र योजना" के बारे में कहा। आपने दूसरे बजट में लिखा कि इसके लिए 150 स्कूल चयनित किए जाएंगे। पिछले साल स्कीम लॉंच की और दूसरे बजट में लिख रहे हैं 150 स्कूल चयनित करेंगे। यहां पर वन मंत्री जी दहाड़ कर बोलते थे कि वन कर्मियों को हथियार दिए जाएंगे। अब कह रहे हैं कि उनको हथियार खरीदने के लिए 15000/-रुपये दिए जाएंगे। पहले वाली आपकी स्वावलम्बन योजना चली नहीं और अब एक और नई "स्वरोजगार मुख्य मंत्री ग्रीन टैक्नोलॉजी ट्रांसफर स्कीम" लॉंच कर दी और इसके अंतर्गत अब आप आजिविका देंगे। आप जितनी मर्जी योजनाएं लॉंच करते रहो, कोई फायदा नहीं होगा। बैंटनी कैसल वीरभद्र सिंह जी ने एक्वायर किया था, उसमें क्या नया है? इसी तरह "होम स्टे योजना" पहले से चल रही है। स्वास्थ्य में सहभागिता के नियम आपने ऐसे बनाए हैं कि उसको कोई लेने वाला नहीं है। "मुख्य मंत्री खेल विकास योजना"

भी वैसी ही है। एक तो अफसरशाही आपके साथ बहुत खिलवाड़ कर रही है और हर काम के आगे वे मुख्य मंत्री लगा देते हैं। और तो और एक दीन दयाल उपाध्याय नामक स्कीम थी, उसका नाम भी इस बार मुख्य मंत्री योजना के नाम से कर दिया है। आप इन पर थोड़ा बहुत चैक रखो कि ये आपके साथ क्या कर रहे हें। जिस ढंग से मुख्य मंत्री जी इन योजनाओं का हश्र हो रहा है, इनको आपको देखना चाहिए। आपको इनके सक्सैस रेट को देखना चाहिए। इनमें लाभार्थी देखिए कि कौन-कौन हैं तथा कौन सा विभाग किस स्कीम को चला रहा है। मुझे लगता है कि आपके बजट का प्रोड्यूसर/डायरैक्टर अभी भी पुराना ही है क्योंकि जिस अंदाज में लिखा गया है, वह वही निराला है।

मुझे लगता है कि बैक सीट से कहीं ड्राइविंग हो रही है। मुख्य मंत्री जी आपने राष्ट्रीय राज मार्ग टच करने की भी जरुरत नहीं समझी। ऐसी भी क्या नाराजगी हो गई है कि आपने बजट डॉक्यूमैंट से नेशनल हाइवे गायब कर दिया और फोरलेन प्रोजैक्ट्स को आप वैसे ही पी गए। आपने पिछली बार कहा था कि 65 हजार करोड़ रुपये के 69 नेशनल हाइवे बनाऊंगा।

11.02.2019/1535/जेके/वाईके/1

अगर हमने बात उठा दी तो आप इतना बुरा मान गए और आपने इसे दस्तावेज़ से भी हटा दिया। आप ऐसा मत करो। आप ऐसे तो नहीं थे। आप क्या कर रहे हो? आप इनको दस्तावेज़ से ही हटा रहे हैं। आपने कहा था कि मैं राम राज्य बनाऊंगा। अब आप राम राज्य की बात ही नहीं कर रहे हैं। ...(व्यवधान)... पिछले बजट में आपने कुछ मार्गदर्शक के सिद्धांत लिखे थे। इस बार वे सारे सिद्धांत लुट गए। उनकी यहां पर कोई चर्चा नहीं हुई। आपने कहा था कि मैं जन-अधिकार पुस्तिका पेश करूंगा। कहां है वह जन-अधिकार पुस्तिका? हम भी उसमें नज़र डालें कि उसमें क्या-क्या लिखा है? इसमें परवाणू- शिमला, कीरतरपुर-मनाली हाइवे का कोई जिक्र नहीं है। आप रिपोर्ट कार्ड तो रख देते। पहले आपने थोड़ा-बहुत सूरंगों के बारे में लिखा था उसका आप इस बार हल्का-फुल्का ही जिक्र कर देते। सैंज-लूहरी-ऑट की सूरंग कहां जा रही है? क्वालिटी मॉनिटरिंग की पिछली

दफा चर्चा की थी और इस दफा आपने लिखने की जरूरत ही नहीं समझी। एच0पी0 रोड़ प्रोजैक्ट फेज़-1 और ॥ के 720 करोड़ रुपये सारे-के-सारे दूसरा बजट आते-आते हवा हो गए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्मार्ट सिटी के लिए इन्होंने कहा कि मैं इस दफा टैंण्डर करवा दूंगा। आप कहां से टैण्डर करवा देंगे? आपने पिछले बजट में लिखा 2110 करोड़ धर्मशाला के लिए और 2905 करोड़ रुपया शिमला के लिए है। अभी हमने प्रश्न लगाया आपने कहा धर्मशाला के लिए 6 करोड रुपये और शिमला के लिए 24 करोड़ रुपये साल के दौरान आए हैं। कहां से आप स्मार्ट सिटी बनाएंगे? आप कह रहे हैं कि मैं टैण्डर भी इन्वाइट करवा दूंगा। ये सब खोखली बाते हैं। आपको केन्द्र सरकार ने कुछ नहीं दिया। आपकी स्मार्ट सिटी पूरी तरह से पिट गई हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप मुख्य मंत्री हैं, मंत्री लोग तो लालच कर लेते हैं कि हमारे इलाके का थोड़ा बहुत विकास हो जाए और मेरी सीट निकल जाए लेकिन आप तो मुख्य मंत्री हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप संतुलित तरीके से सरकार चलाएं। मण्डी में शिवधाम बनेगा, मण्डी ब्यास में घाट बनेगा और हवाई अड्डा नागचला में बनेगा। ...(व्यवधान)... ऐसा मत करो। यदि आप बंदरबांट करेंगे तो मुख्य मंत्री और मंत्री आपस में 680 करोड़ रुपया बांट लेंगे। यह कोई तरीका है? हवाई अड्डा नागचला में बनेंगा। आप आज कह रहे हैं कि अभी कुछ नहीं हुआ और अभी प्रश्न भी लगा था। सांस्कृतिक केन्द्र जंजैहली में बनेगा। मुख्य मंत्री जी जंजैहली से आगे बढ़ो। आपके पास बहुत आगे तक आसमान है। आप जंजैहली से आगे चलो। फार्मेसी कक्षाएं सराज में चलेंगी। हिमाचल प्रदेश के लोगों ने आपके सुपुर्द इतना बड़ा प्रदेश किया है। आप कुछ थोड़ा आगे बढ़ो । बगुलामुखी में हम सभी नेताओं का विश्वास है। अगर बगुलामुखी माता मंदिर का कुछ करना है तो कांगड़ा वाली का भी कर दो। आपके लिखे हुए शब्द हैं हम तो उससे बाहर एक कदम भी नहीं जाएंगे। यह आपके दस्तावेज़ में लिखा हुआ है।

मुख्य मंत्री जी, आपने यहां पर किसान के कर्ज़े की बात कही। आपने यहां पर कहा कि किसान की आय डबल कर देंगे। ...(व्यवधान)... हम मण्डी के पक्षधर हैं। आप कांगड़ा,

ऊना, हमीरपुर, चम्बा, और दूसरे राज्यों को भी दो आप ऐसा मत करों कि 680 करोड़ रुपये ...(व्यवधान)... आए और अकेले मंत्री महोदय 250 करोड़ रुपये ले जाए। आपको भी ठग दिया। आपको कहा कि दूसरे चरण में मिलेंगे। मैंने आपका देखा तो मैंने सोचा कि मंत्री जी क्या कर रहे हैं और आपको कहा कि दूसरे चरण में मिलेंगे। आपने किसान की आय को डबल करने के लिए क्या किया है? आपने कहा कि किसान की आय डबल होगी तो कैसे होगी? कोई योजना तो आपने दी होती। जुमलेबाजी से तो काम नहीं चलेगा। आपके पीछे मंत्री जी बैठे हैं। मंत्री जी, आप जितनी मर्ज़ी योजनाएं बनाओ, चाहे भैंसों की बनाओ, चाहे बकरियां बांटों ...(व्यवधान)...लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि जितना जानवरों का आतंक हिमाचल प्रदेश में है, इस आतंक से आप हिमाचल को निज़ात दिलाएं। ...(व्यवधान)...माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। बंदरों का आतंक शांत करो।

11-02-2019/1540/SS-AG/1

पिछली दफा इन्होंने कहा कि बेसहारा पशुओं के मालिकों की पहचान की जायेगी।

उपाध्यक्षः मेरा सभी से निवेदन है कि कृपया शांति बनाये रखें।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः आप बताएं कि क्या आपने किसी एक बेसहारा पशु के मालिक की तलाश की? आपने इसके बारे में बजट में लिखा हुआ है। आप बताओ कि किसको आपने तलाश किया है? सिर्फ यह लिख देना कि वाटर कंजरवेशन का एक प्रोजैक्ट ए0डी0बी0 को भेजा जा रहा है, क्या इससे किसान की आय डबल हो गई? इस ढंग से आपने काम किया है।

शिक्षा मंत्री जी, आप कृपया बैठिये। आप शिक्षा में क्या कर रहे हैं? आप कहते हैं कि अटल आदर्श स्कूल बनायेंगे। पिछली बार 10 अटल आदर्श स्कूल कहा था और दो भी नहीं बने। दो का पत्थर ज़रूर रखा था। इस बार कहा है कि 15 अटल आदर्श स्कूल बनायेंगे। ऐसे गपोड़शंखों की तरह व्यवहार मत करो। पिछली बार 10, इस बार 15 अटल आदर्श स्कूल खोले जायेंगे और खुला एक भी नहीं। यह क्या हो रहा है? आप स्कूल के बच्चों को वर्दी तो

दे नहीं सके। स्कूल के बच्चों को आपने अभी तक वर्दी नहीं दी। लैपटॉप नहीं दिये। बेचारे पत्रकारों को कह दिया कि लैपटॉप मिलेंगे। भाई, स्कूल के बच्चों के पीछे लग जाना। लाइन में उनके पीछे लग जाना। कब स्कूल के बच्चों को लैपटॉप मिलेंगे और कब उनके बाद पत्रकारों की बारी आयेगी। ...(व्यवधान)... कोई बात नहीं, लिखा ही जायेगा जो हम कहेंगे। शिक्षा मंत्री जी, स्कूल के बच्चों को वर्दी दो। 8.24 लाख बच्चों से आपने धोखा किया है। आपने उनको स्कूल की वर्दी नहीं दी। आपने उनको लैपटॉप नहीं दिया। आपने पहले कहा था कि 50 हजार बच्चों को अंग्रेज़ी सिखायेंगे। इस बार कह दिया कि 50 स्कूलों में संस्कृत सिखाई जायेगी। आप क्या बातें कर रहे हैं? आपने 50 हजार बच्चों को अंग्रेज़ी तो सिखाई नहीं और अब आप उनको संस्कृत सिखायेंगे। यह आप किस ढंग से कर रहे हैं?

पी0टी0ए0, पैट, पैरा,एस0एम0सी0, सबको आप कहते थे कि आपको रेगुलर कर देंगे। आप किसी को रेगुलर नहीं कर पाए। आप (शिक्षा मंत्री) बैठ जाएं और अपनी टर्न पर बोलना। ...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरा टाइम ऐड कर लेना। उपाध्यक्ष महोदय, पत्रकारों को लैपटॉप देने के बजाय जैसे पंजाब, हरियाणा पैंशन दे रही है वैसी कोई योजना इनके लिए शुरू कर देते या कुछ और करते, तो ठीक रहना था।

उपाध्यक्षः कृपया बीच में न बोलें।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः हैल्थ में बात की। लेकिन डेंगू के बारे में कोई बात नहीं की। आज स्वाइन फ्लू फैला हुआ है, उसकी आप बात नहीं कर रहे जबकि 16 मौतें हो गईं। किस ढंग से लोग मर रहे हैं। हॉस्पिटल्ज़ और मेडिकल कॉलेजों की हालत क्या है? उसकी आप किस ढंग से बात कर रहे हैं।

कानून-व्यवस्था की आप क्या बात करेंगे, इस बार 98 मर्डर हुए हैं, 345 रेप हुए हैं। एक प्रकरण पर हिमाचल कितना अशांत हुआ था, लेकिन आपके राज में 345 रेप हो गए।

आप कोई रेल की बात नहीं कर रहे हैं। आप कोई ऐयर की बात नहीं कर रहे हैं। जैसा ठाकुर राम लाल जी ने सवाल किया था, आपने नहीं बताया कि मंदिरों से कितना पैसा

आया है, कितना शराब से पैसा आया है, कितने आपने उससे गौसदन बनाए हैं, आप कोई जवाब ही नहीं देते।

मंत्री जी, आपने वाटर गार्डों के बारे में नीति बनाने की बात कही थी। आप और मुख्य मंत्री जी ने इकट्ठे लोगों को सम्बोधित किया था, क्या आपने उनके लिए नीति बनाई? आपने थोड़ा-सा पैसा बढ़ा दिया। आप बेरोज़गारों से ऐसा खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? अगर आपने नीति कही थी तो आप नीति बनाते। आपने आउटसोर्स की चर्चा नहीं की। कंट्रैक्ट वालों की आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। ओल्ड पैंशन स्कीम की आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। किसानों के कर्जे आप माफ नहीं कर रहे हैं। नेशनल हाईवे आप बना नहीं रहे हैं। ...(व्यवधान)... आप करो न। वाजपेयी जी ने बंद की थी, आप शुरू करवाओ। आप किसान का कर्जा प्रदेश में माफ करना शुरू करो।

मुख्य मंत्री जी, जिस प्रदेश में हर घर में बिजली लम्बे अरसे पहले आ गई, उस प्रदेश में 'मुख्य मंत्री रोशनी योजना' शुरू हो रही है। आपको मुख्य मंत्री रोशनी योजना आज शुरू करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? हिमाचल प्रदेश में हर घर में बिजली है। यह रिकॉर्डिड है। अब आप बेरोज़गारी भत्ते की बात नहीं कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार कहा कि 65 हजार युवाओं को कौशल से रोज़गार देंगे। दीन दयाल उपाध्याय योजना, फिर कहा कि प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के तहत 49500 को रोज़गार संबंधी कौशल दिलवाया जायेगा। इस बार 32 हजार पर आ गए। पिछली बार के 65 हजार को क्या आपने नौकरियां दे दीं, जो आपने लिखा था कि कौशल से रोज़गार दिलवाया जायेगा? आप व्हाइट पेपर जारी करो या सूची जारी करो कि इन 65000 लोगों को आपने नौकरियां दी हैं। आप किस ढंग से सरकार चला रहे हैं?

इंडस्ट्री के बारे में आप बताएं। हमने तो पंडोगा और कंदरोड़ी को पैसे दिये थे। आपने कहा कि कांगड़ा के चिनौर में बनेगा, बिलासपुर के गेहड़वी में बनेगा, ऊना के बसौली में बनेगा, क्या आपने कोई पैसे का प्रावधान किया? मुख्य मंत्री जी, मैं आपको कह रहा हूं कि शासन गम्भीरता से चले।

आपने पिछली बार कहा था कि हिम प्रगति मॉनिटरिंग मुख्य मंत्री जी आप खुद करेंगे। हिमाचल की प्रगति की मॉनिटरिंग का आपने स्पैशल खुलासा किया था कि आप खुद उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। आप बतायें आपने कितनी बार हिम प्रगति के बारे में अधिकारियों के साथ मीटिंग की कि क्या प्रगति हुई है? आप ग्लोबल इन्वैस्टर मीट की बाहर तो बात करते जा रहे हैं कि 80 हजार करोड़ रुपये का निवेश लाएंगे लेकिन बजट के अन्दर लिखने में आपको क्या दिक्कत हो रही है? आपने इसमें उसकी कोई चर्चा नहीं की। इसके अलावा खनिज से नीलामी हम शुरू करके गए हैं, ऐसी बात नहीं है । ऊर्जा का आपका सैक्टर बैठ रहा है, इंडस्ट्री में प्लायन हो रहा है, इसको देखने की जरूरत है। चम्बा के सीमेंट प्लांट की आपने पिछली बार बात की थी लेकिन इस बार इस बजट में उसकी कोई बात नहीं कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 922 करोड़ रु0 की स्वां की योजना कांग्रेस के समय की है। टूरिज्म में 2 हजार करोड़ रु0 का प्रोजैक्ट कांग्रेस के समय का है। बागवानी का 1134 करोड़ रु0 का प्रोजैक्ट श्री वीरभद्र सिंह जी के समय का है। फोरैस्ट प्रोस्पैक्टिव प्रोजैक्ट आपने सरंडर कर दिया। अब एक साल तेरह-चौदह महीने के बाद आप कह रहे हैं कि नई पर्यटन नीति आएगी, नई खेल नीति आएगी, नई उद्योग नीति आएगी? इतनी देर के बाद आप जाग रहे हैं। आपको माया-जाल फैलाने की आदत पड़ गई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज की ट्रिब्यून में भी एक खबर आई है, अब कह रहे हैं कि "मेरा परिवार, भाजपा परिवार" नाम से एक नई स्कीम लाँच होगी। एक स्कीम लाँच होगी और लोगों के घरों पर झंडे लगाए जाएंगे कि गवर्नमैंट स्कीम के बेनीफिशरीज़ कौन हैं? ...(व्यवधान)... आप मुझे बताएं। It is total mis-utilization of Government funds for political gains. आपने धर्मशाला में रैली की। आप कह रहे थे कि बैनीफिशरीज़ को ले कर चलो। बी.डी.ओ. ले कर जाएगा, चीफ सैक्रेटरी ले कर जाएगा, पंचायत सैक्रेटरी ले कर जाएगा, अब आपने दूसरा चरण कर दिया कि जिनको कुछ मिला है, वे अब भाजपा के झंडे लगाएंगे । ये आप क्या कर रहे हैं? सरकारी मशीनरी का इतना दुरूपयोग आप करेंगे और मुझे समझ नहीं आता ऑफिसर्ज़ गैलरी में

बैठे लोग ये सारी बातें कैसे अलाउ कर रहे हैं कि प्रधान मंत्री की रैली में झंडे भी हम लगा देंगे, रैली भी हम करवा देंगे, पैसा भी हम दे देंगे...(व्यवधान)...

उपाध्यक्षः मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन हैं कि बीच में न बोलें। आपको भी समय मिलेगा। मुकेश जी, कृपया वाइंड अप करें।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा था, इनकी सारी पॉलिसीज़ पिट गई। जिनकी मुख्य मंत्री जी बात कर रहे हैं, इनको अगर रिवाइज्ड पे स्केल देने पड़े तो पता लग जाएगा कि स्टेट की क्या हालत है। पुरानी बेसिक पे पर आप दे रहे हैं और अगर असलियत में देने जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। डबल इंजन आपका दम तोड़ चुका है। यह डबल इंजन कुछ कर्जों ने तोड़ दिया, कुछ ऑफिसरों ने तोड़ दिया। दिल्ली के तो अब 20 दिन रह गए। दिल्ली सरकार का तो दम टूट रहा है। ...(व्यवधान)... आप अपना इंजन सम्भालो। लोकायुक्त कहां गया? आपने कहा था लोकायुक्त करेंगे। क्यों आपने लोकायुक्त तैनात नहीं किया? क्या आज आप यह समझते हैं कि उसकी जरूरत नहीं है? आपने कोई रोड़मैप नहीं बनाया। रेवड़ियां बांट कर आप सोच रहे हैं कि आप पूरे प्रदेश को गुमराह कर लेंगे और डवैल्पमैंट की कोई बात नहीं करेंगे, विकास का कोई मॉडल नहीं देंगे। आपकी जो युनिवर्सिटीज़ बनी हैं, यह लिखा गया था कि 25 साल तक युनिवर्सिटियां नहीं बेचेंगे लेकिन अब उनके बिकने की बात आ गई है। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने पिछले साल कहा था कि चादर से बाहर पांव तब आते हैं, असूलों से बड़े जब ख्वाब हो जाते हैं। मैं रिवाइंड करना चाहता हूं इनको कि आपने कहा क्या था और आप कर क्या रहे हैं? पिछला जो आपका बजट था और इस बार जो बजट पेश किया है, इसको कहते हैं, आगे दौड़, पीछे चौड़। पिछला सब पीछे छूट गया और अगली प्लानिंग करनी शुरू कर दी कि हम यह कर देंगे। इस दस्तावेज में कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसको किसी स्तर पर सपोर्ट किया जा सके। मेरा मुख्य मंत्री जी से आग्रह है कि ये जो स्कीमें इन्होंने लाँच की हैं, अब इनके खाते में लगभग 50 के आसपास स्कीमें हो गई हैं। 30 पिछले साल की और 18 उसमें और जुड़ गई, 48 हो गई और जुड़ती जाएंगी तो इन

स्कीमों को जरा सम्भालो और अपनी ब्यूरोक्रेसी को ठीक कर लो ताकि आपका शासन चले। जो आप बोल रहे हैं, आपकी कथनी और करनी में इस समय बहुत ज्यादा अंतर हो गया है क्योंकि यह बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि आप लगातार घोषणाएं करते जा रहे हैं।

11.2.2019/1550/av/dc/1

आपने एक साल के दौरान जितने भी शिलान्यास या उद्घाटन किए; ये क्या आपने बनाये थे? ये तो कांग्रेस पार्टी की सरकार के शासनकाल के थे जो आप करते रहें। आपकी बारी तो अब शुरू होनी है। कांग्रेस पार्टी की सरकार अपने अंतिम वर्ष के शासनकाल में जो बनाकर गई थी उसमें तो आपने पत्थर लगा लिए। लेकिन कुछ ऐसा भी काम कीजिए जो कि आपने शुरू किया हो और आप उसको हिमाचल की जनता को परोस सकें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। लेकिन इस बजट ने हिमाचल को दिवालियापन की तरफ धकेल दिया है। वर्ष 2022 में जब तक इनकी सरकार का अंतिम समय आयेगा उस समय तक ये लोग जो प्रदेश की दुर्गति बनाकर जायेंगे उसको देखकर अभी से रौंगटे खड़े हो रहे हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी।

मुख्य मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय नेता प्रतिपक्ष को बहुत शांति और एकाग्रता से सुना और जिस दिन बजट पर रिप्लाई आयेगा उस दिन इस बारे में उत्तर भी दूंगा। लेकिन मुझे सचमुच में बहुत निराशा हुई है क्योंकि यहां पर बजट वर्ष 2019-20 का प्रस्तुत हुआ है और माननीय सदस्य का पूरा-का-पूरा भाषण वर्ष 2018-19 के बजट पर आधारित था। आप एक वर्ष पीछे चल रहे हैं। ...(व्यवधान)... नहीं, सुन लीजिए। मुझे अपनी थोड़ी सी बात कहने दीजिए। हमारा पीछले साल का जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसमें से बहुत सारी योजनाएं आ गई हैं जिनका असर इन पर भी हो रहा है और प्रदेश के लोगों पर भी हो रहा है। उसके प्रभाव में आकर के इन्होंने जिक्र किया कि जो पिछले बजट में बातें की गई थीं वे नहीं हुईं। आपकी जानकारी के लिए यह अंतिम बजट नहीं है, यह हमारी

सरकार का अभी सिर्फ दूसरा बजट है। इसके बाद जब बाकी वित्तीय वर्षों के बजट प्रस्तुत होंगे तब का दौर उस समय देखेंगे। अभी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यदि फैक्ट्स पर बात हो तो अच्छा लगता है। इसमें दो राय नहीं है क्योंकि कर्ज लेना आपकी भी विवशता थी और हमारे लिए तो आपने और भी ज्यादा विवशता बनाकर रखी है। लेकिन उसके बावजूद मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने आपसे ज्यादा कर्ज नहीं लिया है। हमने कर्ज को कम करने की कोशिश की है और उसमें हम सफल भी हुए हैं। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ सैक्शन्ज जिनके लिए हमने इस बजट में प्रावधान किए हैं। उसके लिए मैं निराशा का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वे समाज के इतने संवेदनशील क्षेत्र तथा वर्ग हैं कि उनमें से यदि आप एक का भी जिक्र करते तो मैं समझता कि आप इस बजट पर अपनी चर्चा को सार्थक कर रहे हैं। लेकिन अच्छी चीज पर तो आप बोलना ही नहीं चाहते। ...(व्यवधान)... मुकेश जी, जब आप बोल रहे थे तो मैं एक बार भी खड़ा नहीं हुआ। हमारे बजट में प्लानिंग का पार्ट भी आपको बिल्कुल स्पष्ट झलकता है। उसके साथ-साथ हमारे काम करने की मन्शा भी इसमें साफ झलकती है। इसलिए जो प्वाईंट्स आपने रेज़ किए हैं मैं उनके बारे में बाद में उत्तर दूंगा। लेकिन सचमुच में मुझे विपक्ष के नेता की तरफ से यह उम्मीद नहीं थी कि वर्ष 2019-20 के बजट की जगह आप वर्ष 2018-19 का जिक्र करते हुए अपनी चर्चा समाप्त करेंगे। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष : अब मैं माननीय सदस्य श्री सुख राम जी को बजट अनुमानों की चर्चा पर बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं। ...(व्यवधान)... मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि दोनों पक्षों को बराबर समय दिया जायेगा। लेकिन सभी अपना-अपना विषय 12 से 15 मिनट के बीच में रखने की कोशिश करें।

श्री सुख राम (पांवटा साहिब) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट वर्ष 2019-20 की वार्षिक योजनाओं का 7100 करोड़ रुपये का प्रस्तुत किया है मैं उसके ऊपर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हिमाचल प्रदेश के सीमित साधन है और सीमित साधनों के साथ-साथ जब हिमाचल के लोगों को विकास करना है तो कुछ-न-कुछ लोन लेना ही पड़ता है।

मैं इनके (विपक्ष) समय की बात कर रहा हूं। प्रदेश में जब दिसम्बर, 2007 से 31 दिसम्बर, 2012 तक जब आदरणीय धूमल जी की सरकार थी तो सरकार ने 7,621 करोड़ रुपये का कर्ज़ लिया था। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में आदरणीय वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में बहुत अनुभवी सरकार बनी और उस समय डेढ़ वर्ष तक केन्द्र में इनकी सरकार थी। उस वक्त हिमाचल प्रदेश सरकार ने 31 दिसम्बर, 2012 से 18 दिसम्बर, 2017 तक 18,787 करोड़ रुपये का कर्ज़ लिया। इसलिए यह कर्ज़ 25,798 करोड़ रुपये से बढ़कर 46,385 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

(माननीय सभापति कर्नल इन्द्र सिंह पदासीन हुए)

आदरणीय जय राम ठाकुर जी ने जो बजट इस बार पेश किया है, यह हिमाचल प्रदेश का ऐतिहासिक बजट है। इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। यह गरीबों का बजट है। मैं कहना चाहता हूं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, 'आयुष्मान भारत योजना' शुरू की है और इसके तहत 50 करोड़ लोगों का 5 लाख रुपये तक का बीमा किया जाएगा। जिसका यह कार्ड बनाया जाएगा, जब वह हॉस्पिटल में एडमिट होगा, उसके इलाज पर जो खर्चा होगा, उसका 5 लाख रुपये तक का खर्चा उस स्कीम के माध्यम से केन्द्र सरकार वहन करेगी। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो लोग इस स्कीम से छूट गए थे, जो इस योजना के अंतर्गत कवर नहीं हुए थे, उनके लिए 'हिम केयर' योजना हिमाचल प्रदेश में चलाई है और उसमें हिमाचल प्रदेश के जो गरीब लोग हैं, विधवा महिलाएं हैं जिनको पेंशन मिलती है, जो व्यक्ति मनरेगा में काम करता है, वह गरीब व्यक्ति होता है। जो 50 दिन तक मनरेगा में काम करेगा, उसको हिम केयर स्कीम के तहत कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा।

हिमाचल प्रदेश सरकार उसका फ्री में कार्ड बनाएगी। इसी प्रकार का कार्ड आउटसोर्स कर्मचारी एक रुपया एक दिन का देकर बना सकते हैं और हिमाचल प्रदेश का आम आदमी 1000/- रुपये देकर यह कार्ड बना सकता है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 125 हॉस्पिटल्ज ऐसे हैं जिनमें दाखिल होने पर उनको फ्री में ट्रीटमेंट दी जाएगी और 1200 अस्पताल 'आयुष्मान योजना' के अंतर्गत कवर्ड हैं। क्योंकि जब कोई गरीब व्यक्ति बीमार होता है, उसके पास इलाज़ करने का कोई साधन नहीं होता है और उसको इलाज़ करवाना मुश्किल हो जाता है। मैं आदरणीय विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूं कि आप 50 साल में एक नीति बताएं, जो गरीब के स्वास्थ्य के लिए आपने शुरू की हों। ये ऐसी स्कीमें हैं जिनका आम आदमी को फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण स्वच्छता अभियान में 10 करोड़ परिवारों में शौचालय बनाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 12000/- रुपये प्रति शौचालय दिए हैं। मैं आदरणीय जय राम ठाकुर जी का इस सदन में धन्यवाद करना चाहता हूं कि 20,000/- रुपये 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के तहत जो घर स्वीकृत होंगे, उनके लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार अतिरिक्त धनराशि के रूप में देगी। इस प्रकार से यह 1.50 लाख रुपये की राशि है जो हर गरीब व्यक्ति को घर बनाने के लिए दी जाएगी। मकान की रिपेयर के लिए जो पैसा आएगा, उसमें भी 10,000/-रुपये अतिरिक्त शामिल करके 35,000/- रुपया दिया जाएगा। ये हिमाचल प्रदेश के गरीबों की बहुत चिन्ता करते हैं। मैं बताना चाहता हूं, जब इनकी (विपक्ष) सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी, मजदूर की दिहाड़ी 170/- रुपये थी और

11-02-2019/1600/NS/HK /1

इन्होंने पांच साल में दिहाड़ी 170 रुपये से 210 रुपये की। यानी केवल 40 रुपये बढ़ाई। आज सरकारी सैक्टर में डेली वेज़र कम हैं और प्राईवेट सैक्टर में ज्यादा हैं। हिमाचल प्रदेश में बहुत-सी प्राईवेट फैक्टरियां हैं और जब कोई व्यक्ति इनमें काम करता है तो उसको वही मिनीमम वेज़िज हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं। विपक्ष ने अपने पांच सालों के

कार्यकाल में केवल पांच रुपये की बढ़ौतरी की। जब प्रदेश में आदरणीय धूमल जी की सरकार थी तो 75 रुपये से दिहाड़ी 170 रुपये की गई थी और हमने इसमें 95 रुपये की बढौतरी की थी। आदरणीय जय राम ठाकुर जी की सरकार ने डेढ़ वर्ष में यह दिहाड़ी 210 रुपये से 250 रुपये कर दी। जितनी इन्होंने (विपक्ष) पांच साल में बढ़ाई, हमारी सरकार ने डेढ़ साल में बढ़ाई। हिमाचल प्रदेश में लाखों मज़दूर प्राईवेट सैक्टर में काम करते हैं, इंडस्ट्रीज में काम करते हैं और जब उनको ये बढ़ा हुआ वेतन 250 रुपये के हिसाब से मिलेगा यानी 40 रुपये बढ़ा हुआ मिलेगा तो हिमाचल प्रदेश में उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बढ़ी हुई राशि तो उद्योगपतियों ने देनी होती है और 90 प्रतिशत लोग प्राईवेट सैक्टर में काम करते हैं और उनको ये दिहाड़ी मिलती है। क्योंकि 40 रुपये पांच सालों में बढ़ाना, मुझे कई बार इनके (विपक्ष) ऊपर शक होता है, हमारे विपक्ष के नेता उस समय उद्योग मंत्री थे और कहीं उद्योगपतियों के साथ इनका कोई समझौता तो नहीं हुआ था कि मज़दूरों की दिहाड़ी बढ़ानी ही नहीं है। क्योंकि उनको हिमाचल प्रदेश के लोगों को बढ़ी हुई मज़दूरी देनी पड़ेगी और उनकी जेब में अधिक पैसा जाएगा। ये (विपक्ष) पांच साल में 40 रुपये दिहाड़ी बढ़ाते हैं और इस सदन में बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि जैसे इन्होंने हिमाचल प्रदेश को कहां-से-कहां पहुंचा दिया। आज"हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना" माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत महत्वकांक्षी योजना है। इस योजना के अंतर्गत 49,000 हिमाचली गृहणियों को गैस के कनैक्शन दिए गए हैं और यह गैस कनैक्शन 3500 रुपये का पड़ता है। हमने लगभग 1.33 लाख गैस कनैक्शन देने हैं। "प्रधानमंत्री उज्जवला योजना" के अंतर्गत लगभग 86,000 लोगों को हिमाचल प्रदेश में कनैक्शन दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इससे बढ़कर आगे काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि "प्रधानमंत्री उज्जवला योजना" में जो गैस के सिलेंडर मिलेंगे, उसमें गैस का सिलेंडर और चूल्हा व पाईप हिमाचल प्रदेश सरकार मुफ्त में देगी।

"हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना" में हिमाचल प्रदेश में कनैक्शन स्वीकृत किए गए हैं, उनके गैस सिलेंडर की रिफिलिंग भी फ्री में हिमाचल प्रदेश सरकार करेगी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है।

इसके अतिरिक्त "सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना" में गरीब व्यक्ति को पैंशन मिलती है, वह पिछली बार 650 रुपये से बढ़ा कर 750 रुपये की गई थी और इस बार 750

रुपये से 850 रुपये कर दी गई है। एक साल में 200 रुपये बढ़ा दिए हैं। हमने पैंशन के लिए 80 साल से 70 साल उम्र की , उनकी सामाजिक सुरक्षा पैंशन 1300 से 1500 रुपये कर दी गई है। इससे गरीब व्यक्ति को फायदा होगा।

"मुख्यमंत्री रोशनी योजना" एक गरीब व्यक्ति जो आई0आर0डी0पी0 से संबध रखता है और जो कनैक्शन नहीं ले सकता है और उसको लगभग 2500 से 3000 रुपये कनैक्शन के ऊपर खर्च करना पड़ता है तथा जब वह अपनी आय का सर्टिफिकेट देगा तो उसको सर्विस टैक्स और मीटर का खर्च नहीं देना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश की सरकार उसको फ्री में कनैक्शन देगी। हिमाचल प्रदेश की सरकार यानी माननीय जय राम ठाकुर की सरकार किसानों को समर्पित सरकार है। "मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना" में सोलर फैंसिंग के अतिरिक्त कांटेदार तार और चेन जिंक तार लगाने के लिए 50 प्रतिशत उपदान प्रदेश की सरकार हिमाचल प्रदेश के किसानों को देगी। मैं एक बात कहना चाहता हूं हि जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, यह किसानों की कितनी हितैषी सरकार रही है? हिमाचल प्रदेश के निचले क्षेत्र जैसे पांवटा साहिब, ऊना, कांगड़ा और नालागढ़ का क्षेत्र है, जब हमारे इन क्षेत्रों में किसान टयूबवैल लगाते हैं तो हमारे यहां पानी भी गहरा निकलता है और यह 150 से 200 फुट में निकलता है। पंजाब में बिजली फ्री थी, हरियाणा में 100 रुपये में 5 एच0पी0 150 रुपये में 7 एच0 पी0 और 200 रुपये में 10 एच0पी0 महीने का खर्च आता था।

11.02.2019/1605/RKS/HK-1

किसानों की इस हितैषी सरकार ने अपने समय में किसानों के ट्यूबवैल्स की बिजली 50 पैसे से बढ़ाकर 1 रुपया प्रति यूनिट कर दी थी। मैं आदरणीय जय राम ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने पिछले बजट में ट्यूबवैल्स की बिजली 1 रुपये से घटाकर 75 पैसे प्रति यूनिट की और इस बजट में 75 पैसे से घटाकर 50 पैसे प्रति यूनिट कर दी है। इस सस्ती बिजली के कारण यदि किसी व्यक्ति के ट्यूबवैल का बिल एक महीने में एक हजार रुपये आता है तो यह बारह महीनों में बारह हजार रुपये बनता है। प्रदेश सरकार ने इस पर 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की है जिससे किसान को एक साल में 6000 रुपये बिजली की बचत से बचता है। ...(व्यवधान)... 50 पैसे प्रति यूनिट बिजली

कर दी गई क्या इससे किसान का भला नहीं हुआ? किसान का मुद्दा बहुत संवेदनशील मुद्दा है। किसान को किस तरह लाभ दिया जाए जिससे उसकी आमदनी बढ़े और इसके लिए हमारी सरकार ने बड़ी गंभीरता के साथ काम किया है। जो किसान दूध बेचते हैं, उन किसानों के दूध की कीमत दो रुपये प्रति लीटर बढ़ाई गई है। देशी नस्ल की गाय की खरीद हेतु अधिकतम 25,000 रुपये सब्सिडी का प्रावधान है। जो आई.आर.डी.पी. परिवार वाले भेड़-बकरियां खरीदना चाहते हैं उन्हें 85 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जा रही है। आम व्यक्ति को 60 प्रतिशत सब्सिडी प्रदेश सरकार प्रदान कर रही है। 'मुख्य मंत्री खुंब विकास योजना' जोकि 1688 करोड़ रुपये की योजना है, इस योजना से प्रदेश के लोगों को काफी लाभ होगा। जिन किसानों की जमीन 24-25 बीघा से कम हैं उनके खाते में केंद्र सरकार द्वार 6000 रुपये जमा किया जाएगा। यह एक महत्वकांक्षी योजना है और हमारे मित्र कहते हैं कि यह बहुत कम राशि है। इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के 90 प्रतिशत किसान कवर होंगे। अगली बार माननीय नरेन्द्र मोदी जी दोबारा प्रधान मंत्री बनेंगे और यह राशि और भी बढ़ा दी जाएगी। इसलिए आप इस चीज की चिंता मत कीजिए। आप बताओ कि आपने 50 वर्षों में किसान को क्या दिया? आपने आज तक किसानों को कोई उपदान नहीं दिया। ट्रैक्टर और अन्य उपकरणों पर प्रदेश सरकार 50 प्रतिशत सब्सिडी दे रही है। कृषि तभी अच्छी हो सकती है जब हमारे किसानों को सिंचाई की सुविधा मिले। जब किसान के खेतों को पानी मिलेगा, अच्छा बीज मिलेगा, अच्छे औजार मिलेंगे, ट्रैक्टर पर सब्सिडी मिलेगी, बिजली सस्ती मिलेगी, सस्ते बीज मिलेंगे, अच्छा पशुधन मिलेगा, तब जाकर किसान की आमदन बढ़ सकती है और इसके लिए बहुत-सी योजनाएं प्रदेश सरकार किसानों के लिए ला रही है। 4, 070 करोड़ रुपये की नई योजना सिंचाई के क्षेत्र में लाई जा रही है। बाढ़ संयंत्र में भी लगभग 3 हजार करोड़ रुपये की कुछ योजनाएं हैं। माइक्रो इरिगेशन की बहुत-सी स्कीमें हैं जिनमें 80 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की जाती है। जब हम पाइपें खरीदते हैं या स्प्रिंकल सिस्टम अपने खेत में लगाते हैं, उसमें यह सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस तरह यह छोटे-छोटे फायदे किसान को मिलते हैं। एक किसान

एक समय में एक ही ट्रैक्टर खरीदता है। यदि 6 लाख के ट्रैक्टर में उसे 3 लाख रुपये की सब्सिडी मिल जाए तो यह किसान के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। औजार लेने के लिए यदि उसे 50 प्रतिशत उपदान मिल जाए तो इससे प्रदेश के किसानों की आय में काफी बचत होती है। कर्मचारियों और बेरोजगारों के बारे में भी यहां पर बहुत-सी बातें कही गई। इन्होंने पांच साल में 40 रुपये बढ़ाकर बेरोजगारों पर बहुत बड़ा परोपकार किया है। जहां तक पद भरने की बात है, जाते-जाते पता नहीं आप कितने स्कूल खोल गए? जहां प्राइमरी स्कूल की मांग थी, वहां मिडिल स्कूल दे दिया गया, जहां मिडिल स्कूल की मांग थी, वहां प्लस टू स्कूल दे दिया गया । भले ही स्कूल में बिल्डिंग और साधनों को अभाव क्यों न हो।

11.02.2019/1610/बी0एस0/वाई0के0-1

डैप्यूटेशन में दूसरे स्कूलों से अध्यापक लगा दिए गए, न उस स्कूलों में पढ़ाई अच्छी हुई और न ही जहां से उन्हें बुलाया गया वहां पढ़ाई अच्छी हुई। मैं मुख्य मंत्री आदरणीय जय राम ठाकुर जी को बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद करना भी चाहता हूं । साथ ही मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस पिछले वर्ष में हजारों पद भर कर स्कूलों में जो खाली पद थे उन्हें भरने का प्रसास किया है। पूर्व सरकार हिमाचल प्रदेश के लोगों के प्रति कितनी संवेदनशील है कि जो व्यक्ति अपनी नौकरी में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता था तो आपकी सरकार ने यह नियम बनाया था कि जो 50 वर्ष की आयु से पहले जिसकी मृत्यु हो जाती थी उसे तो करूणामूलक आधार पर नौकरी मिल जाती थी परंतु जो इसके बाद मृत्यु को प्राप्त होता था उसे कोई नौकरी नहीं दी जाती थी। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस वर्ष इन्होंने कहा कि आयु सीमा की कोई भी शर्त नहीं लगाई जाएगी। जो पूर्व सरकार ने 50 वर्ष रखी थी उसे खत्म कर दिया गया है। हमारी सरकार ने कहा कि किसी भी कर्मचारी की चाहे 58 वर्ष में मृत्यु हो या 60 वर्ष के अतंराल में किसी कर्मचारी की मृत्यु हो उन्हें करूणामूलक आधार पर नौकरी प्रदान की जाएगी। 20 हजार लोगों को इस आधार पर लोगों को नौकरियां प्रदान की

जाएगी। इसमें जो आय की शर्त लगा रखी है उसमें भी हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हम उसमें छूट देंगे, यह कोई छोटी योजना नहीं है। आप और हम जब अपने क्षेत्रों में जाते हैं, जिन लोगों की 5-7-8 वर्ष पहले नौकरी पर ही मृत्यु हो चुकी है उनके परिवार वाले हमारे सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरे पिता जी का देहांत हो गया था मुझे नौकरी चाहिए। जब वे आवेदन करते हैं तो यहां से ऑब्जैक्शन लग जाता है कि इसकी आयु तो 50 वर्ष से अधिक हो गई है इसलिए इसका केस रिजैक्ट किया जाता है या इसकी तो इनकम ज्यादा है इसलिए केस रिजैक्ट किया जाता है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने ऐसे लोगों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। इस आधार पर किसी भी विभाग में खाली पद होंगे, चाहे वह आई.पी.एच. में हो , चाहे लोक निमार्ण विभाग में हो, चाहे वन विभाग में हो, चाहे बिजली बोर्ड में हो । जब वे लोग आएंगे तो 20 हजार पद भरे जाएंगे। हमारी सरकार ने कहा कि कैबिनेट की आने वाली बैठकों में इन पदों को भरने की प्रक्रिया प्रदान की जाएगी। यह बहुत बड़ा तोहफा हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री ने हिमाचल प्रदेश की गरीब जनता को दिया है । यह बहुत बड़ी राहत प्रदेश को लोगों को माननीय मुख्य मंत्री जी ने दी है । सरकारी सैक्टर में आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने 2.50 लाख रुपये से 5 लाख रुपये इंकम का जो क्राइटिरिया बढ़ाया है इससे आम कर्मचारी खुश है। यह बहुत बड़ी राहत आम कर्मचारी को दी है, हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने दी है। हम 20 हजार पद करूणामूलक आधार पर भरेंगे। 8 हजार पद जो शिक्षकों के रिक्त पड़े हैं उन्हें सरकार भरेगी, 300 डाक्टर्ज के पदों को भरा जाएगा, 3 हजार पैरा मैडिकल स्टाफ भरा जाएगा, 1 हजार कनिष्ठ सहायक भरे जाएंगे, 1400 कॉस्टेबल, 300 फोरेस्ट गार्ड, 200 कनिष्ठ अभियंता, 50 सहायक अभियंता, आई.पी.एच. में भी बहुत सारे पदों को भरा जाएगा। इसी तरह से शिक्षा विभाग में जो पार्ट टाइम पदों से कर्मचारी सेवादर बन जाते थे आपने उन पदों को खत्म कर दिया था परंतु माननीय जय राम ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने कहा है कि 1 हजार पदों को बहाल करेंगे। इस वर्ष हम स्कूलों में 1 हजार पदों की भर्ती करेंगे। हमारी सरकार ने प्रदेश के आम जन को राहत देने का कार्य किया है।

इसी तरह परिवहन निगम में 800 पद भरे जाएंगे, बिजली बोर्ड में 1000 पदों को भरा जाएगा। अभी तो हमारी सरकार का 1 वर्ष का कार्य काल ही पूरा हुआ है, आप आगे देखते जाएइए आगे-आगे क्या होता है। इस सरकार का कार्यकाल अभी 5 वर्ष का है। जहां तक कर्मचारियों की बात है जिन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की 20 वर्ष की सेवा पूर्ण हो चुकी है जिनका पे स्केल 5910-20200 रुपये है और पदोन्नति नहीं मिली है। वह 20 वर्षों से एक ही पद पर कार्य कर रहे हैं। आदरणीय जय राम ठाकुर जी की सरकार उन्हें एक अतिरिक्त इंक्रीमैंट प्रदान करेगी। यह उन व्यक्तियों के लिए बहुत बड़ी राहत है । वाटर गार्ड का वेतन भी हमारी सरकार ने 3000 रुपये कर दिया, पंप आप्ररेटर का 4000 रुपये वेतन कर दिया गया है।

11.02.2019/1615/DT/YK/-1

मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना 35 वर्ष से बढ़ाकर आयु 45 वर्ष की है और 40 लाख से इनकम बढ़ाकर 60 लाख की है। विधायक प्राथमिकता में जब नाबार्ड में हमारी स्कीमें जाती थी, कई विधायक कहते थे 90 करोड़ की सीमा खत्म हो गई यह बढकर 105 करोड़ कर दी गई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर जी ने आपकी विधायक निधि का पैसा 1करोड़ 25 लाख से बढ़ाकर 1करोड़ 50 लाख कर दिया है और माननीय विधायकों की विवेक अनुदान राशि को 7लाख से बढ़ाकर 8 लाख रूपये कर दिया है अगर आप महिला मण्डलों को पैसा देना चाहते हैं तो 25,000 हजार आप दे सकते हैं। जो बजट हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी पेश किया है यह आम व्यक्ति का बजट है। पंचायती राज में जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं उनका सभी का मानदेय बढ़ा दिया गया है चाहे वह पंचायतों के ,चाहे नगर परिषद के हैं, नगर निगम के हैं ,आशा वर्कर्ज है ,पंचायत चौकीदार है, पटवारी/ चौकीदार हैं, हमने उन सभी का मानदेय बढ़ाया है ।

यहां पर यह जनमंच की बहुत चर्चा करते हैं। 106 जनमंच हुए 33966 समस्याओं को मौके पर ही समाधान किया गया आज इनको हिमाचल प्रदेश के बजट के खर्चे की बड़ी चिन्ता होती है । क्योकि जिस दिन जनमंच होता है इनको पता है कोई न कोई कांग्रेसी

जरूर आएगा और वह कहीं भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आ गया तो इस डर के मारे यह विरोध करते हैं क्योंकि बहुत से कांग्रेस के मित्र भी जनमंच में काम करवाने आते है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तो कहा कि एक जनमंच जिला स्तर में होगा जिसकी अधयक्षता वह स्वयं करेगे और यह 10 प्रतिशत जो अन्य पिछडे वर्ग के जो लोग है जिनको आरक्षण केन्द्र सरकार ने दिया है यह मैं सोचता हूं कि समाज में समानता लाने का बहुत बड़ा कदम हमारे देश में आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने किया है गरीबी किसी के घर में जात देख के नहीं आती ब्राहमण भी गरीब हो सकता है राजपुत भी गरीब हो सकता है, मुस्लिम समाज के लोग आज सबसे गरीब है।आपने तो कुछ किया नही है उनके लिए आज 10 प्रतिशत आरक्षण जो केन्द्र सरकार ने दिया है हमारी सरकार भी हिमाचल प्रदेश में इसको लागू कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट लेकर आपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं मैं किसी आरक्षण के विरोध में नही हुं। परन्तु जब एक व्यक्ति गरीब ब्राहणा समाज के घर में पैदा हो जाता है और उसके साथ एक दुसरे समाज का लोग होता है जिसको अरक्षण की बजह से बेनफिट मिलता है उसकी 5 मंजिला कोठी होती है उसके बच्चे भी अच्छी-अच्छी नौकरी में लग जाते है और वह वयक्ति गरीब होता है। आर्थिक साधान कमजोर होते है, अच्छी पढ़ाई वह कर नहीं सकता इस समाज में वह कंपिटिशन की भावना नहीं कर सकता। उसको सहारे की जरूत होती है आर्थिक आधार पर आरक्षण की जरूत होती है। यह बहुत बड़ा इतिहासिक कदम हमारे देश के आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने लिया है और इसका बहुत बड़ा फायदा आम व्यकित को मिलने वाला है। इस लिए हमारे मित्र इससे बहुत परेशान है। आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने भारत वर्ष में समानता लाने का बहुत बड़ा काम किया है। यह चहुंमुखी विकास का बजट है, आम व्यक्ति का बजट है, किसान का बजट है, मजदूर का बजट है, कर्मचारियों का बजट है, महिलाओं को बजट है, आम व्यक्ति को इसमें राहत मिली है। इस बजट से हमारे विपक्ष के जो मित्र है बहुत चिन्तित है क्योंकि लोक सभा के चुनावो में यह बजट इनको बहुत सताएगा यह चिन्ता इनको लगी है। मैं इस बजट का जो

आदरणीय जय राम ठाकुर जी ने 9 फरवरी 2019 को पेश किया भरपूर समर्थन करता हूं। जय हिन्द, जय भारत ।

उपाध्यक्षः अब माननीय सदस्य श्री राम लाल ठाकुर जी ।

श्री राम लाल ठाकुर (श्री नैना देवीजी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय,जो इस माननीय सदन में 9 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट अनुमान इस माननीय सदन में प्रस्तुत किए मैं भी उस चर्चा मैं अपने आपको सम्मिलित करता हूं। विस्तार से माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी ने हर बिन्दु के ऊपर अपने विचार रखे हैं मैं उनके ऊपरर आपका ज्यादा समय नहीं लूगा।

11-02-2019/1620/ए.जी./एन.जी./1

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप देखेंगे कि जो केन्द्र सरकार ने बजट दिया, पार्लयमैन्ट के चुनाव दहलीज पर हैं, तो उन्होनें भी लुभावना बजट देश की संसद में पेश किया है । जिसमें किसानों के लिए 6000 हजार रूपये प्रति वर्ष देने की बात कही है। ऐसे बहुत सारे वायदे केन्द्र सरकार के बजट में किए गए हैं । मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश का यह बजट भी चुनावी बजट है । क्यों कि simultaneously हमारे केन्द्र सरकार के बज्ट के साथ ही पार्लयमैन्ट के चुनाव को देखते हुए जल्दी से इस बजट को यहां पर प्रस्तुत करना पडा । मैं यह कहना चाहूंगा कि This budget is a copy paste of the Central Government budget. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि जो वायदे उसमें किए गए और बिना संसाधनों के सारे कार्य करने में हिमाचल प्रदेश की सरकार सक्षम नहीं है । मैं कहूंगा की तुफान से भरे हुए समुद्र से हिमाचल प्रदेश की किश्ती को बाहर कैसे निकालेंगे । हिमाचल प्रदेश के लोग और जो हिमाचल के लोग प्रदेश से बाहर भी रह रहे हैं वह इस सब पर चर्चा कर रहे हैं कि जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह ठीक है और सबको खुश करने के लिए किया लेकिन देखना यह चाहिए कि जो आपने पिछली बार 30 बिन्दुओं के उपर ज्यादा जोर दिया था और इस बार 18 नए बिन्दु ओर नए

जुडे हैं । आप क्या करने वाले हैं, कहीं पर आपने बोर्ड बनाने का गठन किया, कहीं पर युवाओं के लिए नया कार्यक्रम चलाने के लिए वायदा कर दिया । मैं यह कहना चाहूंगा कि यह सारा करना बहुत मुश्किल है । अगर हम कृषि की बात करें, बागवानी की बात करें क्यों कि हिमाचल प्रदेश जितनी भी जन संख्या है उसमें से more than 80 per cent or 90 per cent के बीच में कृषक लोग हैं जो खेतीबाडी का काम करते हैं, चाहे वो हमारे ट्रेडिशनल खेती हो, या आज की तारीख में किसान बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन कर रहा हो, या फल उत्पादन कर रहा है । उपाध्यक्ष महोदय, बजट में की हुई टिप्पणीयों को आप देखें तो पिछले साल की तुलना में कृषि क्षेत्र में भी हम माईनस में गए हैं, और बागवानी में भी हम पिछले साल की तुलना में माईनस में गए है । आने वाले वर्ष के लिए किसानो को लुभाने के लिए जो वायदे किए गए हैं, मैं कहूंगा की यह एक ऐसा स्वप्न है जो स्वप्न हिमाचल प्रदेश की सरकार दे रही है, कि आने वाला समय जो है वह कृषकों के लिए होगा और इसमें साहरा किसका लिया जा रहा है, जो केन्द्र सरकार ने घोषनाऐं की है उनका साहरा लिया जा रहा है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि जो भारत वर्ष की सरकार ने दिल्ली में किया उनके तो अभी 2-3 महीने ही रह गए हैं और खुलासा हो जाएगा । जिस प्रकार से भारत वर्ष के अन्दर साढे चार-पौने पांच सालों के अन्दर हुआ है उससे केन्द्र में बैठे हुकुमरानो की नींद उडी हुई है । चाहे वो नोटबन्दी का ईशू हो, चाहे वो जीएसटी का ईशू हो, चाहे वो नौजवानों को रोजगार देने का ईशू हो । उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश के माननीस मुख्यमन्त्री जी भी उसी लाईन के उपर चले हुए हैं । हिमाचल प्रदेश के नौजवनों को रोजगार देने के लिए 20 हजार नई नौकरियां देने का वायदा बजट के अन्दर किया गया है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से भी हैरानी में हूं, हमारे साथी जो बोलते हैं तो यह नहीं सोचते की हम किस बिन्दु पर और किस ढंग से बोल रहे हैं । यह जो 20 हजार नौकरियां देने का प्रश्न है, सेवा में जिनका निधन हो गया उनके बच्चों को करूणामूलक आधार पर 20 हजार नौकरियां नहीं मिलेंगी । ये 20 हजार नौकरियां सभी विभागों में, हैल्थ विभाग में, आईपीएच में,

11/02/2019/1625/RG/AG/1

बिजली बोर्ड, पुलिस विभाग इत्यादि में ये नौकरियां सबको मिलेंगी। लेकिन ये जो करूणामूलक आधार पर नौकरियां देने की बात कर रहे हैं, इस बारे में मुझसे पहले वक्ता ने हिमाचल प्रदेश में बीस हजार नौकरियां करूणामूलक आधार पर देने की बात कही।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जब ये हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री थे तो उस समय, उस तरफ के लोगों ने अपने आदमी कोर्ट में इसलिए भेजे कि ये मुख्य मंत्री जी जो करूणामूलक आधार पर नौकरियां दे रहे हैं, ये नहीं मिलनी चाहिए। यह मसला सुप्रीम कोर्ट तक गया। जहां कोर्ट ने कहा कि कानूनी तौर पर करूणामूलक आधार पर नौकरियां नहीं मिलनी चाहिए और यह कानूनी तौर पर कहा गया था। लेकिन मैं माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी का पुनः धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इसके लिए एक और दरवाजा निकाला और यह कहा कि जिस गरीब परिवार के मुखिया का नौकरी में रहते हुए निधन हो गया, उसके सदस्य को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। इसलिए मैं कहूंगा कि माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी के कारण यह दुबारा से शुरू हुआ था। आज यह कहा जा रहा है कि 58 साल तक की आयु में जिसका निधन हो जाए उसके परिवार के सदस्य को नौकरी मिलेगी। मैं यह नहीं कहूंगा कि सरकार ने यह गलत किया। लेकिन जो पिछली सरकार ने किया था, वह भी रिकॉर्ड में रहना चाहिए कि कोर्ट ने इसके लिए मनाही कर दी थी परन्तु उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी की सरकार और माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी ने गरीबों के लिए यह फैसला किया। इसलिए किसी चीज को कहने से पूर्व हम लोगों को उसके गुण और दोष के बारे में मन्थन करना चाहिए और उसके पश्चात ही आगे बात करनी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष जी, पॉली हॉऊसिज के लिए जमीन के बारे में कहा कि इतनी जमीन और आएगी और पिछले साल जो जमीन का वायदा किया गया था, उससे मल्टीप्लाई होगी। सालभर जो वायदे हुए थे, उनका क्या? उप निदेशक, कृषि विभाग के कार्यालय में जाओ, पूछो कि कौन सा पैसा कौन सी स्कीम में आया है या कहीं किसान को

जो पैसा मिलना है, वह आया या नहीं? तो वे कहते हैं कि पहली तिमाही का पैसा भी अभी तक नहीं आया। अगले चार महीने और निकल गए। अगर मान लो सिंचाई की स्कीम भी बनानी है तो उसके बाद भी अधिकारी कहते हैं कि उसके लिए भी अभी पैसा जिला मुख्यालय में नहीं पहुंचा है। अगर औजार खरीदने हैं तो उसका पैसा भी जिला मुख्यालय में अन्तिम तिमाह तक मैं कह सकता हूं कि अगर मेरे बिलासपुर जिले में यदि अधिकारियों को पूछा तो कहते हैं कि अभी तक बजट हमारे यहां नहीं पहुंचा है। तो सरकार यह कैसे कह रही है कि सालभर में हमने वह कर दिया, जो शायद आपने सपने में भी नहीं सोचा था।

माननीय उपाध्यक्ष जी, यही हमारे यहां हॉर्टिकल्चर में हुआ। आज जो पॉली हॉऊसिज लगाने की बात कर रहे हैं, सरकार किसानों को 85 प्रतिशत उपदान सहायता देने की बात कर रही है। मैं इस वेदना को भी आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के चार हजार से ज्यादा किसान वे हैं जिन्होंने पॉली हॉऊस लगाए थे और वे तब लगाए थे जब केन्द्र सरकार से इस पर केवल मात्र 15 प्रतिशत का अनुदान मिलना था। बाकी लोगों ने बैंकों से कर्ज लिया। उसके बाद केन्द्र सरकार ने फिर पॉलिसी बदली। फिर वह 50-60 प्रतिशत पर आई और बाद में किसानों को इसके ऊपर 80 प्रतिशत अनुदान दिया गया। हमने यह मसला माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी के सामने भी उठाया था और मौजूदा सरकार के सामने भी हमने यह मसला उठाया। विभाग के सैक्रेट्री, श्री शर्मा जी थे, उनके पास इसकी एक फाईल बनी थी जिसमें माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी ने कहा था कि इनका कुछ-न-कुछ करना है। लेकिन किसानों की जमीनों की कुर्कियां हो गईं, किसान पुरानी जमीन से भी हाथ धो रहे हैं और सरकार आगे भी पॉली हॉऊस लगाने की बात कर रही है। लेकिन जो चार या साढ़े चार हजार के आस-पास किसान हैं जिनकी कुर्कियां हो रही हैं, जिनको आज बैंक नोटिस दे रहा है और आज वे अपनी जमीन से भी हाथ धो बैठे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि इस सरकार ने उनके बारे में क्या सोचा है? क्योंकि इन्होंने तो केन्द्र सरकार की स्कीम को कट एण्ड पेस्ट कर दिया कि हिमाचल प्रदेश के किसानों को हम इस पर 85 प्रतिशत उपदान देने वाले हैं। लेकिन आज हमें उन किसानों के बारे में भी सोचना होगा जिनकी पुश्तैनी जमीन पर आज बैंक कब्जा लेने की बात कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, इसी प्रकार से ये जी.डी.पी. की बात कर रहे हैं,

क्या कारण है कि जी0डी0पी0 ज्यादा हो रही है लेकिन कृषक/बगवान की इन्कम कम हो रही है? पर्यटन की दृष्टि से "इंडिया टूडे" के सर्वे के मुताबिक हिमाचल दूसरे पायदान पर था लेकिन अब हम 20वें पायदान पर आ गए हैं। मैं तो कहूंगा कि ये आंकड़े भी प्रश्नवाचक चिह्न पैदा करते हैं कि आप जी0डी0पी0 तो ज्यादा बता रहे हैं लेकिन 80 परसेंट हिमाचल प्रदेश के किसानों/बागवानों की आय आपके ही आंकड़ों के मुताबिक कम हुई है। इसलिए मेरा यह कहना है कि इससे बहुत किस्म की भ्रांतियां पैदा होती हैं।

उपाध्यक्ष जी, मैं बिलासपुर जिला से संबंधित दो-तीन बातें कहना चाहूंगा। मैं शिक्षा विभाग के बारे में भी कहना चाहता हूं। माननीय पूर्व मुख्य मंत्री वीरभद्र सिंह जी को भी याद होगा कि ये जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जब नये स्कूल/कॉलेज की क्रिएशन होती है और कैबिनेट में मसला जाता है कि कितने पद सैंक्शन होने हैं तो उसमें शारीरिक शिक्षकों के पद ही क्रिएट नहीं होते हैं क्योंकि सेक्रेटरी के वहां से इस प्रकार का मसौदा आता है कि पी0ई0टी0 और डी0पी0 के पद जरुरी नहीं हैं लेकिन यहां मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि नौजवानों को नशे से छुड़वाने के लिए आज इन अध्यापकों की आवश्यकता है।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पी0टी0ए0 के तहत लगे टीचर्स को आज रेगुलर करने की बात हो रही है लेकिन उपाध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड पर लाना चाहूंगा कि 1500 ऐसे पी0ई0टी0 और डी0पी0 थे जो स्कूल मैनेजमैंट कमेटीज ने लगाए थे, जिनको सरकार ने आते ही बाहर निकाल दिया। जब उनको बाहर निकाला तो वे कोर्ट में चले गए। आज उन 1500 टीचर्स ने स्टे ऑर्डर ले रखा है और उसके बाद वे नौकरी पर हैं। मैं मौजूदा सरकार से कहना चाहूंगा कि जिन्होंने स्टे ऑर्डर लिया है और जिनकी सर्विस पूरी हो गई है, उसमें आप केवल एक पहलू को देख रहे हैं और आज कह रहे हैं कि पी0टी0ए0 वालों को हमने नियमित करना है लेकिन जो 1500 डी0पी0 और पी0ई0टीज0 हैं, जो कोर्ट के स्टे के बाद स्कूलों में नौकरी कर रहे हैं, उनका क्या होगा?

यहां खेल विभाग की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। मैं आज यह कहना चाहूंगा कि 50 कोचिज के पद माननीय वीरभद्र सिंह जी के समय में सैंक्शन हुए थे। क्या

कारण है कि कुछ हमारे ब्यूरोक्रेट्स उसके ऊपर बैठ जाते हैं या एसोसिएशन के प्रधान ऐसा करते हैं? फिर क्या होता है कि जो ज्यादा महत्वपूर्ण खेल हैं, जिस खेल में नेशनल लैवल पर मैडल आ रहे हैं, उनके कोचिज नहीं लग रहे हैं। हमारी स्टेट की गेम वॉलीवॉल है और इस खेल के भी कोचिज नहीं हैं। ...(घण्टी)... आज अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में कबड्डी और दूसरी जो हमारी परिणाम देने वाली गेम्ज हैं उनके कोचिज नहीं हैं और आपकी सरकार युवा नीति की बात कर रही है? खेल मंत्री जी सदन में नहीं बैठे हैं। जब मैंने इस बारे में चर्चा मांगी थी कि आप स्पोर्ट्स के बारे में क्या करना चाहते हैं और मैंने बताया कि इसके ऊपर राजनीतिक लोग किस प्रकार से कब्जा जमाए हुए हैं तो इन्होंने कहा था कि हम हरियाणा वाली पॉलिसी लेकर आएंगे। मुझे हैरानी हुई कि वही मंत्री हिमाचल प्रदेश के अखबारों के माध्यम से कह रहे हैं कि हमने स्पोर्ट्स की कोई पॉलिसी नहीं लानी है जबकि आज माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां कहा कि हिमाचल प्रदेश के लिए स्पोर्ट्स पॉलिसी आएगी। अब मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि जो मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं उसके विपरीत उनके मंत्री कह रहे हैं। यह रिकॉर्ड की बात है। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं विपक्ष का विधायक हूं लेकिन अगर आप रिकॉर्ड उठाएं तो मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी से पिछले बजट सत्र के दौरान जब इस मसले को उठाया था तो इन्होंने कहा था कि हरियाणा की तर्ज पर पॉलिसी लाएंगे। सत्र खत्म हुआ और हरियाणा की तर्ज भी खत्म हो गई और अब फिर कह रहे हैं कि हम स्पोर्ट्स पॉलिसी लेकर आएंगे। यह किस प्रकार का न्याय है और किस प्रकार की नीति आप खेलों के लिए बनाना चाह रहे हैं?

अब मैं पर्यटन की बात करूंगा। अब आपने मण्डी के अलावा पौंग डैम पकड़ लिया है। मण्डी मुख्य मंत्री जी का चुनाव क्षेत्र है और साथ में मण्डी काशी की बात कर रहे हैं। उपाध्यक्ष जी, सरकार को यह सोचना चाहिए कि अगर पर्यटन को बढ़ावा देना है तो जैसे ही पर्यटक हिमाचल प्रदेश में एंटर होता है, उसको वहां के वातावरण के मुताबिक सहुलियत मिलनी चाहिए।

11.02.2019/1635/जेके/डीसी/1

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और करना चाहता हूं कि भाखड़ा विस्थापितों ने अपने प्राणों की आहूति दी। मैं यहां पर कहूंगा कि बिलासपुर के 3600 लोग

ऑस्टीज़ बनें और हिसार चले गए। वहां पर उनका बसाव ठीक नहीं हुआ। उनके ऊपर कर्जे चढ़े थे। यह सारी बातें रिकॉर्ड में हैं। माननीय वीरभद्र सिंह जी आए और उससे पहले माननीय श्री शांता कुमार जी पीपल के पेड़ के नीचे कसम खा गए थे कि भाखड़ा ऑस्टीज़ के कर्जे मैं माफ करूंगा लेकिन जब उनकी सरकार बनीं और जब वहां के लोग यहां पर उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि मैंने केवल बिलासपुर के लोगों को ही नहीं देखना है। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं श्री वीरभद्र सिंह जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, आपने उनका ब्याज भी माफ किया, आपने उनके कर्ज़े भी माफ किए, आपने नए सैक्टर्ज़ बनाने की भी बात की । अब देखेंगे कि वर्तमान सरकार वे सेक्टर कहां पर बना रही है? आज जब हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, जब हम पैरा ग्लाइडिंग की बात कर रहे हैं और बड़े-बड़े डैम्ज़ से फायदा लेने की बात कर रहे हैं, मैं कहूंगा कि वह भाखड़ा बांध जिसमें जिन लोगों ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया उस भाखड़ा बांध के विस्थापितों के लिए एक शब्द भी हिमाचल प्रदेश सरकार ने नहीं कहा है। बी0बी0एम0बी0 हमारे को कुछ नहीं देना चाहता। आप जो 7.19 प्रतिशत इम्पलॉयमैंट देने की बात कर रहे हैं, वह भी बिलासपुर और हिमाचल प्रदेश के लोगों को नहीं मिली। मैंने प्रश्न के माध्यम से पूछा था कि जो हिमाचल प्रदेश को बी0बी0एम0बी0 का हिस्सा मिलेगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, उसमें विस्थापितों के लिए क्या करेंगे? मुझे उत्तर मिला, यहां पर पावर मिनिस्टर साहब बैठे हैं, वह प्रश्न नहीं लगा लेकिन उत्तर आ गया था। उसमें इन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी कोई स्कीम नहीं है। इसका मतलब जिन्होंने भाखड़ा विस्थापन में अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, हिमाचल प्रदेश की मौजुदा सरकार उनके लिए कुछ भी करने वाली नहीं है।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, प्लीज वाइंड अप करें।

श्री राम लाल ठाकुरः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक-दो बातों को कह कर अपनी बात को वाइंड अप करूंगा। जनमंच पर मैं आपकी सेहत को खराब नहीं करना चाहता । पहले भी "प्रशासन जनता के द्वार" कार्यक्रम होता था। आपने जो कार्यक्रम शुरू किए, उन

कार्यक्रमों में और क्या जोड़ा गया? यह कि आपने जमाबंदी की नकल इन जनमंच के कार्यक्रमों में देनी है। वहां पर एस0सी0 का सर्टिफिकेट, एस0टी0 का सर्टिफिकेट जनमंच में मिलेगा। अगर कहीं पर किसी की सूट पार्टिशिन की हिस्सेदारों के बीच में है, तब भी उन चीजों को जनमंच में उठाते हैं। मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि मैं पेशे से वकील हूं। जो भी पार्टिशन है, उसमें लिगली आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप लोगों को बुला रहे हैं कि पार्टिशन के लिए भी अप्लाई करो। अगर पानी का नलका देना है तो हमारे महेन्द्र सिंह ठाकुर जी क्या करेंगे? आप वहां पर नलका देने की भी बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अब 50 मीटर तक 50 प्रतिशत हिस्सा मकान मालिका का होगा और 50 प्रतिशत हिस्सा कनैक्शन देने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार देगी। साथ में कह दिया कि हर घर को बिजली का कनैक्शन मिलेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं रिकॉर्ड में लाना चाहूंगा, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, मैं हिमाचल प्रदेश में माननीय वीरभद्र सिंह जी के साथ पावर डिपार्टमैंट देख रहा था, उस समय हिमाचल प्रदेश के जितने भी एस0सीज़0 लोग थे, जिनके पास पैसा नहीं था, उनको हिमाचल प्रदेश की उस समय की सरकार ने यह कहा था कि डेढ़ प्वाइंट हर घर के अन्दर हिमाचल प्रदेश की सरकार लगाएगी। मुझे खुशी है कि हमने वर्ष 1987 तक इस कार्य को पूरा किया था।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, प्लीज वाइंड अप करें।

श्री राम लाल ठाकुरः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर एक बात और पूछना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। मेरे चुनाव क्षेत्र नैना देवी जी में कार्यक्रम हुआ। वहां पर पंचायती राज मंत्री गए हुए थे। मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूं कि क्या कारण है कि आप बेटी के नाम से एक पौधा तो लगाना चाहते हैं लेकिन आप बरसात के मौसम में सर्दियों में लगने वाला पौधा लोगों को बांट रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि बिलासपुर के नैना देवी में किन्नू के पौधे दिए गए जो सर्दियों में नहीं लगते, बरसात में लगते

हैं। इसी से लगता है कि आप बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ के बारे में कितने चिंतित हैं, आप बेमौसमी काम करना चाहते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जुखाला में एक कैफे बना हुआ है। माननीय प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी ने उसका शिलान्यास किया था। पिछले साल भी वह नहीं चला। इस सरकार को एक साल हो गया।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, आपसे निवेदन है कि आप वाइंड अप करें।

श्री राम लाल ठाकुरः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस कैफे के सारे-के-सारे शीशे टूट गए। अगर उसकी जरूरत नहीं थी तो उसको टूरिज्म नें क्यों बनाया? आज की तारीख में भी वही कैफे वहीं पर है। दूसरे, मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा जितने भी हैण्डपम्प लगाए जा रहे हैं उनको ज्यादा महत्व मिलना चाहिए,

11-02-2019/1640/SS-HK/1

जो ड्रॉट हिट एरिया है। यह न हो कि लोगों को हैंडपम्प चाहिए जहां पर पानी नहीं है और फिर टेलीफोन आ जाए है कि यह हैंडपम्प नहीं मिलना चाहिए।

उपाध्यक्षः काफी हो गया। माननीय राम लाल जी, मेरा निवेदन है कि आप कृपया वाइंड अप करें।

श्री राम लाल ठाकुरः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आनंदपुर हाईडल की स्कीम के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। 25 क्यूसिक आनंदपुर हाईडल की स्कीम माननीय वीरभद्र सिंह की सरकार ने 88.9 करोड़ रुपये की स्वीकृत की थी। उन दिनों मैं हिमाचल प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री हुआ करता था। आगे सरकार बदली और हुआ यह कि काम करने के लिए फिर दूसरी सरकार आई, 88.9 करोड़ रुपया खर्च हो गया लेकिन उस स्कीम के अधीन जो जमीन आनी थी वह नहीं आई। कागज़ों में 20 परसैंट जमीन को पानी मिल गया लेकिन वास्तव में जमीन में पानी नहीं आया। जब मैंने इस मसले को उठाया तो मुझे महेन्द्र सिंह जी

ने बोला कि हमने डिपार्टमैंट को आदेश किये हैं। अब 18 करोड़ रुपये से हमारे बचे हुए खेत को पानी देने की बात हो रही है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार से चंगर एरिया के लिए जो हमारी पानी की स्कीम है उसके बारे में बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में उसके ऊपर आप कुछ नहीं कर रहे हैं।

उपाध्यक्षः माननीय राम लाल जी, आपसे गुजारिश है कि आप समाप्त करें अन्यथा मैं श्री विनोद जी को बोलने के लिए बुलाऊंगा।

श्री राम लाल ठाकुरः इसलिए मैंने जो हिमाचल प्रदेश के अंदर हो रहा है, उसके बारे में बताया। लोगों की दुर्गति हो रही है। उस दुर्गति के बारे में भी हिमाचल प्रदेश की सरकार को चिन्तित रहना चाहिए। इसलिए मैं यह कहूंगा कि यह लोगों को मूर्ख बनाने वाला बजट है। नौजवानों व किसानों को मूर्ख बनाने वाला बजट है, इससे कोई भी रिजल्ट आगे आने वाला नहीं है।

उपाध्यक्षः मेरा सभी माननीय विधायकों और माननीय सदस्यों से निवेदन है कि जिस तरह से आप घंटी बजाने के बाद रफ्तार पकड़ते हैं, ऐसी रफ्तार शुरू से ही रखें और विषय पर ही बोलें। ऐसा मेरा आप सभी से निवेदन है। अब माननीय विनोद जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री विनोद कुमार (नाचन)ः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री, आदरणीय जय राम ठाकुर जी ने 9 फरवरी, 2019 को हिमाचल प्रदेश का 2019-20 का बजट पेश किया, मैं उस बजट पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, प्रदेश के मुख्य मंत्री आदरणीय जय राम ठाकुर जी ने जो बजट पेश किया है वह हिमाचल प्रदेश को विकास की नई दिशा देने वाला बजट है। इस बजट में हिमाचल प्रदेश में रहने वाले हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। इसके लिए मैं प्रदेश की समस्त जनता की ओर से माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं तथा धन्यवाद करता हूं। जहां तक इस बजट को ले करके हमारे विपक्ष के कुछ साथियों ने चर्चा की है, उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि इन्होंने अपना राजधर्म निभाया है। विपक्ष का काम जो सत्तापक्ष द्वारा किया हुआ काम होता है, उसमें नुक्स निकलाना और बाल की खाल निकलाना होता है। मुझे लगता है कि उस काम को भी विपक्ष बखूबी से नहीं कर पा रहा

है। जो बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है उसे लेकर विपक्ष की ओर से काफी टीका-टिप्पणी हुई है। मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर आदरणीय ध्वाला जी को लेकर भी माननीय विपक्ष के नेता की ओर से बात आई है कि ध्वाला जी को प्लानिंग बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जो हमने किया, वह आपके हिसाब से गलत है। आप शायद अपना वक्त भूल गए कि जब आपकी सरकार प्रदेश में थी तो आपने गंगू राम मुसाफिर जी को पांच वर्षों तक उसी प्लानिंग बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाकर रखा और उसी पुरानी कोठी में उन्हें बिठाकर रखा। वे कहते थे कि अगर मैं इस कोठी में रहूंगा तो दूसरी बार फिर जीतकर आऊंगा। इस तरह की चर्चाएं उस समय हुआ करती थीं। जैसा कि यहां पर कहा गया कि अभी तक वह कोठी उनके द्वारा खाली नहीं की गई। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यहां पर किसानों को लेकर बहुत बड़ी-बड़ी चर्चाएं की जा रही हैं। आपकी सरकार प्रदेश में पांच साल रही,

11.2.2019/1645/केएस/एचके/1

आपने किसानों के उत्थान को ले कर कौन सी योजना बनाई, इस सदन के माध्यम से आप प्रदेश की जनता को बताएं? मैं कहना चाहूंगा कि जब 2012 में हम पहली बार विधान सभा में चुन कर आए थे तो आपने जो पहला बजट पेश किया था, उसके अंदर आपने किसानों को जो बिजली मिलती है, 75 पैसे युनिट से बढ़ाकर आपने 1 रुपये प्रति युनिट की थी। मैं हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने सरकार बनने के तुरंत बाद यह निर्णय लिया, सभी विधायको के साथ इस बात पर चर्चा हुई कि किसानों के उत्थान तथा विकास को ले कर हम क्या योजना बना सकते हैं तो सभी विधायकों की ओर से सुझाव आया था कि किसानों को मिलने वाली बिजली के दाम कम होने चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं प्रदेश के मुख्य मंत्री का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने अपने पहले ही बजट के दौरान उस एक रुपये युनिट से मिलने वाली बिजली को 75 पैसे प्रति युनिट करने का काम किया । जब दूसरा बजट पेश करना था तब भी इन्होंने सभी माननीय विधायकों से चर्चा करने के बाद, जब फिर से माननीय विधायकों ने अपना पक्ष रखा कि किसानों को लेकर हमें और चिंता करने की आवश्यकता है, सभी विधायकों ने माननीय

मुख्य मंत्री जी से विचार-विमर्श किया कि यह जो 75 पैसे युनिट बिजली किसानों को मिलती है, इसको 75 पैसे से घटाकर 50 पैसे प्रति युनिट किया जाना चाहिए तो मुख्य मंत्री जी ने किसानों की चिंता करते हुए और विधायकों की ओर से जो सुझाव आए थे, उन पर चिंता करते हुए 50 पैसे प्रति युनिट बिजली देने का काम किया है। मैं इस माननीय सदन के माध्यम से अवगत करवाना चाहूंगा कि 50 पैसे प्रति युनिट बिजली किसानों को आज से लगभग 15 या 20 साल पहले मिलती थी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के मित्र कह रहे थे कि राम राज्य कब आएगा? मित्रो, मैं कहना चाहूंगा कि 15 साल पहले जिस दर से किसानों को बिजली मिलती थी, आज उसी दर से आदरणीय जय राम ठाकुर जी ने किसानों को बिजली देने का काम किया है, यही राम राज्य है। इसके साथ-साथ यहां पर जनमंच को ले कर विपक्ष की ओर से बहुत टीका-टिप्पणी की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रदेश सरकार की ओर से अभी तक 106 जनमंच के कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में किए गए हैं और इसमें 33,966 शिकायतों का प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों तथा वहां पर आए अधिकारियों की ओर से निपटारा किया गया। एक बात कही गई कि पुराने समय में भी इस प्रकार के कार्यक्रम हुआ करते थे। जैसे यहां पर कहा गया कि "सरकार जनता के द्वार" एक कार्यक्रम होता था। हमने भी शायद वह कार्यक्रम देखा हैं लेकिन उस कार्यक्रम में और इस कार्यक्रम में एक अंतर है। उस समय जब वह कार्यक्रम होता था तो नेता के साथ कुछ अधिकारी/कर्मचारी और कुछ पार्टियों के वहां के जो स्थानीय नेता होते थे, वे चुपचाप किसी रैस्ट हाउस में बैठ कर चर्चा करते थे, भोजन करते थे लेकिन जो दूर-दूर से लोग आते थे, जो चार-चार, पांच-पांच घंटे उस कार्यक्रम में बैठते थे, उनकी किसी प्रकार की चिंता उस सरकार द्वारा नहीं की जाती थी। फर्क देखिए कि उस समय के नेता रैस्ट हाउस में बैठकर भोजन करते थे लेकिन आदरणीय जय राम ठाकुर जी के मंत्री वहां आई हुई जनता के बीच में बैठकर भोजन करते हैं, यह राम राज्य है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर बहुत सी टीका-टिप्पणी मेरे बड़े भाई आदरणीय मुकेश जी द्वारा की गई। यहां पर "अटल आदर्श विद्यालय" योजना की बात आई। मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने इस बात को सीधे तौर पर कहा है कि जिन विधान सभा क्षेत्रों के अंदर कोई भी केन्द्रीय विद्यालय नहीं है, कोई सैनिक स्कूल नहीं है, वहां पर

11.2.2019/1650/av/yk/1

हमारी सरकार द्वारा पिछले बजट में यह तय किया गया था कि 10 विधान सभा क्षेत्रों में अटल आदर्श विद्यालय खोले जायेंगे। यह बात ठीक है कि अभी तक दो ही आदर्श विद्यालयों का शिलान्यास हुआ है और बाकियों के लिए प्रोसैस चला हुआ है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय के आशीर्वाद से हमें एक अटल आदर्श विद्यालय दिया गया है। लेकिन उसमें हम जगह को लेकर यह निर्णय नहीं कर पाये कि इसको यहां बनाना है या वहां बनाना है जिसके कारण उसमें देरी हुई है। लेकिन सरकार ने उस अटल आदर्श विद्यालय को हमें दे भी दिया है और उस विद्यालय का निर्माण कार्य आने वाले समय में जल्दी ही शुरू होने वाला है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह भी तय किया है कि उन 10 अटल आदर्श विद्यालयों के अलावा 15 और नये अटल आदर्श विद्यालय खोले जायेंगे जिसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। पहले बहुत से स्कूलों से शिकायत आती थी कि गर्मी के मौसम में खराब पानी पीने के कारण वहां पढ़ने वाले बच्चे बीमार पड़ गये। पिछली सरकार के समय इस तरह की बहुत सारी शिकायतें आती रही हैं। इसलिए इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए मुख्य मंत्री जी ने एक नई योजना 'अटल निर्मल जल योजना' का शुभारम्भ किया है। इस योजना के तहत हमारे सभी सरकारी स्कूलों में वाटर फिल्टर लगाये जायेंगे। मैं इसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। यहां पर विपक्ष की ओर से प्रदेश के युवाओं के उत्थान और स्पोर्ट्स एक्टिविटी को लेकर के बातें आ रही थीं। लेकिन मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने 'मुख्य मंत्री युवा निर्माण योजना' शुरू की है। इस

योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा हरेक विधान सभा क्षेत्र में दो बड़े-बड़े खेल के मैदानों सहित जिम भी उपलब्ध करवाये जायेंगे ताकि हमारा नौजवान जो नशे की तरफ जा रहा है वह उससे दूर रहे। इस मन्शा के साथ हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने इस योजना को शुरू किया है।

वर्ष 2006 से लेकर जिन पी0टी0ए0 टीचर्स को लेकर चुनावों के दौरान राजनीति व चर्चा होती थी उन सभी पी0टी0ए0 अध्यापकों को यदि किसी ने सबसे बड़ी राहत देने का काम किया है तो वह हमारी आदरणीय जय राम जी की सरकार ने किया है। इन अध्यापकों को अब नियमित अध्यापकों के बराबर मानदेय मिलने वाला है। मैं यह कहना चाहूंगा कि पूरे हिमाचल प्रदेश में हमारे ये जो 5500 के करीब पी0टी0ए0 अध्यापक हैं इनकी सैलरी अब मुख्य मंत्री जी के आशीर्वाद से 20 हजार से बढ़कर 34-35 हजार रुपये होने वाली है। इसके अतिरिक्त हमारे 97 पैरा टीचर्स थे और इनको भी नियमित अध्यापकों के बराबर मानदेय मिलेगा। इसी तरह से एस0एम0सी0 के अध्यापकों की भी डिमाण्ड थी कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। इनकी 20 प्रतिशत सैलरी बढ़ाने के लिए मैं प्रदेश के मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। यहां पर विपक्ष की ओर से मुख्य मंत्री स्वावलम्बन योजना की बात की गई है। इस योजना के तहत पहले 18 से 35 वर्ष के नौजवानों को लाभ दिया जाता था। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में हमारे प्रदेश के नौजवान माननीय मुख्य मंत्री जी से मिलें और कहा कि इस आयु सीमा को 35 वर्ष से बढ़ाया जाना चाहिए। मैं प्रदेश के मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इस 35 वर्ष की आयु सीमा को बढ़ाकर 45 वर्ष किया है। इसमें पहले जो 40 लाख रुपये तक का ऋण मिलता था उसको भी आपने बढ़ाकर 60 लाख रुपये किया है।

11/02/2019/1655 /टी0सी0वी0/वाई0के0/1

इसमें उन नौज़वानों ने एक बात और कही थी कि इसमें बिल्डिंग का प्रोविज़न भी किया जाए, वह भी आपने किया है। यहां पर माननीय सदस्य करूणामूलक आधार पर नौकरियों

की बात कर रहे थे कि जो भी किया है, वह पिछली सरकारों ने किया है। लेकिन मैं एक बात इस सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा कि क्या यह बात सही नहीं है?, जब पिछली बार आपकी सरकार थी तो आपने ही तय किया था कि यदि 50 साल की उम्र से ऊपर किसी भी सरकारी कर्मचारी की डैथ होती है, तो उसको करूणामूलक आधार पर सरकारी नौकरी में नहीं रखा जाएगा। इस प्रकार की नोटिफिकेशन कांग्रेस सरकार के द्वारा की गई थी। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस आयु सीमा को हटाकर तह किया कि जब तक कोई कर्मचारी/अधिकारी रिटायर नहीं हो जाता, चाहे रिटायरमेंट होने से दो दिन पहले भी किसी कर्मचारी/अधिकारी की मृत्यु होती है तो उसके परिवार के किसी नौज़वान को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा रोजगार दिया जाएगा। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। इससे प्रदेश के लगभग 20 हजार नौज़वानों को सीधा लाभ मिलने वाला है। एक और बहुत अच्छी सुविधा माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा शुरू की गई है। जितने भी मैडिकल कॉलेजिज है, पहले जब किसी मैडिकल कॉलेज में क्रिटिकल कंडीशन में कोई पेशैंट होता था तो उसको ले जाने के लिए वैंटिलेटर की आवश्यकता होती थी। क्योंकि एम्बुलेंस के अंदर वैंटिलेटर नहीं होते थे और वे चण्डीगढ़ से मंगवाने पड़ते थे। इस तरह का एक केस मण्डी में श्री अजय राणा जी का था। वहां पर भी इसी तरह की एक एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ी थी, जिसमें वैंटिलेटर भी एम्बुलेंस के अंदर हो। लेकिन अब जितने भी मैडिकल कॉलेज खोले गए हैं, उन सभी मैडिकल कॉलेजों में यह एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। ये है राम राज्य। जब हम गावं में जाते हैं, तो बहुत से लोग वहां पर बीमार होते हैं और जब उन्हें हर महीने 500-1000 रुपये की दवाइयां लेने होती है, तो उस समय उनके घरवाले भी स्पोर्ट नहीं करते हैं। उस समय उनका कोई भी सहारा नहीं होता है। इसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक नई योजना 'सहारा' का शुभारम्भ किया है। इस योजना के तहत कैंसर, पैरालाइज्ड, हीमोफिलिया या रीनल फेल्योर, इन सभी बीमारियों से जूझ रहे जो व्यक्ति होंगे, उन गरीब परिवारों को हर महीने 2000-2000 रुपये प्रदेश सरकार की ओर से दिए जाएंगे।

माननीय उपाध्यक्ष जी, जब कोई आदमी अपने परिवार के किसी सदस्य को ले करके जोनल हॉस्पिटल में जाता है और कहीं कारण से उसके उस सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी डैड बॉडी ले जाने के लिए जब एम्बुलेंस या गाड़ी वालों से बात करते हैं तो वह कहते हैं कि हम डैड बॉडी को लेकर नहीं जाएंगे। इसके लिए भी सभी जोनल अस्पतालों के लिए एक शव वाहन लाने की योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाई है। जिसके तहत जितने भी प्रदेश के अंदर जोनल अस्पताल हैं, उनमें वह शव वाहन मिलेंगे। जिसका सीधा लाभ वहां के गरीब लोगों को मिलेगा।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, वाइंडअप करें।

श्री विनोद कुमारः माननीय उपाध्यक्ष जी इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा यहां पर किसानों के उत्थान के लिए बड़ी-बड़ी बातें की गई। हमारी सरकार ने पिछले साल 'मुख्यमंत्री संरक्षण योजना' के तहत एक नहीं अनेकों लोगों को इस योजना के तहत सोलर फैंसिंग का प्रबंध किया था। लेकिन बहुत से विधायकों (पक्ष/विपक्ष) की ओर से एक बात आई थी कि ये जो सोलर फैंसिंग लगाई जा रही है यह ठीक है।

11-02-2019/1700/NS/AG /1

लेकिन इसके साथ-साथ कांटेदार तारें भी बीच में लगनी चाहिए। इस बात को भी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने मान लिया है। इन तारों को लगाने के लिए अगर आपके 100 रुपये खर्च होते हैं तो 50 रुपये प्रदेश सरकार की ओर से दिए जाएंगे। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री का दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूंगा। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहूंगा कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट में दूध के दाम 2 रुपये बढ़ाए हैं, इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। यहां पर माननीय मुख्यमंत्री ने एक और नई योजना की घोषणा की है, "मुख्यमंत्री स्वजल योजना।" हम देखते हैं कि जब गरीब आदमी अपना घर बनाता है तो घर बनाने के बाद पहला काम बिजली और दूसरा काम पानी का होता है। जब पानी का कनैक्शन लेने की बात आती है और वहां पर 7 या 10 पाईपें लगनी हों तथा जब इन पाईपों को खरीदने की बात आती है तो निश्चित तौर पर

गरीब आदमी इस बात की चिंता करता है कि इन पाईपों को कैसे लाया जाए? मैं, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस योजना के तहत 50 मीटर पाईप 50 प्रतिशत सबसिडी के ऊपर हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा यह बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, कृप्या वाईंड-अप करें।

श्री विनोद कुमारः माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं अपनी बात को एक-दो मिनट में समाप्त करूंगा। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि नाबार्ड के तहत हमें लगभग 90 करोड़ रुपये पांच साल में खर्च करने होते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने तय किया है कि हमें लगभग 90 करोड़ नहीं बल्कि लगभग 105 करोड़ रुपये हर विधान सभा क्षेत्र को पांच साल में खर्च करने के लिए मिलेंगे। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहूंगा।

इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री ने विधायक निधि 1.25 करोड़ रुपये से बढ़ा करके 1.50 करोड़ रुपये की है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं इस माननीय सदन को बताना चाहूंगा कि जब हम पिछली बार यहां पर जीत करके आए थे तो उस समय दो वर्षों में केवल 10 लाख रुपये विधायक निधिको उस समय की सरकार की तरफ से बढ़ाया गया था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की सरकार ने 40 लाख रुपये विधायक निधि बढ़ाई है। इसके लिए मैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। विधायक निधि के अंतर्गत हम 20,000 रुपये की राशि महिला मंडल के लिए देते थे, अब ये राशि 25,000 रुपये की गई है। इसी की तर्ज़ पर हम युवक मंडलों को भी 25,000 रुपये दे सकेंगे। इसके साथ-साथ हमारी ऐच्छिक निधि भी माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से 7 लाख रुपये से बढ़ा करके 8 लाख रुपये की गई है। अंत में, मैं यही कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि "हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना" और केंद्रीय "उज्जवला योजना" के लाभार्थियों को एक अतिरिक्त गैस रिफिल मुफ्त दिया जाएगा। पूरे प्रदेश में लगभग 2 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा और गैस का कनैक्शन फ्री में हमारी सरकार ने देने का काम किया है और एक गैस रिफिल मुफ्त देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने जो चूल्हा

जलता था उस चूल्हे को जलाने के लिए माचिस की एक तीली तक देनी उचित नहीं समझी। इसलिए इस बात को ले करके इनको (विपक्ष)पीढ़ा हो रही है।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, कृप्या वाईंड-अप करें।

श्री विनोद कुमारः माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

सपने वे सच होते हैं, जिन सपनों में जान होती है।

पंखों से कुछ नहीं होता है, मित्रो, हौंसलों से उड़ान होती है।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

उपाध्यक्षः अब माननीय सदस्य, डा0 (कर्नल) धनी राम शांडिल चर्चा में भाग लेंगे।

डा0 (कर्नल) धनी राम शांडिलः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री ने वर्ष 2019-2020 का बज़ट इस माननीय सदन में 09 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत किया। मैं उसी चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं।

11.02.2019/1705/RKS/AG-1

व्यवस्था का प्रश्न

Smt. Asha Kumari (Dalhousie): Hon'ble Deputy Speaker, Sir, I am on a Point of Order. You cannot run the House without a single Minister. बजट सत्र चल रहा है, बजट पर चर्चा हो रही है और सदन के भीतर एक भी मंत्री उपस्थित नहीं है। ...(व्यवधान)... आपको रूल्स पता नहीं हैं तो आप मत बोलिए। There is no Minister in the House and this is against the rules.

उपाध्यक्षः माननीय सदस्या, श्रीमती आशा कुमारी जी इसके लिए मैं व्यवस्था सुनिश्चित करूंगा। माननीय सदस्य, डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल जी आप अपनी बात रखिए।

डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिलः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता, श्री मुकेश अग्निहोत्री ने बड़े विस्तार से विभिन्न घटकों पर चर्चा की है। उनका प्रयास रहा है कि इस

बजट में कौन-कौन सी चींजें हाइलाइट की गई हैं जो प्रदेश के जनहित में दी गई हों तथा कौन-कौन सी चीजें ऐसी हैं जो लोकहित में नहीं है। मुझे लगा कि शायद यह बजट केंद्रीय बजट की तर्ज पर प्रस्तुत किया गया है। मैं इस चर्चा से पहले कुछेक महत्वपूर्ण बिन्दु बताना चाहूंगा। मेरा मानना है कि सदन सत्तापक्ष और विपक्ष दो पहियों पर चलता है। विपक्ष का मजबूत होना बहुत अनिवार्य है वरना लोकहित के मुद्दे कई बार ओझल हो जाते हैं। मैं वर्ष 2014 की चुनावी सभा और रैलियों को थोड़ा-सा विवरण देना चाहूंगा। वर्ष 2014 में कुछेक बहुत अच्छे-अच्छे वायदे किए गए थे और इसका जनता को सब पता है। सब लोग जानते हैं कि वे वायदे कितने पूरे हुए और कितने पूरे नहीं हुए। मेरा कहना है कि घोषणा ऐसी हों जो पूरी हो सके। यदि हम इस चर्चा में जाएंगे तो हमें सीमित समय में ही अपनी बात रखनी होगी और इसमें हम फंस जाएंगे। इसलिए मैं कुछेक बातें ही कहना चाहूंगा। चाहे स्मार्ट सिटी की बात हो , 'स्वच्छ भारत अभियान' हो या सांसदों का गांव को गोद लेना हो, आर्मी कंटोनमैंट्स या उनका खोलना हो, युवाओं की बेरोजगारी की बात हो या फिर नोटबंदी और जी.एस.टी. को बिना किसी प्लानिंग के लगाना हो। बड़े-बड़े घरानों के लोगों को तो संरक्षण मिल जाता है लेकिन कमजोर वर्ग या आम जनता को कतार पर खड़ा होना पड़ता है। मैं समझता हूं the last but not the least is the "Rafale". मैं इन सब चीजों का इसलिए इशारा करना चाहता था कि हम आज देश में किस प्रकार के दौर से गुजर रहे हैं। हो सकता है कि इस बजट से इसका संबंध न हो। लेकिन मेरा मानना है कि हमें वास्तविकता का पता होना चाहिए। Thomas Sowell has said that - I am repeating last year's quotation - "Talkers are usually more articulate than doers, since talk is their speciality". I repeat it. Talkers are usually more articulate than doers, since talk is their speciality. कल बसंत पंचमी थी और मेरे सामने बैठे साथियों ने शायद मां सरस्वती की पूजा की होगी। इन पर मां सरस्वती का विशेष वरदान है क्योंकि यह किसी भी बात को किसी भी रूप में रख सकते हैं। कभी-कभी इस प्रकार से लोक-लुभावन वायदे किए जाते हैं और लोगों को लगता है कि यह सच में होने जा रहा है। मैंने पूरा बजट पढ़ा है। जहां तक बजट का आशय है इसमें कोई संदेह नहीं कि बजट के लिए एक अच्छा प्रयास किया गया है। लेकिन मेरा मानना है कि जब इसे धरातल पर उतारा जाएगा तो इसमें मुश्किल सामने आएगी और I wish to substantiate my statement. जब फैक्ट्स एंड फिगर्ज शो करते हैं तो यह बजट 44,387

करोड़ रुपये का है जिसमें 7352 करोड़ रुपये डैफिसिट बताया गया है जिसे कर्ज लेकर पूरा किया जाएगा। इस बजट में अलग-अलग विभागों से 20 हजार नौकरियां देना प्रस्तावित है। My simple question is how you will deal with the deficit. एक इक्नॉमिक और फाइनैंस प्लानिंग का प्रश्न है। मैं समझता हूं कि घाटा पूरा करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। Is it going to be a back door taxation?

11.02.2019/1710/बी0एस0/डी0वी0-1

How do you visualize to achieve double imminent projects and how do you visualize to complete these projects and the targets. जैसा कि खास तौर से विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा बताया गया कि संसाधनों की कमी सामने आई है। पैरा 11-16 तक इस बजट में देखा जाए they are pertinent. दिए गए सीमित समय में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा it appears as if this Budget has been presented keeping in view the upcoming Lok Sabha elections. Para.12 on page 5 says " Deputy Speaker Sir, it is matter of pride that Himachal Pradesh has been ranked as the top performing State'. Yes, it is.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपके माध्यम से केवल इतना ही कहना है कि सरकार ने केवल अपनी ही पीठ थपथपाने का प्रयास किया है। हमें यह भी समझना चाहिए कि यहां तक हम कैसे पहुंचे? इस बारे में क्या कभी आपने सोचा है? इसमें आज तक की सरकारों और माननीय नेताओं को भी शुमार करना चाहिए था। चाहे इसमें स्वर्गीय डा0 वाई.एस. परमार जी हों, चाहे ठाकुर राम लाल जी हों या राजनीति के हिमालय हमारे शीर्ष नेता राजा वीरभद्र सिंह जी इस माननीय सदन में विद्यामान हैं। जिन्होंने विकास की बुलंदियां छुई हैं। मैं समझता हूं एक स्वर्णिम इतिहास इन्होंने दर्ज किया है। इनका भी यदि इस 83 पृष्ठ और 223 पैराज के डाक्यूमैंट में कहीं जिक्र किया होता तो हमें भी प्रसन्नता होती। Just a passing reference I am quoting Para 59 of last (2018-2019) Budget Speech ' Gram Gaurav Patt'. Hon'ble Deputy Speaker Sir, I want to ask you that which agency will decide कि यह गौरवशाली व्यक्तित्व है और यदि

डिसाइड भी कर लिया then who will protect that monument where it is erected. I am saying all this because recently four days back, मैं अपनी ग्राम पंचायत हिनर में था। वहां इन्होंने एक बोर्ड और साफ कर दिया। उससे पहले मैंने यह बात कही भी थी और मैंने पुलिस को खुद रिपोर्ट भी की थी कि 4-5 बोर्ड आई0पी0एच0 विभाग के ऐसे समाप्त कर दिए गए हैं जिसमें राजा वीरभद्र सिंह जी, माननीय श्रीमती विद्या स्टोक्स जी और मैं भी वहां पर शामिल था। पूर्व में आई0पी0एच0 मंत्री आदरणीय रविन्द्र सिंह रवि जी का भी बोर्ड साफ कर दिया गया। इन सब के बारे में मैंने पुलिस को लिख कर दिया। मैं समझता हूं कि पक्ष के माननीय सदस्यों को पूर्व प्रधान मंत्री आदरणीय पंडित जवाहर लाल नेहरू जी का नाम लेना भी अच्छा नही लगता । आम जन में यह भावना पैदा करनी होगी कि जो भी गौरव हम प्रदान करना चाहते हैं, जो भी सम्मान हम देना चाहते हैं उसे महफूज रखा जाए। Before I come to the text of my own area and budget. I also wish to speak about the rare happenings of our Country which we have demolished. हम सब संसाधनों को डैमेज कर चुके हैं चाहे आर.बी.आई. हो, चाहे सी.बी.आई. हो, चाहे इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो या फिर न्यायपालिका हो। I wish to say they have not even left the armed forces जिसके लिए माननीय कर्नल इन्द्र सिंह जी यहां पर हैं, माननीय सुरेश कश्यप जी भी यहां पर हैं । माननीय मंत्री जी यहां पर नहीं बैठे हैं परंतु हमारे सैनिक कल्याण मंत्री हैं I want to just depict and define, who is a soldier? Soldier is to go where no human can go, Soldier is to do what no human can do and survive where no human has ever survived. This is not enner government job at all. Try to live that life of soldier for one day and your head will go in respect for him. मैं समझता हूं हमें हमारी आम फोर्सिज को जहां हैं, जैसी हैं उन्हें रहने देना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। Army cantonments का खोलना आम लोगों के लिए, it is not in the public interest and neither it is in the interest of security. Ratnuchak in Jammu & Kashmir का उदाहरण हमारे सामने है। हमरे दो दर्जन बच्चे वहां पर आतंकवादियों का शिकार हो गए थे। मैं जानता हूं सरकार को जन हित में कुछ वायदे करने होते हैं, भत्ते बढ़ाने होते हैं, पे बढ़ानी होती है।

11.02.2019/1715/डी0टी0/डी0सी0-1

श्री डा0 (कर्नन) धनी राम शांडिल जारी....

It is a good incentive. I must appreciate and compliment that MLA grant has been made Rs. 1.50 crores.

विवेक अनुदान राशि 7 से 8 लाख रुपये कर दी गई, it is good step, I appreciate it. I remember जब हम राजा वीरभद्र सिंह जी के पास जाते थे as a Minister, मैंने एक बार कहा कि आंगनबाड़ी के एक मुश्त पैसा बढ़ा दी जाए, इन्होंने पूछा कि कितने करने हैं, मैंने कहा 1000 रुपये और सचमुच में इन्होंने एक हजार रुपये बढ़ा दिया । भत्ते बढ़ाना अच्छी बात है यह कोई अभी की बात नहीं है we have been doing it in past. इसके अतिरिक्त हम लोगों ने नारी निकेतन केंद्र मशोबरा का आधुनिकीकरण किया। राजा साहब ने जो वृद्धाश्रम बसंतपुर में बनाया, उस वक्त की मंत्री रही श्रीमती नज़मा हैबतुल्ला जी ने भी उसे सराहा, मुझे आज भी याद है हम विज्ञान भवन में एक संगोष्ठी में उपस्थित हुए थे, उन्होंने कहा था कि यह सर्वश्रेष्ठ वृद्धाश्रम है जो राजा वीरभद्र सिंह जी की अध्यक्षता में हिमाचल को दिया । No wonder it is India's best Vridha Ashram.

Hon'ble Deputy Speaker, Sir, if I get little time from you, I would like to talk about my own Constituency, मैं जानता हूं आप भी समय बद्ध हैं। कोशिश करूंगा मैं अपने समय में ही अपनी बात पूरी कर सकूं। मैं समझता हूं कि माननीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने अपने अथक परिश्रम से और अपनी टीम के साथ जो स्कीमें शुरू की थी लगभग उन सभी स्कीमों को रोका गया है। मैं नही जानता हूं कि यह किस आशय से हुआ है परंतु मैं यह जानता हूं कि चुनाव नजदीक में हैं और इसका फायदा आप लोगों को मिलेगा। लेकिन इस बीच इन स्कीमों को जिस उद्देश्य के लिए इसे बनाया गया है वह एक बड़ा पहलू है जो प्रभावित हो रहा है। मैं अपने शामती बाई पास की बात करूं जो कि 28.5 करोड़ का फुली फंडिड प्रोजेक्ट है। यह बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है but now the work is very slow. थोड़ा सा पोर्सन रहता है which must have been done by now. यह तो शुक्र है

राजा वीरभद्र सिंह जी की अध्यक्षता में हम लोगों ने अपना मिनि सचिवालय समाप्त किया और उसका लोकाअर्पण भी कर दिया। अगर यह उस वक्त नहीं किया जाता तो शायद वह इससे आगे चला जाता। इसी प्रकार से हमारे अन्य स्कूल भी है चाहे वह कोटी दयोरा हो, चाहे वह सर्कट हाउस चंबा घाट हो, माननीय मुख्य जी ने पिछली साल शायद 3.5 करोड़ रुपये दिऐ थे। परंतु अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ है। Similarly walking path from Chambaghat to Saint Lukes area, इसी प्रकार चंबा घाट का अस्पताल, स्कूल का खेल मैदान is very important. Other projects in the area like Shamshanghat in Chambhaghat which was a public demand and I specially created a fund of Rs. 30 lakh for it but it is yet to come.हमने एक हरिद्वार बस मांगी थी वह मिल भी गई थी, उस वक्त के माननीय परिवहन मंत्री बाली जी ने उसे दिया भी था। परंतु न जाने किन कारणों से इसे बंद कर दिया गया है। मेरा सरकार से विनम्र निवेदन रहेगा कि इसे आरंभ किया जाए यह बहुत ही महत्वूपर्ण बस है। इसी प्रकार से कई सड़कें जिन्हें बहुत जल्द पूरा किया जा सकता है। वह पूरी कर दी जाए। Irrespective of MLA and his status in his constituency, I request Hon'ble Chief Minister that the direction must be given personally to each and every MLA about the programme of Hon'ble Chief Minister and Hon'ble Ministers. We use to do this in our Government. राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार में हर मंत्री का प्रोग्राम जाता था और सभी माननीय विधायकों को यह जाता था। यह अलग बात है कि उसमें आए या न आएं। परंतु यदि निमंत्रण नहीं दिया जाता तो यह एक अपमान वाली बात है। One very important thing which I want to discuss is regarding security reason. I had requested other MLAs also खासकर चम्बा या कुल्लू और दूरदराज के क्षेत्रों की तरफ जो जाते हैं उन लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। It is because there is no flash light.

11-02-2019/1720/एच.के./एन.जी./1

If security -cum- communication code is given to the POS's, so that MLAs can move faster with efficiency and reach the place where the programme is

organized in time. Sir, this is my request to you. In the nutshell, I want to say that the schemes are almost same old ones only covered with new decent, pleasant and popular names. So we can say that this is 'a old wine put into a new bottle now'. Sir, Law and Order must be attended as it merits special attention.

हमारे वरिष्ठ सदस्य माननीय श्री राम लाल ठाकुर जी ने कुछ बहुत ही जनहित में अच्छे मुद्दे दिए हैं जो किसानों के लिए, बागवानो के लिए और लो एण्ड आर्डर से सम्बन्धित है । मैं उन विषयों में अपने आप को सम्बन्ध करता हूंः

Mr. Deputy Speaker, Sir, before I conclude, I wish to submit in this August House that there comes a time in the history of a Nation when each female, male, young men and individual of a Country must think in one voice and now the time has come. We must protect our Country, our Constitution, our integrity and unity and we must have that love, affection for each and every community and sector of our society. As a soldier I can give you the evidence of that. It is a golden page in the history, when in 1962, 1965 & 1971 whatever was the difference between the ideologies, 'all rank and file' of all the political parties, irrespective of what orders they follow; everyone came together and we won these wars. Our Iron Lady Smt. Indira Gandhi, brought Pakistan Army to their knees and 93 thousand soldiers had to surrender arms, then Atal ji had described her 'Druga'. Secondly, we need to focus on Drug Menace. I am happy that there is a very good effort particular by Hon'ble Chief Minister and I have also attend one or two function with him. We must continue it as a good Abhiyan. We must learn from the past and never say that nothing happened.

To say that only in 55 months we have done what they couldn't do in 55 year. This is not a good statement at all. It is not appreciated. We must encourage our local industries, cottage industries and our unemployed youth to do the work. We need to impart them good training so that they can stand on their own feet.

मैं समझता हूं कि विकास एक सतत प्रक्रिया है । इसमें एक पार्टी या एक व्यक्ति या एक विचारधारा कुछ नहीं कर सकती । इसमें सभी का होना बहुत जरूरी है । यह एक महा यज्ञ की तरह है जिसमें सभी की आहुति डलनी चाहीए ।

Towards the end, I should have to say that to produce this document of 83 pages with 223 para's was a good hard work. My humble suggestion would be that we labour harder to bring all this to the grounds and let it be in reality so that people feel that it is not only to win 2019 Lok Sabha Election but to give benefit to our men and to our people. I am afraid till that happens I will not be in a position to support this document. Thank you Mr. Deputy Speaker, Sir, you give me the time to speak. Jai Hind.

उपाध्यक्ष : बजट परिचर्चा में भाग लेने के लिए माननीय सदस्य श्री किशोरी लाल जी ।

श्री किशोरी लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमन्त्री परम श्रद्धेय श्री जय राम ठाकुर जी ने 9 फरवरी, 2019 को वर्ष 2019-20 का जो यहां पर बजट अनुमान प्रस्तुत किया है मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खडा हुआ हूं । प्रदेश के चहुंमुखी विकास के इस बजट को प्रस्तुत करने के लिए मैं माननीय श्री जय राम ठाकुर जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं । समाज के सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा गया । उसमें हिमाचल प्रदेश के अन्दर परम श्रद्धेय श्री जय राम ठाकुर जी का धन्यवाद करता हूं कि 68 विधानसभा क्षेत्र में से 65 विधानसभा क्षेत्र का उन्होनें प्रवास किया है । जिसमें वहां लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए बहुत से कार्य किए है ।

11/02/2019/1725/RG/HK/1

विपक्ष के नेता श्री मुकेश अग्निहोत्री जी प्रदेश के मुख्य मंत्री और अधिकारियों की चर्चा कर रहे थे। मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि जब पिछली बार इनकी सरकार थी तो उस समय इन्होंने अपनी सरकार में सेवा निवृत्त अधिकारियों को बैठाकर रखा था जिससे पिछले पांच वर्षों में प्रदेश का विकास नहीं हो सका। जिस तरह से हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी ने वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक योजना के प्रस्तावित परिव्यय में 7,100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जो पिछले वर्ष के मुकाबले 800 करोड़ रुपये अधिक है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां जनमंच की बहुत ज्यादा चर्चा की जा रही थी। विपक्ष के मित्र इससे बहुत बैचेन हैं क्योंकि जिस ढंग से इसकी लोकप्रियता को देखते हुए पूरे हिमाचल प्रदेश में इस जनमंच के कार्यक्रम में आम-आदमी का फायदा होता है और गांव-गांव या दूर-दराज के क्षेत्रों में ये जनमंच के कार्यक्रम होते हैं। जिनकी किसी को कोई सुध नहीं होती थी, वहां कोई पूछता नहीं था, आज जनमंच कार्यक्रम के माध्यम से वहां कार्यक्रम किए जा रहे हैं जिससे लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है। लेकिन विपक्ष के ये मित्र कह रहे हैं कि इसमें खर्चा बहुत हो रहा है। यहां तो भाई श्री नन्द लाल जी ने इस बारे में एक प्रश्न भी लगाया था। मैं इनसे यह पूछन चाहता हूं कि आज पूरे हिमाचल प्रदेश में गांवों में किसी की सुध-बुध नहीं होती थी, अब इस जनमंच के कार्यक्रम द्वारा जो प्रदेश में हमारे गरीब भाइयों का फायदा हो रहा है, वह काबिलेतारीफ है। इस जनमंच के माध्यम से अब तक 106 कार्यक्रम हो चुके हैं जिसमें हजारों लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया। यहां एक बात और कही गई कि इससे अधिकारी व्यस्त रहते हैं। लेकिन मैं इसके लिए प्रदेश सरकार का धन्यवाद करता हूं कि यह जनमंच कार्यक्रम छुट्टी वाले दिन होता है। यदि मैं अपने आनी विधान सभा चुनाव क्षेत्र की बात करूं, मेरे यहां 22 पंचायतों में यह कार्यक्रम हुआ। जो कार्य नहीं भी होने थे, इस कार्यक्रम के आयोजन से पहले ही वे ऐडवान्स में पहले हो चुके थे। मैं इसके लिए प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि अभी हाल ही में जिला स्तर पर भी यह जनमंच कार्यक्रम के आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। आने वाले समय में हमारे इस जनमंच कार्यक्रम का और अधिक लोगों को फायदा मिलेगा।

माननीय उपाध्यक्ष जी, इसके अलावा हमारी सरकार ने अभी हाल ही में --(व्यवधान)--

उपाध्यक्ष : कृपया बीच में बात न करें।

श्री किशारी लाल : मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि इस तेरह महीने के छोटे से कार्यकाल में ही प्रदेश के विकास की विभिन्न योजनाओं के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रयासों से केन्द्र सरकार से 10,330/- करोड़ रुपये आ रहा है जिसमें विभिन्न योजनाओं के लिए प्रदेश में यह पैसा खर्च होगा। जिससे हमारे यहां प्रदेश का बहुत अधिक विकास होगा। अब कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं कि यह पैसा कहां आया? तो यह इनकी जेबों के लिए नहीं आएगा बल्कि प्रदेश के विकास के लिए यह पैसा आएगा। --(व्यवधान)---

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बीच में बात न करें।

श्री किशोरी लाल : इसके लिए मैं देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का एक बार पुनः धन्यवाद करता हूं। आज जिस तरह से विधायकों की प्राथमिकता योजनाओं के लिए नाबार्ड के अन्तर्गत प्रति विधान सभा चुनाव क्षेत्र में जो पहले 90 करोड़ रुपये का प्रावधान था, उसको बढ़ाकर अब 105 करोड़ रुपये किया गया है। इसके अलावा 'विधायक क्षेत्र विकास निधि' को भी 1.25 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.50 करोड़ रुपये करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जब हम गांवों में जाते थे तो वहां युवक एवं महिला मण्डलों के लिए फर्नीचर इत्यादि के लिए जो पहले राशि देते थे उसको भी 20,000/-रुपये बढ़ाकर अब क्रमशः 25-25 हजार रुपये किया गया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्य मंत्री आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी का धन्यवाद करता हूं कि लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए एक 'मुख्य मंत्री हैल्पलाईन' की स्थापना की गई है जिसमें हम फोन पर शिकायत कर सकते हैं और संबंधित विभाग के अधिकारी के माध्यम से उस शिकायत का निवारण किया जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज हम देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि 'उज्ज्वला योजना' के तहत 86,000 परिवारों को गैस के कनैक्शन दिए गए हैं। जो क्षेत्र इस योजना के अन्तर्गत छूट गए थे, अब 'हिमाचल गृहिणी

सुविधा योजना' के अन्तर्गत उसी तर्ज पर 49,000 परिवारों को गैस के कनैक्शन दिए जा रहे हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। अभी बजट में इस बात की घोषण की गई है कि इसके अतिरिक्त 'हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना' और केन्द्रीय उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एक अतिरिक्त गैस रिफिल भी मुफ्त दिए जाएंगे।

11/02/2019/1730/MS/AG/1

किसानों/बागवानों के लिए हमारे कांग्रेस के भाई बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप 60 वर्ष तक यहां राज करते रहे, फिर आपने इनके लिए क्या किया? मैं प्रदेश के लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने बागवानों/किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं स्वीकृत की हैं। जिसमें "मुख्य मंत्री खेत संरक्षण योजना" के तहत सोलर फैंसिंग लगाने व कांटेदार तार अथवा चेन लिंक बाड़ लगाने के लिए 50 प्रतिशत उपदान दिया जाएगा। इसी तरह से "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना" से भी हमारे किसानों को काफी फायदा हो रहा है। मैं "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना" के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि किसानों/बागवानों के लिए, जिनके पास 2 हैक्टेयर से कम जमीन है, उनको हर वर्ष 6000/-रुपये दिए जाएंगे। इससे हमारे हिमाचल प्रदेश के किसानों को फायदा होगा और किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी।

उपाध्यक्षः मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन रहेगा कि बीच में न बोलें।

श्री किशोरी लालः पहले कृषकों को सिंचाई के लिए बिजली की दर 1 रुपए प्रति युनिट से घटाकर 75 पैसे प्रति युनिट किया गया था और अब 75 पैसे से घटाकर उसको 50 पैसे किया है। "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" के तहत भी बहुत से क्षेत्रों का विकास होगा

और हिमाचल प्रदेश में 5,000 पॉली-हाउस बनाने के लिए हमारी सरकार द्वारा 85 परसेंट उपदान के रूप में दिया जा रहा है। हमारी सरकार ने इस बार एक और पहल की है कि जैसे पहले फलदार पौधे व बीज इत्यादि बाहर से निर्यात किए जाते थे, अब कृषक/बागवानों के लिए राहत देते हुए यहीं पर उनकी पैदावार को तैयार किया जाएगा।

इसी तरह से प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन के लिए देसी नस्ल की गाय खरीदने हेतु 50 परसेंट उपदान दिया जा रहा है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारा आनी विधान सभा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का ऐसा क्षेत्र है जहां दूध का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। पिछली बार जब हमारी सरकार थी तो दत्त नगर में एक मिल्क प्रोसैसिंग प्लांट स्थापित किया गया था परन्तु उसमें कुछ कमी आ गई और इस बार अब दत्त नगर में 50,000 लीटर प्रतिदिन की अतिरिक्त क्षमता का दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए हम प्रदेश के लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। उसके अलावा दूध के रेट में भी 2/-रुपये की वृद्धि की गई है, इसके लिए भी हम मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं।

इस बजट में पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों के मानदेय में भी वृद्धि की गई है, इसके लिए भी हम मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं।

"जनमंच" कार्यक्रम में लोगों की ओर से पानी की समस्याओं के बारे में कहा जा रहा था। लोगों की समस्याओं के निवारण हेतु "मुख्य मंत्री स्वजल योजना" लाई है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 50 मीटर तक पाइप सरकार द्वारा 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा वॉटर गार्ड, फिटर्ज और पम्प ऑप्रेटर्ज के मानदेय में भी वृद्धि की गई है।

यहां पर कांग्रेस के मेरे भाई कह रहे थे कि पी0टी0ए0/पैट की नियुक्तियां कर दीं और अब इनको नियमित नहीं किया जा रहा है। भाइयो, जब आप सरकार में थे, उस समय यह आपकी गलती रही क्योंकि आपने गलत नीति बनाई थी और रोस्टर को इम्प्लीमैंट नहीं किया था। आज आप उनको नियमित करने की बात कर रहे हैं? वे कैसे नियमित होंगे? आज हम प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते हैं कि जो टीचर्स अनुबन्ध पर रखे हैं तथा

जिन्होंने सितम्बर, 2018 को तीन साल की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें पेबैंड की न्यूनतम राशि जमा ग्रेड-पे व महंगाई भत्ता के बराबर राशि देने के लिए बजट में प्रावधान किया है।

11.02.2019/1735/जेके/वाईके/1

उसके अलावा यहां पर "मुख्य मंत्री स्वावलम्बन योजना" जो कि बहुत बड़ी योजना है, जिसमें हमारे युवाओं को रोजगार में फायदा होने वाला है, उसमें हमारी सरकार ने पिछली दफा 40 लाख रुपये उपदान देने का प्रावधान किया था और उसमें उम्र पिछली दफा 18 से 35 थी, इस बार हमारी सरकार ने 35 से बढ़ा कर 45 कर दी है। इसमें जो 40 लाख रुपये का उपदान देने का प्रावधान था, इस बार 60 लाख रुपये देने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए हम प्रदेश के लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस बार नई योजना "मुख्य मंत्री दस्तकार योजना"लाई है। जो गांव में कारिगर होते हैं, उनको औज़ार खरीदने के लिए हमारी सरकार ने 75 प्रतिशत तक उपदान देने का प्रावधान किया है। इसके अलावा इस प्रदेश में जो युवा हैं उनके द्वारा इस प्रदेश को आगे ले जाना है इसलिए उस दृष्टि से नशे को रोकना है, हमारी सरकार ने इसमें प्रयास किए हैं। मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे पड़ौसी मुख्य मंत्रियों के साथ और पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ पंचकुला में बैठक की, क्योंकि जो यह नशा है उसको रोकना बहुत जरूरी है। चिट्टा एक ऐसा नशा है जिसको रोकने के लिए हमारी प्रदेश सरकार ने कानून बनाया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम अपने देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने निर्णय लिया है कि जो सामान्य वर्ग के गरीब लोग हैं, उनको फायदा दिया जाए। हम चाहते हैं कि उनका बहुत ज्यादा विकास हो। जो सामान्य वर्ग में गरीब लोग हैं उनके लिए 10 प्रतिशत का आरक्षण रखा गया है। आज प्रदेश की बागडोर हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री, श्री जय राम ठाकुर जी के हाथों में है जो कि एक

किसान के बेटे हैं। उनकी सोच है कि हमने इस प्रदेश को आगे ले जाना है और गांव में किसी तरह से आम जन-मानस का विकास हो सके।

माननीय उपाध्यक्ष जी, पैंशन की भी बात की गई। सामाजिक सुरक्षा पैंशन 750 रुपये से बढ़ा कर 850 रुपये प्रतिमाह की है। जो 80 साल की उम्र की सीमा कांग्रेस के वक्त थी वह हमारी सरकार ने 70 वर्ष कर दी है । 1300 रुपये प्रतिमाह पैंशन राशि को बढ़ा कर अब 1500 रुपये कर दिया गया है।

इसके अलावा पर्यटन के बारे में हमारे विपक्ष के मित्र कह रहे थे कि पर्यटन पर कुछ नहीं हो रहा है। मैं प्रदेश के मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इसके लिए पिछले साल 50 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया था और वर्ष 2019-20 के लिए भी 50 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान रखा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी 25 जनवरी को मेरे चुनाव क्षेत्र आनी आए थे। उन्होंने मेरे आनी विधान सभा क्षेत्र के लिए बहुत से कार्य किए। आनी में जो सी0एच0सी0 50 बैडिड हॉस्पिटल था, उसको 100 बैडिड करने की अधिसूचना जारी कर दी है। आने वाले समय में वहां पर भवन का भी निर्माण किया जाएगा। आनी में एच.आर.टी.सी. का सब-डिपो खोला गया है। उसके अलावा लूहरी में बस स्टैंड बनाने की घोषणा की है।

11-02-2019/1740/SS-AG/1

उसके अलावा हमारे आनी में सर्किट हाउस के निर्माण की बात की है। निरमंड क्षेत्र के साथ हमारा सराहन से भठाट रोड जोकि दो निर्वाचन क्षेत्रों को जोड़ता है, उसे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में डाल दिया है। उसके लिए हम प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं।

पर्यटन की दृष्टि से मेरे आनी विधान सभा क्षेत्र में बहुत से ऐसे रमणीक स्थान हैं जिनको आने वाले समय में हम विकसित कर सकते हैं जैसे सबसे पहले हमारा पनेओ है।

उसके अलावा टकरासी, खनाग, लटांडा, मरगी, बागा-सराहन श्रीखंड महादेव और निरमंड है। निरमंड के साथ सरगा है और उसमें विशेष रूप से जो श्रीखंड महादेव की यात्रा है हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हम अपने प्रदेश के लोकप्रिय मुख्य मंत्री से मांग करेंगे कि चूंकि श्रीखंड महादेव की यात्रा में दूसरे प्रदेशों से भी बहुत सारे सैलानी आते हैं इसलिए वहां पर रोपवे की व्यवस्था की जाए। प्रदेश सरकार के माध्यम से यहां से एक बहुत बड़ा प्रोजैक्ट केन्द्र सरकार को भेजा जाए। यदि इसके माध्यम से भी वह सम्भव नहीं हो सकता है तो उस काम को प्राइवेट पार्टी को भी ऑफर कर सकते हैं ताकि आने वाले समय में मेरे आनी विधान सभा क्षेत्र का बहुत ज्यादा विकास हो सके।

मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि इतिहास में पहली बार तीन घंटे में बहुत सुन्दर तरीके से हिमाचल प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए बजट प्रावधान किया गया है और हमारे विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं है। इसमें बहुत कुछ है, ये बारीकी से कुछ देखते नहीं हैं और कह रहे हैं कि चुनावी बजट है। यह चुनावी बजट नहीं है। यदि आप पिछले साल का भी बजट देखें तो उसमें भी हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्य मंत्री ने प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए बहुत सारी योजनाओं का प्रावधान किया है।

मैं ज्यादा न कहते हुए इस शानदार बजट का, जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां पर पेश किया है, जोरदार समर्थन करता हूं, धन्यवाद, जयहिन्द, ।

उपाध्यक्षः धन्यवाद किशोरी लाल जी। अब चर्चा में भाग लेने के लिए मैं माननीय सदस्य, श्री अनिरूद्ध सिंह जी को आमंत्रित करता हूं।

श्री अनिरूद्ध सिंह (कसुम्पटी)ः माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट पर हो रही चर्चा में भाग लेने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी जो बजट आया है, मैं इसमें मुख्य बातें बोलना चाहूंगा। सबसे पहले सभी सदस्यों ने जनमंच के ऊपर बात कही। मैं समझता हूं कि जनमंच एक टोटल फेल्योर है और अपने ही लोगों की आपसी लड़ाई दिखाने के लिए जनमंच का निर्माण किया गया है। अभी आपने पीछे हाल में देखा है कि चौड़ा मैदान में क्या हुआ। मैं समझता हूं कि जो उसमें पैसे खर्च किये जा रहे हैं, उसमें 4.2

लाख रुपये की लिमिट है। वह पब्लिक का मनी है। माननीय राजा साहब के समय में भी मैं बोलना चाहूंगा कि प्रशासन जनता के द्वार कार्यक्रम था।

(कर्नल इंद्र सिंह, माननीय सभापति महोदय पदासीन हुए।)

मगर उसमें सरकार के कोई भी पैसे नहीं लगते थे। लोग खुद पैसे इकट्ठे करके कार्यक्रम करते थे। इसमें रेवेन्यू संबंधी काम हो रहे हैं, यह जनमंच में लैपटॉप लेकर और प्रिंटर लगाकर दिखा रहे हैं। यह काम पहले भी होते थे। पहले भी एस0डी0एम0 जाते थे। लेकिन यह पॉलिटिकली दिखाने की कोशिश की गई है कि मंत्रियों को वहां बिठा दो। यहां लोगों को और अफसरों को मंत्रियों की झाड़ का सामना करना पड़ रहा है, यह बड़ी शर्मनाक बात है।

इसमें स्टेट हाईवेज़ की बात आई है। आप डेढ़-दो साल से यही राग अलाप रहे हैं कि 65 हजार करोड़ रुपये स्टेट हाईवेज़ के लिए आए हैं, 59 हाईवेज़ बनने जा रहे हैं। परन्तु आप मुझे बताएं कि क्या एक की भी डी0पी0आर0 तैयार है? एक का भी सर्वे हुआ है? यह ज़रूर सदन में बताएं।

लैपटॉप और स्कूल ड्रैसिज़ की बात अगर करें तो पूरा साल निकल गया, बच्चे अगली क्लास में भी प्रॅमोट हो गए हैं परन्तु उनको अभी तक लैपटॉप और स्कूल ड्रैसिज़ नहीं मिल पाई। कुछ तो कॉलेज में भी चले गए हैं तो अब कॉलेज के लिए ही ड्रैस लेकर दे दीजिए तो ठीक रहेगा। ...(व्यवधान)... आप अपनी बारी में भी बोलियेगा कि अगली बारी देंगे।

11.2.2019/1745/केएस/एजी/1

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार बनने से पहले बात की गई थी कि चार टाइम्ज़ लैंड एक्विज़िशन हम देंगे। जो कम्पलसरी एक्विज़िशन है, चार टाइम उसका मुआवज़ा देंगे। क्या आप एक भी केस बताएंगें जिसमें चार गुना मुआवज़ा दिया गया है? लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया गया है। वह चाहे हेलिटैक्सी हो, बहुत बड़ाई की गई कि हम जुब्बड़हट्टी से हेलिटैक्सी चलाएंगे। जुब्बड़हट्टी से तो फेल होनी ही थी क्योंकि जितना समय शिमला से जुब्बड़हट्टी को लगता है, उतनी देर में तो सोलन पहुंच जाते हैं। तो यह तो

बहुत बड़ा फ़ेल्यर था । कम्पनीज़ नहीं मिल पाई । आदरणीय मुख्य मंत्री जी, शिक्षा मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी और कई अन्य ढली बाई-पास पर जा कर, साइट पर खड़े हो कर लोगों को बख़ान करते हैं और अखबारों में देते हैं, मैं बताना चाहूंगा उसके लिए 7 करोड़ रुपये की राशि माननीय वीरभद्र सिंह जी ने, जब ये मुख्य मंत्री थे, उसके लिए सेंक्शन करवाए और फोरैस्ट केस क्लीयर करवाया था। यह काँग्रेस सरकार के समय में हुआ है। बी.जे.पी. के एक साल के समय में कोई जादू नहीं हो गया है और उसका आज काम चल रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, आउटसोर्सिंग के लिए कहा गया था कि जितने भी 72 हजार लोग आउटसोर्सिंग पर नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए एक पॉलिसी बनाई जाएगी परन्तु जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, बजट में उसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है कि उनको रैगुलराइज़ किया जाएगा या उनको काँट्रैक्ट पर लिया जाएगा। यह हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ बहुत ज्यादा चीटिंग है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम लॉ एण्ड ऑर्डर की बात करें, नशे का जो हिमाचल प्रदेश में हाल है, एक बहुत ही गम्भीर समस्या पैदा होती जा रही है। रोज़ आए दिन अख़बारों में छप रहा है, मेरे पास कटिंग भी है। दैनिक जागरण कम से कम 50 बार छाप चुका है और अलग अलग हैडिंग से-"नशे के चुंगल में फंसी पहाड़ की जवानी, "शराब छोड़ चिट्टा-चरस के आदि हो रहे युवा, "पहाड़ बन गया नशे का बड़ा बाज़ार" इस तरह के कई हैडिंग्ज़ हैं। रोज़ अखबारों में आ रहा है। लॉ एण्ड ऑर्डर का तो यह हाल है कि एक साल के अंदर 1342 केस केवल एन.डी.पी.एस. के रजिस्टर किए गए। 7566 कैप्सूल्ज़ सीज़ किए गए, टेबलेट लगभग 38 हजार पकड़ी गई, इंजैक्शन 1100 पकड़े गए हैं, सीरप 1022, यह सिर्फ मैं आपको जनवरी तक का डाटा दे रहा हूं, चरस 70 किलो पकड़ी गई , हेरोइन 7.70 किलो पकड़ी गई और चिट्टे की बात करें तो उसके मेरे पास फीगर्ज़ नहीं हैं परन्तु पिछले हफ्ते ही जिस समय विधान सभा चल रही थी, शिमला शहर के बीचों-बीच मीडिया कर्मियों के सहयोग से 378 ग्राम चिट्टा पकड़ा गया। यह कानून के

हाल है । आए दिन मर्डर और रेप तो आम बात हो चुकी है। यह बहुत गम्भीर बात है लेकिन इसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, इसका बजट में कोई उल्लेख नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रिहैब सैंटर्ज़ के बारे में इस बजट में लिखा तो है कि इसके लिए हमने बजट रखा है लेकिन क्या वे बनेंगे या नहीं? मुझे तो लगता है कि यह सिर्फ कागज़ी बात है। मुझे नहीं लगता कि हिमाचल प्रदेश में सरकार ये सैंटर्ज़ स्थापित कर पाएगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम होर्टिकल्चर की बात करें, बड़े-बड़े बख़ान रोज़मर्रा के पेपर्ज़ में आ रहे हैं कि हम एंटी हेलगन लगाएंगे, हम किसानों/बागवानों के लिए सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं । परन्तु ऐटी हेलगन कहां है? केवल अख़बारों तक ही सीमित है। इस बारे में भी सरकार सोचें।

क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में हमारे बड़े भाई श्री राकेश सिंघा जी ने बड़ा वैलिड प्वाइंट बोला था कि क्रॉप इंश्योरेंस का कोई डॉक्युमैंट नहीं है। डॉक्युमैंट होना जरूरी है। वह स्टेट की पावर में है, वह इंश्योरेंस कम्पनीज़ को आदेश करें कि जैसे गाड़ी का या लाइफ इंश्योरेंस होती है, वैसे ही इसके लिए डॉक्युमैंट्स दें । वैदर और विंड के जो नॉर्मज़ हैं, बिल्कुल ठीक बात है कि यहां पर साइक्लोन नहीं आता या छतें व घर नहीं उड़ते, उसके नॉर्मज़ देखें जाएं ताकि असली फायदा किसानों/बागवानों को मिल सके न कि उनके खाते से डायरैक्ट पैसे कटें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट में "हिमाचल पुष्प योजना" की बात की गई है। मैं पूछना चाहूंगा कि कितने लोग हैं जिनको इस योजना के तहत पोली हाउसिज़ के पैसे दिए गए? सदन में उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाए। मुख्य मंत्री आवास योजना की बात करुं, अभी पिछली विधान सभा के दौरान अखबार में छपा था कि ढली में आशियाना बना था। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बनाया था और लोगों ने उसको बेच दिया है।

उसको किराये पर दे दिया है। मैं समझता हूं कि अगर ऐसा हो रहा है तो यह सरकार कहां सो रही है? कोई काम नहीं हो रहा है। अगर वे बेच रहे हैं तो उनको अलॉट कैसे किए गए? इसके बारे में जांच होनी चाहिए और जिम्मेवार अधिकारियों के विरुद्ध ऐक्शन लिया जाना चाहिए। यहां पर डिजास्टर मेनेजमैंट की बात की गई। मगर जब डिजास्टर होता है तो मैं समझता हूं उस समय कोई मेनेजमैंट नहीं होती है। हमने ऐसे कई इंस्टांस देखें हैं जैसे इस साल यहां पर जब बाढ़ आई थी, भारी वर्षा हुई थी और रास्ते बंद हुए थे तो कुछ नहीं किया गया था। आपके घोषणा पत्र में चुनाव के दौरान पी0टी0ए0 अध्यापकों को यह कहा गया था कि उनको नियमित किया जायेगा मगर सत्ता में आने के बाद आप लोग मुकर गये। आप अब यह कह रहे हैं कि इसमें कानूनी अड़चन आ रही है। इस कानूनी अड़चन का क्या आपको पहले पता नहीं था जिस वक्त घोषणा पत्र में लिखा जा रहा था। तब क्या ऐसी समस्या नहीं थी या ऑफिस में बैठ कर ऐसे ही लिख दिया गया? भविष्य में पहले सारे पहलुओं की जांच करने के बाद इस प्रकार के वायदे किया करें क्योंकि जनता सबकुछ देखती है। अभी आने वाले लोक सभा चुनाव की भी बात हो रही थी और उसमें आपको पता चल जायेगा। आप हमें एक स्कूल ऐसा बतायें जो पिछले एक साल के कार्यकाल में आपने अपग्रेड किया हो। यहां पर बात की गई कि सरकार नई माइक्रो, स्मॉल एण्ड मीडियम इंडस्ट्री की पॉलिसी लायेगी। लेकिन यह कब लाई जायेगी इस बारे में कुछ नहीं लिखा है। इस बारे में पॉलिसी या रूल कब फ्रेम होंगे ऐसा कुछ नहीं लिखा है। बैंकों से लोग लोन लेते हैं मगर वर्तमान सरकार बोल रही है कि हमने प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिया है। आपने उनको रोजगार कहां दिया है आपने तो उनको बैंक से लोन दिलवाया है। उसने बैंक से लोन लेने के लिए सारी औपचारिकताएं पूरी की हैं और यह रोजगार देना नहीं होता है। आप इस तरह से लोगों को गुमराह करना छोड़ दीजिए। अगर फोरैस्ट की बात करें तो आपने कहा है कि वन कर्मियों के मनोबल को बनाये रखने तथा उनकी सुरक्षा हेतु 200 अति संवेदनशील बीटों में तैनात वन कर्मियों को 15000 रुपये तक अनुदान देकर निजी

हथियार उपलब्ध करवाये जायेंगे। लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप लाईसैंस भी देंगे? प्रदेश में हजारों लोगों ने क्रॉप प्रोटैक्शन और सैल्फ प्रोटैक्शन के लिए लाईसैंस अप्लाई किए हैं लेकिन उनको रिजैक्ट कर दिया जाता है। वहां से पहले फोरैस्ट को भेजेंगे और फोरैस्ट वाले अपना ऑब्जैक्शन लगाते हैं। इस तरह से घूम-फिरकर 30 लाख रुपये की राशि तब जारी होगी जब उनको लाईसैंस मिलेंगे। अगर लाईसैंस ही नहीं मिलेगा तो मैं समझता हूं कि इसमें इसके बारे में लिखना बेकार काम है।

इसके अतिरिक्त बजट में टूरिज्म के अंतर्गत होम स्टे, शिव धाम, वाटर स्पोर्ट्स और मंडी में हरिद्वार की तरह आरती की बात की गई। ये सब तो सारे सपने दिखाने वाली बात है। आप यह बतायें कि पिछले एक साल के दौरान टूरिज्म में इतना फॉल क्यों आया, उसके क्या कारण थे? उसका कारण हमारी टूटी हुई सड़कें थीं जो आप लोग ढंग से पक्की नहीं कर पायें। उन सड़कों में गड्ढे पड़े हुए हैं। अगर आप शिमला से कालका वाला रोड देखेंगे तो पायेंगे कि उसमें कितने ज्यादा गड्ढे हैं और चण्डीगढ़ पहुंचने को साढ़े चार घंटे का समय लगता है। हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर भी बहुत पूअर है। पिछले साल सबसे बुरी बात यह रही कि सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाल दी और जिसके बारे में इस सदन में मुकर गये। मेरे पास उस नोटिफिकेशन की एक कॉपी भी है। ये लोग बाद में मुकर गये कि हमने तो ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं की है। उसमें यह बताया गया था कि अभी शिमला में पानी की कमी है। यहां पर प्रत्येक होटल वाले को पानी का हर महीने के हिसाब से बिल आता है मगर वह होटल वाला अपने पैसों से पानी का टैंकर मंगवाता है। सरकार उसके लिए पानी प्रोवाइड नहीं करवा रही है। फिर आप ऐसी नोटिफिकेशन क्यों निकालते हैं कि पानी की कमी है इसलिए यहां पर टूरिस्ट न आएं। यहां पर भारी वर्षा हो रही है तो आप परवाणू ही रुक जाइए, यहां आने की जरुरत नहीं है। मैं समझता हूं कि ऐसी नोटिफिकेशन्ज से सरकार का घाटा है, हमारे टूरिज्म का घाटा है। पर्यटक हिमाचल प्रदेश को छोड़कर उत्तराखंड और श्रीनगर जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह की नोटिफिकेशन्ज न निकाली जाएं।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से हैल्थ के बारे में पूछना चाहूंगा। आप सुन्नी गये और वहां पर नये बी0एम0ओ0 ऑफिस की घोषणा कर दी। मगर आपने मशोबरा का बी0एम0ओ0 ऑफिस वहां के लिए शिफ्ट किया है। आप इस तरह से शिफ्टिंग की घोषणा न करें। अगर आप नया ऑफिस खोलने की घोषणा करते हैं तो आपको वहां नया बी0एम0ओ0 ऑफिस खोलना चाहिए। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, शायद यह बात आपके ध्यान में नहीं है। आप इस बारे में सम्बंधित ऑफिसर से संज्ञान लीजिए कि बी0एम0ओ0 ऑफिस मशोबरा से शिफ्ट क्यों किया गया? अगर आपने नये ऑफिस की घोषणा की है तो आपको इसके लिए अपनी जुबान भी रखनी चाहिए थी। माननीय मुख्य मंत्री जी, मशोबरा भी आपका ही इलाका है क्योंकि आप पूरे प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं। मैं समझता हूं कि शिफ्टिंग एक बेड आइडिया है और नया खोलना एक अच्छा आइडिया है। आप नया खोलिए और जो शिफ्ट किया गया है वह वापिस मशोबरा आना चाहिए।

11/02/2019/1755 /टी0सी0वी0/डी0सी0/1

क्योंकि गुम्मा की पी0एच0सी0 सुन्नी शिफ्ट की गई है और अब लोगों को सुन्नी जाना पड़ता है। चमयाना, आई0जी0एम0सी0 फेस-॥ का 52 बीघा का एफ0आर0ए0 का केस बना हुआ है। टी0सी0सी0 कैंसर हॉस्पिटल का 45 करोड़ रुपया लैप्स हो रहा है क्योंकि 15 दिनों के अंदर आचार संहिता लगने वाली है। ये हमारे प्रदेश के लिए शर्मनाक बात होगी। इसमें जो बजट है वह 30 प्रतिशत सिविल कंस्ट्रक्शन के लिए और 70 प्रतिशत मशीनरी के लिए है। माननीय मुख्य मंत्री जी इसमें शीघ्र कोई एक्शन लें वरना इससे राज्य के लिए हानि होगी।

सभापतिः माननीय सदस्य, प्लीज वाइंडअप करें।

श्री अनिरूद्ध सिंहः सभापति महोदय, सिर्फ 3 मिनट और लूंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट में कहा कि वॉटर सप्लाई के लिए हम बहुत गंभीर हैं। अभी चाबा से 10 एम0एल0डी0 पानी शिमला के लिए आ रहा है लेकिन बजट में कोल डैम की कोई बात नहीं की गई है कि

उसके टैंडर कब लगेंगे, उसका काम कब शुरू होगा। जबकि सरकार ने शहरवासियों से 24 घंटे पानी उपलब्ध करवाने का वायदा किया है। पानी के बिल 4-5 महीने के बाद दिए जा रहे हैं। जिसके कारण स्लैब बढ़ जाने से लोगों को ज्यादा बिल देना पड़ रहा है। ये पानी के बिल हर महीने दिए जाने चाहिए ताकि जनता पर बोझ न पड़ें। बजट में 50 मीटर पाइप देने की बात की गई है, ये तो लोगों के साथ मज़ाक है क्योंकि 1200 रुपये तो इस पाइप को खरीदने के लिए उसका आने-जाने का खर्चा लग जाएगा। इसलिए इसकी सीमा बढ़ाई जाए और यह 200 मीटर की जाए। किसी भी घर में 9 पाइपों से पानी का कनेक्शन नहीं लग सकता है। इस पर विचार किया जाना चाहिए। 'गौ सेवा सेवा आयोग' की बात की गई है, लेकिन कितने गऊ सदनों के लिए फण्ड का प्रावधान किया गया है। जो रजिस्टर्ड गऊ सदन है, उनके लिए सरकार की क्या पॉलिसी है? अर्बन वेस्ट की बात भी बजट में कि गई, इसमें लिखा है ' they will be assisted in construction and management of the Solid Waste', लेकिन इसके लिए न तो कोई पॉलिसी है और न ही ग्रांट का प्रावधान है। सरकार बनने से पहले कर्ज़ मुक्त हिमाचल का नारा लगाया गया था। मैं कुछ आंकड़े देना चाहूंगा, सरकार वर्ष 2019-20 के लिए 44,388 करोड़ रुपये का कर्ज़ लेगी। जोकि बहुत होता है। वर्ष 2017-18 में कर्ज़ 5600 करोड़ रुपये था जोकि वर्ष 2018-19 में बढ़कर 7944 करोड़ रुपये हो गई है और वर्ष 2019-20 में 7081 करोड़ रुपये दिया गया है। लेकिन मैं समझता हूं कि 8500 करोड़ रुपये तक यह जाने वाला है। वर्ष 2017-18 एक्सपेंडीचर 2753 करोड़ रुपये था, वर्ष 2018-19 में 33400 करोड़ रुपये होगा और आने वाले वित्तीय वर्ष 2019-20 में 36000 करोड़ रुपये से ऊपर चला जाएगा। वर्ष 2019-20 4550 करोड़ रुपये तो ब्याज पर ही खर्च होने वाले हैं। वर्ष 2019 में मात्र 3261 करोड़ रुपये लोन के वापिस होंगे और 4550 करोड़ रुपये ब्याज के देने पड़ेंगे। इससे 4352 करोड़ रुपये का लॉस प्रदेश को होगा। माननीय सभापति महोदय, यदि हम हिसाब लगाएं तो हिमाचल प्रदेश का हर एक व्यक्ति 1.26 लाख रुपये के कर्ज़ में डूबा हुआ है। इस तरह से वायदे करना आसान है लेकिन निभाने मुश्किल हैं। इसलिए आप उतना ही लिखें, जितना निभा सकते हैं, वरना

जनता घर पर बैठा देती है। पिछले साल जब बजट पेश किया गया था तो कहा गया कि अभी तो सरकार को बने हुए 9 महीने ही हुए हैं। इसलिए आप उतना ही लिखें जितना आप 9 महीने में कर सकें। लोगों को यह बात पसंद आएगी। सभापति महोदय, आपने बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

11-02-2019/1800/NS/HK /1

सभापतिः अब माननीय सदस्य, परमजीत सिंह चर्चा में भाग लेंगे।

श्री परमजीत सिंह (दून)ः माननीय सभापति महोदय, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर जी द्वारा 09 फरवरी, 2019 को जो बज़ट इस माननीय सदन में पेश किया गया है, इस चर्चा में भाग लेने के लिए मुझे आपने बोलने का समय दिया इसके लिए मैं, आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बज़ट पेश किया है, यह हिमाचल प्रदेश के नौज़वानों के लिए, गरीबों, किसानों और हिमाचल प्रदेश के हर वर्ग को लाभान्वित करने वाला बज़ट है। इससे हर वर्ग लाभान्वित हुआ है। इस बज़ट का पता ज़नता के बीच जा करके लगता है और हमारे विपक्ष के मित्र कहते हैं कि इस बज़ट में कुछ नहीं है। ज़नता कहती है कि इस बज़ट में सब कुछ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर वर्ग को कुछ-न-कुछ देने की कोशिश की है, चाहे किसान वर्ग हो या नौज़वान वर्ग हो या फिर कोई भी वर्ग हो। हिमाचल प्रदेश में मैक्सिमम आबादी गांव में रहती है और गांव में जब बुजुर्गों को पैंशन मिलती है तो पता चलता है कि अब यह सामाजिक सुरक्षा पैंशन 1300 रुपये से बढ़ा करके 1500 रुपये की गई है। तब बुजुर्गों ने कहा कि हमारे प्रदेश को ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो हर गरीब को पूछता है, मिलता है और जानता है। इसलिए मैं, माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने सामाजिक सुरक्षा पैंशन 1300 रुपये से बढ़ा करके 1500 रुपये की है।

इसी तरह "मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना" में आयु सीमा बढ़ा करके 45 वर्ष कर दी गई है और निवेश की सीमा को बढ़ा करके लगभग 60 लाख रुपये किया गया है। मैं इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, माननीय जय राम जी की सरकार ने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए जमींदार, कृषक को सिंचाई के लिए टयूबवैल का बिजली बिल, पहले कांग्रेस की सरकार में यह बिल एक

रुपये प्रति यूनिट था, लेकिन हमारी सरकार ने पिछले साल इसको कम करके 75 पैसे किया था और इस साल कम करके 50 पैसे प्रति यूनिट किया गया है। मैं मानता हूं कि माननीय जय राम ठाकुर की सरकार ने यह एक सराहनीय कदम उठाया है। इस देश के माननीय प्रधानमंत्री, नरेन्द्र मोदी जी ने किसानों के बारे में सोचा है। कांग्रेस के लोगों ने देश में 55 सालों तक राज किया। लेकिन किसानों के बारे में किसी ने नहीं सोचा। मैं, माननीय नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने यह सोचा कि जिस किसान के पास 2 हैक्टेयर से कम भूमि है, उसके खाते में 6000 रुपये प्रति हैक्टेयर डाले जाएंगे। इसके लिए आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी का बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री ने विद्युत मोड द्वारा नये कनैक्शन प्रदान करने हेतु लो वोल्टेज़ में सुधार करने के लिए और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति उद्देश्य के लिए 850 नये वितरण उपकेंद्र स्थापित किए जाएंगे, इसके लिए भी बजट प्रावधान किया गया है। विद्युत आपूर्ति को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए इस बजट में 26,000 पुराने गले सड़े खंबों को लगाने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए मैं, माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं। इसके अतिरिक्त पुराने मीटरों को बदल कर 4 लाख इलैक्ट्रॉनिक मीटर लगाए जाएंगे। इससे भी हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण जनता का बहुत भला होने वाला है। मैं, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बज़ट में "मुख्यमंत्री रोशनी योजना" शुरू की है। इससे गरीब परिवारों को दिए जाने वाले विद्युत कनैक्शन पर कोई भी सर्विस कनैक्शन चार्जिज़ नहीं लिए जाएंगे। इस बजट में इसके लिए लगभग 475 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं।

(माननीय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने "होम स्टे" को प्रोत्साहित करने के लिए वर्तमान में 3 कमरों की सीमा को बढ़ा करके चार कमरे कर दिया है और इसके लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है।

इसके लिए भी मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय मुख्य मंत्री ने प्लानिंग की मींटिग्स में सभी विधायकों की मांगों को चाहे उसमें कांग्रेस के विधायक हों, भाजपा के विधायक हों या कोई भी विधायक हों सभी की मांगों को पूरा किया है। सभी विधायकों ने मांग की थी कि विधायक निधि को डेढ़ करोड़ रुपये किया जाए, उस निधि को भी माननीय मुख्य मंत्री ने डेढ़ करोड़ रुपये किया है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने नाबार्ड की राशि को 90 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 105 करोड़ रुपये किया है और इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में 'मुख्य मंत्री स्वजल योजना' की शुरूआत की है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 50 मीटर तक की पाइप लाइन को 200 मीटर बढ़ाया गया है। पिछली सरकार ने इसे 50 मीटर भी नहीं बढ़ाया था। मैं इसके लिए भी आदरणीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इसे और भी बढ़ा देंगे। एक हमारे विपक्ष के साथी कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में नशे का प्रचलन बहुत बढ़ चुका है। मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने नशे के ऊपर एक अभियान छेड़ा है जोकि बहतु ही सराहनीय कदम है। कोई भी सरकार यह नहीं चाहती कि हिमाचल प्रदेश के अंदर नशा आए लेकिन इसको रोकने के लिए जो पग माननीय जय राम ठाकुर जी ने उठाए हैं वे बहुत ही सराहनीय हैं। इस बजट के अंदर नशा मुक्त प्रदेश बनाने का प्रावधान भी किया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निर्वाचन क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र है। BBNDA प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में गिना जाता है। इस क्षेत्र की मुख्य सड़कों के सुधार के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्तीय पोषित परियोजना के अंतर्गत आवश्यक संसाधन जुटाने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है। मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। यह बजट गरीबों, किसानों, मजदूरों और नौजवानों के हक का बजट

है। मैं ज्यादा न बोलते हुए इस बजट का जोरदार समर्थन करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल।

उपाध्यक्षः अब माननीय सदस्य, श्री प्रकाश राणा चर्चा में भाग लेंगे।

श्री प्रकाश राणा (जोगिन्द्रनगर)ः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो वर्ष 2019-20 का बजट प्रस्तुत किया है, इस पर चर्चा करने के लिए आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। वर्ष 2019-20 का बजट बहुत ही सराहनीय बजट है। पूरे हिमाचल की जनता इस बजट की तारीफ कर रही है। मीडिया के लोगों ने भी इस बजट की काफी सराहना की है। इस बजट में हर चीज उल्लेखित है और मैं नहीं चाहता कि हर चीज को पढ़कर अपना समय बर्बाद करूं। इसमें गरीब, किसान और सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। कोई भी वर्ग इससे अछूता नहीं है। यहां तक कि विधायक निधि को भी 1.50 करोड़ रुपये किया गया है। हमारे निर्वाचन क्षेत्र के लिए जो नाबार्ड का पैकेज मिलता है उस पैकेज को भी 90 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 105 करोड़ रुपये किया गया है।

11.02.2019/1810/बी0एस0/वाई0के0-1

तो स्वाभाविक है कि क्षेत्र का विकास होगा। हम सब को एक गर्व होना चाहिए कि इस वक्त हमारे देश का नेतृत्व करने वाले हमारे माननीय प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी एक चाय बेचने वाले है और प्रदेश का नेतृत्व करने वाले आदरणीय जय राम ठाकुर जी एक कारीगर के बेटे हैं। इससे पता चलता है कि हमारा लोकतंत्र कितना मजबूत है। मैं कहना चाहता हूं कि इस वक्त जिस तरह से हमारा केन्द्र का बजट आया है उसी के साथ हमारा प्रदेश का बजट पस्तुत हुआ है इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मैं अपने प्रधान मंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज केन्द्र में भी सरकार को 5 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं परंतु कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप उनके ऊपर नहीं लगा है। हमारे राज्य के लिए केन्द्र जो 10.300 करोड़ रुपये की नई-नई स्कीमों के लिए एवं परियोजनाओं के लिए

दिया है इसके लिए मैं माननीय मोदी जी का बहुत- बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझे नहीं लगता कि पहले इस तरह का कार्य हुआ होगा, अगर हुआ भी होगा तो हमें इसकी जानकारी नहीं है। हमारे छोटे से राज्य के लिए इतनी बड़ी धनराशि का मिलना बहुत खुशी की बात है। मैं अपने माननीय सदस्यों से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जब से चर्चा आरंभ हुई है मैं सुन रहा हूं, विपक्ष के माननीय सदस्यों का कहना है कि इस बजट में कुछ नहीं है । मैं इतना कहना चाहता हूं कि कम से कम जो बजट में विधायक निधि को बढ़ाया गया है और जो नाबार्ड का पैकेज बढ़ाया गया है, कम से कम उसकी तारीफ ही कर देते। यह तो दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों के लिए बढ़ाया गया है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के लिए यह बहुत अच्छा समय है, इस वक्त चहुंमुखी विकास हमारे प्रदेश का हो रहा है। आज हमारे प्रदेश को ऐसे मुख्य मंत्री मिले हैं जो जमीन से जुड़े हैं। अपने कार्य को करवाने के लिए कोई भी माननीय सदस्य इनके पास गया आज तक इन्होंने किसी के कार्य को मना नहीं किया। बड़ी खुशी की बात है कि इन्होंने बदले की भावना से कार्य नहीं किया और न ये करना चाहते हैं। हमें यहां आए हुए अभी एक वर्ष का समय हुआ है। परंतु जो मैंने नोट किया है वह मैं बता रहा हूं। पहले का मुझे इतना पता नहीं है । आप लोग भी समझ रहे हैं कि आज हमारा प्रदेश उन्नति के पथ पर अग्रसर है।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि कृपया बीच में न बोलें।

Shri Prakash Rana : Please, let me complete first. Don't speak in between. मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, इस वक्त हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। मैं पहले भी देख रहा था और अब भी देख रहा हूं । परंतु हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो 65 विधान सभा क्षेत्रों का दौरा किया है वह सराहनीय है। मैं अपने चुनाव क्षेत्र का उदाहरण देना चाहूंगा । मेरे विधान सभा चुनाव को चाहे जनसंख्या के आधार पर देखा जाए या एरिया के हिसाब से देखा जाए। वहां पर एक लाख के करीब वोटर हैं।

11.02.2019/1815/DT/YK-1

लेकिन आज तक वहां पर कोई विकास पर बात नहीं हुई, न तो कोई आई0पी0एच0 डिविजन था, न तो कोई बस डिप्पो था और ऐसा पिछड़ा इलाका था लोग पानी के लिए भी तरस रहे थे। मुझे लगता है कि अगर चुनाव मुझे लड़ना पड़ा है तो ये भी वजह रही है कि हमारे क्षेत्र का विकास कुछ भी नहीं हुआ है। मुझे यह भी समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। उस क्षेत्र से मंत्री भी रहे हैं तो उस क्षेत्र को क्यों नहीं देखा गया। ये तो में इस बात को नहीं कहना चाहता हूं कि क्या हुआ है लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब हमारे क्षेत्र का दौरा किया तो मैं बता देना चाहता हूं कि बस डिपो, आई.पी.एच डिवीजन, आई.टी.आई, और सब तहसील लडभड़ोल की घोषणा हुई। हम कहें कि विकास नहीं हो रहा है यह गलत है। मैं यह विकास हर क्षेत्र में देख रहा हूं। सभी क्षेत्रों को कुछ न कुछ मिला है। अगर हम पिछली बातों को दोहराते रहे तो मुझे लगता है कि विकास होना मुश्किल है। हम चाहते हैं कि जहां अच्छाई हो रही है उसकी हम लोग तारीफ करें । जहां कमी है उसके लिए हम अपने विचार दें। आज बड़ी खुशी की बात है कि केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है और इससे अच्छा विकास हो रहा है। हमें पूरी उम्मीद है कि केंद्र में दोबारा भाजपा सरकार आए और हमारे प्रदेश का विकास हो। क्योंकि जब ऑपोजिट सरकार आती है तो विकास में कमी आती है यह सबको पता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो विधान सभा का सिस्टम है वह जो 40-50 वर्ष से चलता आया उसे हम फॉलो कर रहे हैं। जो रूलिंग और ऑपोजिशन की आपस में डिबेट है उसमें टाइम बेस्ट हो रहा है और जो कार्य हमें करना चाहिए वे कार्य भी नहीं हो रहे हैं। 40-50 वर्षों में बहुत कुछ बदला है। बड़ी तरक्की हुई है लेकिन हम पुराने सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं और क्षेत्र का पिछड़ना यह भी एक कारण है। यह सदन हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर है। सभी हिमाचलियों की आस्था इस सदन से जुड़ी हुई है। सब लोग यहां मेहनत करके आए हैं लेकिन यहां आकर पता चलता है कि यहां पर हमारी आपस की लड़ाई समाप्त नहीं होती है तो विकास कहां

से होगा। मैं चाहता हूं हमें अपनी सोच को बदलना होगा।मेरा मानना है कि हमारे जीवन का जो सबसे बड़ा शत्रु है वह हमारी अपनी सोच है। जो हमें अच्छा जीवन नहीं जीने देती।

11-02-2019/1820/ए.जी./एन.जी./1

नैगेटिव विचार आदमी के सम्पूर्ण जीवन को नैगेटिव बना देता है । मेरा यह मानना है कि जो अच्छा काम है हम सब को उसकी सराहना जरूर करनी चाहिए । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज मैं देख रहा हूं कि जो ये नैगेटिव विचार है यह हमारे कलचर में आ चुका है । हम अपने दुःख से ज्यादा दुःखी दुसरों के सुःखों से हैं । इस वजह से हमारी सुःख-शान्ति भंग है । अभी सोचने का विषय तो यह है कि इस वक्त हमारे हिमाचल पर जो लोन/कर्जा है जोकि 50 हजार करोड रूपये पर कर चुका है । इसकी हमें चिन्ता नहीं है और हम सब सारा मुख्यमन्त्री जी पर छोड देते हैं और यह नहीं सोचते की यह हम सब का फर्ज है । हम सब अपने-अपने क्षेत्र से आए हैं और हम सब मिलजुल कर इसके बारे में सोचे । आज हमारे घर का अगर एक रूपये खर्चा है और इनकम 50 पैसे हो तो घर कब तक चलेगा, यह सोचने का विषय है । क्या हमने कभी इस बारे में सोचा है कि हम सभी अपने क्षेत्रों से आए है कम से कम हम अपने क्षेत्र के 50 लोगों को रोजगार का तो कोई बन्दोबस्त करें । कोई छोटा-मोटा फैक्टरी में, इन्डस्ट्री में, खेती बाडी में रोजगार का अवसर प्रदान करवाए लेकिन हम सोचतें हैं कि सारा काम मुख्यमन्त्री करें और फिर उल्टा उनको टारगेट करने लगेंगे । कोई भी मुख्यमन्त्री हो, चाहे पहले के मुख्यमन्त्री हैं, या अभी के, मुख्यमन्त्री की कुर्सी ऐसी कुर्सी होती है अगर कोई आदमी इस मुख्यमन्त्री की सीट पर बैठता है, तो वह कभी नहीं चाहेगा की मैं गलत करूं, वह हमेशा अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करता है । लेकिन हमारी सोच थोडा अलग है । मैं यह कहना चाहता हूं की अभी भी मौका है, अभी भी समय है, की कुछ बदलाव हम लोग करें, मिलजुल कर चले, ताकि हमारे इस हिमाचल प्रदेश का विकास हो, नहीं तो यदि ऐसा ही आता गया, आता गया, तो विकास होना मुश्किल होगा । आज हम लोग कहते हैं कि नौकरियां नहीं है, युवा बेरोजगार है । बेरोजगारी क्यों नहीं होगी, क्या आपने कभी सोचा इसके लिए कि जो ये ऋण है हम

इसका 3600-3700 करोड केवल ब्याज अदायगी में ही दे रहे हैं । यदि यह 3600-3700 करोड लोन नहीं होता तो हम इससे तकरीबन 10 हजार के रेशो से 3 लाख लोगों को रोजगार दे सकते थे, हमने इस बारे में सेचा ही नहीं है कभी भी क्योंकि हम आपस की लडाई में ही उलझे हुए हैं । 3 लाख लोगों को हम केवल ब्याज में जा रही धनराशि से रोजगार दे सकते थे । मेरा यह कहना है कि हमारे घर में जो हमारा लाईफ पार्टनर जो होता है हम उसे रोज जाकर बोलेंगे कि आपने कुछ नहीं किया, या वो मुझे बोले की आपने कुछ नहीं किया, तो क्या वो घर चलेगा, नहीं चलेगा और कब तक चलेगा । लडाई-झगडा चाहे घर का हो, चाहे बाहर का हो या चाहे प्रदेश का हो, लडाई झगडे से कोई आगे नहीं बढा है । अगर कुछ करना चाहते हो तो अभी भी सोचने की आवश्यक्ता है । इस वक्त जरूरत है मिलजुल कर काम करने की और हिमाचल प्रदेश को कैसे हम इम्प्रूव करें, कैसे इसे आगे बढाऐं । मैं अपने बारे में भी थोडा सा बता देना चाहता हूं कि मैने भी बहुत धक्के खाऐं है । मैने अपना जीवन जीरो से शुरू किया था । काफी कुछ देखा, दुनिया के लगभग सभी देश मैने देखे हैं, और एक अच्छा अनुभव मिला है, अच्छा देखने को मिला है । ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं जानते हैं ।

उपाध्यक्ष : अगली बार आप बुर्ज खलिफा जाएं तो ध्वाला जी को साथ लेकर जाएं ।

श्री प्रकाश राणा : ध्वाला जी को जरूर ले जाउंगा लेकिन पहले हम सब प्रदेश का कुछ भला तो करें । पहले प्रदेश को उठाओ और मिलजुल कर कुछ करो । उपाध्यक्ष महोदय मैं ज्यादा ना बात करता हुआ इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरा यह मानना है कि आज एक अच्छा समय आया है और इस वक्त हमें जो मुख्यमन्त्री मिलें है वह एक दम जमीन से जुडे मुख्यमन्त्री हैं ।

11/02/2019/1825/RG/AG/1

माननीय मुख्य मंत्री जी की एक बहुत अच्छी सोच है, वे बदले की भावना से काम नहीं करना चाहते हैं। मैंने देखा है कि जो दूसरे मुख्य मंत्री पहले आते थे कि पुरानी सरकार ने

क्या किया, उस मामले को खोलो कि उसमें क्या हुआ, यह सब होता था। लेकिन जो ये मुख्य मंत्री हमें मिले हैं, इन्होंने इस चीज को तो भुला ही दिया कि हमने बदले की भावना से काम करना है। इसलिए यह सोचने का विषय है। अगर कहीं ऐसा काम किया हो, तो बताएं। इस बात को विपक्ष वाले बता सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जब एक अच्छा मौका हमारे प्रदेश को मिला है तो हम सब क्यों न मिलजुल कर अपने प्रदेश के लिए इकट्ठे काम करें। जो हमारा ऋण बढ़ रहा है, कम-से-कम इस कर्जे को रोक दें। यह ऋण कोई मुख्य मंत्री का नहीं है, यह कोई मेरा नहीं है। हम लोग पूरा दोष मुख्य मंत्री के ऊपर डाल देते हैं। मुख्य मंत्री क्या करेंगे? जब आप कहेंगे कि हमें यह भी दो, यह भी लाकर दो, वह भी दो, यह भी होना चाहिए तो फिर वे कर्जा लेने के सिवाय क्या करेंगे? इसलिए हमें अपने खर्चों को कंट्रोल करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। हम सबको करना पड़ेगा, यह ऋण कोई मुख्य मंत्री का नहीं है। यह हमको है, मेरे परिवार को है, मेरे बच्चों पर है और हम सबको है। इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। क्या हम अपने घर को कभी ऐसा करते हैं कि भई ऋण लेकर घर का खर्चा चलाते रहो? क्या आपने कभी सोचा कि इससे कितना दुःख और तकलीफ होती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस ओर हम ध्यान दें और जो अच्छा समय आया है, हम मिलजुल कर काम करें। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं। यह सोचने का विषय है। मेरा विपक्ष वालों से भी आग्रह है कि इसके बारे में सोचें। जो ऋण हमारे प्रदेश के ऊपर बढ़ रहा है, इसको हम उतारें और बेरोजगारों के लिए हम रोजगार के साधन ढूंढे। कुछ-न-कुछ करें, यह न मेरे अकेले से होगा, न मुख्य मंत्री जी के अकेले के करने से कुछ होगा, न आपके अकेले से होगा। इसको यदि हम मिलजुल कर करेंगे तो हम अपने इस प्रदेश को आगे ले जा सकते हैं। मैं एक बार फिर माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। ज्यादा न कहते हुए मुझे इसको पढ़कर नहीं सुनाना है, इसमें सब कुछ लिखा है कि क्या अच्छा है, क्या नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मैं एक-एक चीज कहूं कि ऐसा किया, वैसा किया। लेकिन जिस तरह से हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी काम कर रहे हैं, वाकयी यह सराहनीय है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने वर्ष 2019-20 का जो बजट यहां प्रस्तुत किया है, मैं इसका समर्थन करता हू। बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। वैसे मैं तो आज बोलने के लिए तैयार नहीं था लेकिन आपने मौका दिया, आपका धन्यवाद।

उपाध्यक्ष : दूसरों के सुखों से दुःखी न हों। धन्यवाद।

अब इस माननीय सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 12 फरवरी, 2019 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **यशपाल शर्मा,**
दिनांक : 11 फरवरी, 2019 **सचिव।**